राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 99

मूल्य ₹8 .00 नई दिल्ली, सोमवार, 16 सितंबर, 2024

www.jagran.com

पृष्ठ 14

कोटे पर राहुल की टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता

>> 5

जागरण विशेष

जल वितरण व भूजल की बर्बादी रोकेगी तकनीक

नई दिल्ली: जल की बर्बादी रोकने के साथ, जहां जरूरत है वहां आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तकनीक मददगार बन रही है। प्रगति मैदान में हाल ही में संपन्न हुए वाटर एक्सपो में ऐसी ही कुछ तकनीक को प्रदर्शित किया गया। ● पेज-6

संपादकीय

सहमति की राह पर सरकार: मोदी सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगा

रहे लोग भूल जाते हैं कि पूर्व में पूर्ण बहुमत के बावजूद पीएम मोदी ने कई नीतिगत मुद्दों पर अपने कदम पीछे खींचे। **ए. सूर्यप्रकाश** का विश्लेषण।

मत प्रचार की स्वतंत्रता पर हो पुनर्विचार: लोगों को मत प्रचार-प्रसार से जुड़ी छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यह कोई दुकान या व्यापार नहीं है। **आरके सिन्हा** का दृष्टिकोण। ● पेज-8

विमर्श

यूपीआइ की बढ़ती वैश्विक मान्यता: भारत में यूपीआइ यानी 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' आधारित भुगतान प्रक्रिया अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। सात देशों में इसका प्रयोग हो रहा है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक मान्यता को ही दर्शाता है। **ऋषभ मिश्रा** का आलेख।

अपराधियों के एनकाउंटर में जातियों की सियासत: कहा तो यही जाता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी केवल अपराधी होता है, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों के जाति-धर्म की सियासत कुछ ज्यादा ही गर्माई हुई है। **अजय जायसवाल** की डायरी। ● पेज-9

सप्तरंग

साहित्य और संगीत का

हिंदी साहित्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता!

कर्नाटक संगीत की "देवी" एमएस सुब्बुलक्ष्मी

● पेज-13

केजरीवाल का बड़ा दांव, छोड़ेंगे मुख्यमंत्री का पद

आप के संयोजक ने कहा, कल देंगे त्यागपत्र, मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- कहा, फरवरी के बजाय नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में भी कराएं जाएं विस चुनाव
- भाजपा ने बताया नया नाटक, कहा-इस्तीफा देना घोटाले के आरोपों को स्वीकार करना है

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के दो दिन बाद चौंकाने वाले घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। कहा कि वह 17 सितंबर (मंगलवार) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। पांच माह तक जेल में रहने के बाद रविवार को पहली बार पार्टी मुख्यालय पहुंचे केजरीवाल ने आयोजित कार्यक्रम में कहा, मनीष सिसोदिया भी सरकार में शामिल नहीं होंगे। कहा, दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं, मगर नवंबर में महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली के भी चुनाव कराए जाएं। भाजपा ने इसे नया नाटक बताते हुए कहा, शराब घोटाले में जेल में रहकर इस्तीफा न देकर बाहर आने के बाद त्यागपत्र देना बताता है कि उन्होंने आरोपों को स्वीकार लिया है। जब भी चुनाव होंगे, तब केजरीवाल सरकार की विदाई तय है।

राजनीति के जानकार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के इस फैसले को हरियाणा चुनाव व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी को हुए नुकसान को रोकने की कोशिश से जोड़ कर देख रहे हैं। केजरीवाल ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि उन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं है और वे शीर्ष पद पर लौटने से पहले जनता का फैसला चाहते हैं। पार्टी मुख्यालय पर केजरीवाल ने कहा, अगले दो-तीन दिनों में विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नए सीएम पर फैसला होगा। वह स्वयं लोगों के बीच जाएंगे और समर्थन मांगेंगे। अगर दिल्लीवालों को लगता है कि मैं ईमानदार हूं, तो मेरे पक्ष में वोट दें और लगता है कि गुनाहगार हूं, तो मुझे होने वाले चुनाव में वोट ना दें। अगर जनता को लगता है कि केजरीवाल बेईमान है, तो मैं एक मिनट के लिए भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मैंने अपने जीवन में इज्जत ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं कमाया है, मेरा और मेरी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है।

तिहाड़ जेल से छुटने के बाद रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चंद्र प्रकाश मिश्र

कानून की अदालत में न्याय मिला, लेकिन अब जनता की अदालत में न्याय चाहता हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा।

-अरविंद केजरीवाल

'गैर-भाजपाई मुख्यमंत्री इस्तीफा न दें, जेल से चलाएं सरकार'

केजरीवाल ने कहा कि अगर गैर-भाजपा मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो मैं आग्रह करता हूं कि वे इस्तीफा न दें, बल्कि जेल से सरकार चलाएं। मार्च में जेल जाने से पहले केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने की घोषणा की थी। उनका कहना है कि उन्होंने इसे साबित भी कर दिया है।

'ये शर्तें हमारे लिए कोई अड़चन नहीं हैं'

केजरीवाल बोले, मेरे लिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की कुछ शर्तें लगाई हैं कि काम नहीं कर पाएंगे। पिछले 10 वर्ष में इन लोगों ने शर्तें लगाने में क्या कोई कसर छोड़ी थी? एलजी ने शर्तें लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार ने कानून पर कानून लाकर मेरी पावर छीनी, पर मैंने दिल्ली के काम नहीं बंद होने दिए। ये शर्तें हमारे लिए कोई अड़चन नहीं हैं।

छवि पर पड़े दाग को साफ करने के लिए खेला दांव

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर बड़ा दांव खेला है। उन्होंने विरोधियों को जवाब देने के साथ जनता को अपने साथ और मजबूती से जोड़ने का प्रयास किया है। साथ ही भाजपा के इस आरोप का जवाब भी दिया है कि वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। यह संदेश दिया है कुर्सी से उन्हें बहुत लगाव नहीं है। (पेज-2)

सीएम के लिए आतिशी का नाम सबसे ऊपर

आतिशी

कैलाश गहलोत

केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। जिन नामों पर कयास लग रहे हैं, उनमें शिक्षा मंत्री आतिशी सबसे ऊपर हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि कहा यहां तक जा रहा है कि आप इस पद के लिए कोई चौंकाने वाला नाम भी दे सकती है। (पेज-2)

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिये नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लांच नहीं किया गया है। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है। (पेज-3)

सजा में छूट पाने के लिए गलत बयानी पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित

नई दिल्ली: दोषियों की समयपूर्व रिहाई हासिल करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत व याचिकाओं में बार-बार गलत बयानी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब-जब वह ऐसे मामलों से दो-चार होती है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हालिया एक आदेश में अपनी चिंता दर्ज की है। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत में बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं जिनमें सजा में स्थायी छूट नहीं प्रदान करने के बारे में शिकायत की गई है। (पेज-7)

राजग सरकार के वर्तमान कार्यकाल में ही लागू होगा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव'

- सूत्रों जताया विश्वास, इसे सभी पार्टियों का प्राप्त होगा समर्थन
- लोस चुनाव में भाजपा के घोषणा-पत्र में प्रमुख थी यह घोषणा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार अपने वर्तमान कार्यकाल में ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करेगी। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी देते हुए विश्वास जताया कि इस सुधारवादी कदम को सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त होगा।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के तीसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे हो रहे हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकजुटता शेष कार्यकाल में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' इसी कार्यकाल में हकीकत बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने स्वाधीनता दिवस पर अपने संबोधन में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार पैरवी की थी और कहा था कि बार-बार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। लिहाजा देश को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए आगे आना होगा। प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से देश की प्रगति सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय संसाधनों का इस्तेमाल जनसामान्य के लिए सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लोकसभा चुनावों में भाजपा के घोषणा-पत्र की एक प्रमुख घोषणा थी। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने इस वर्ष मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने और फिर सौ दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुशंसा की थी। विधि आयोग द्वारा भी 2029 से तीनों चुनावों एकसाथ कराने और त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में यूनिटी गवर्नमेंट के प्रविधान की अनुशंसा किए जाने की संभावना है। कोविन्द समिति ने एकसाथ चुनाव कराने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है। समिति ने 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है और अधिकतर में राज्य विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन संसद से कुछ संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की आवश्यकता होगी।

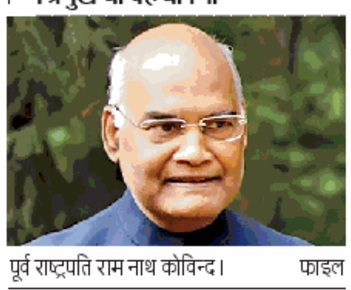

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द। फाइल

वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दे रहे घुसपैठियों को संरक्षण : मोदी

- जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, झामुमो और राजद को निशाने पर लिया
- कांग्रेस को बताया देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, कहा, झामुमो भी उसी से ले रहा प्रशिक्षण
- भारी वर्षा के बीच रांची से सड़क मार्ग से परिवर्तन महारैली में पहुंचे पीएम

राज्य ब्यूरो, जागरण ● जमशेदपुर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस, झामुमो और उसके सहयोगी दल बांग्लादेशी तथा रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। इनकी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण आदिवासियों का अस्तित्व और बहन-बेटियों की अस्मिता खतरे में है। घुसपैठिये जमीन से लेकर पंचायतों तक पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासियों की संख्या तेजी से घटने के कारण क्षेत्र की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। पीएम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राजद झारखंड के तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तीनों भ्रष्टाचार में एक-दूसरे के सहयोगी हैं। राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के तुष्टीकरण के लिए आदिवासी समाज पर अत्याचार होता देख रही है। वह रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में भाजपा की परिवर्तन महारैली को संबोधित कर रहे थे।

झामुमो के भीतर घुस गया है कांग्रेस का भूत: मोदी ने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस है। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो भी इसी भ्रष्टाचार की पाठशाला से प्रशिक्षण ले रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर कांग्रेस का भूत घुस गया है और जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। आरोप लगाया कि खान, खनिज, बालू और सेना की जमीन राज्य सरकार के संरक्षण में लूटी जा रही है।

आदिवासियों का अपमान : जमेशदपुर में महारैली के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि क्या चम्पाई सोरेन आदिवासी नहीं हैं? क्या वो गरीब घर से नहीं आते हैं? ऐसे में जिस तरह से उन्हें अपमानित कर उनसे सीएम की कुर्सी छीनी गई। यह झारखंड के सभी आदिवासियों का अपमान है। इतना ही नहीं जिस तरह से सीता सोरेन को उनके घर से अपमानित कर निकाला गया, वह भी आदिवासियों का अपमान है।

छह वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन, दो करोड़ पीएम आवास में गृह प्रवेश का शुभारंभ: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड से दो करोड़ सुविधा संपन्न घरों में गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके अलावा 650 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी और छह नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त भी भेजी गई। कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़ा, महिलाएं, युवा एवं किसान हैं। सरकार इन सबके विकास के लिए कृतसंकल्प है।

जमशेदपुर में रविवार को आयोजित परिवर्तन महारैली के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रेट्र

नियुक्ति परीक्षा में हुई मौत और लूट की होगी जांच

पीएम ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। सिपाहियों की नियुक्ति परीक्षा में 15 युवाओं की मौत हो गई। पेपर लीक के मामलों में भी झारखंड का नाम आ रहा है। भाजपा की सरकार बनने पर इन सभी मामलों की जांच कराई जाएगी।

लोगों का प्यार और आशीर्वाद बड़ी पूंजी

भारी वर्षा के बीच प्रधानमंत्री निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से रांची से जमशेदपुर पहुंचे। कहा कि मौसम खराब होने के कारण हेलीकाप्टर उड़ नहीं सकता था। इस कारण सड़क मार्ग से पहुंचे। रास्ते में बारिश के रूप में आशीर्वाद मिला। रास्ते भर में लोगों ने भींगकर स्वागत किया, लोगों का प्यार और आशीर्वाद जीवन की बड़ी पूंजी है। कहा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आमने-सामने बैठकर मिलेंगे।

देश के हर डाक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र

- एमएमसी पोर्टल पर एमबीबीएस डाक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू
- देश के 13 लाख से अधिक डाक्टरों के बारे में मिल सकेगी जानकारी

नई दिल्ली,प्रेट्र: अब आप महज एक क्लिक कर देश के किसी भी डाक्टर की योग्यता, अनुभव के बारे में जान सकेंगे और अच्छे से अच्छे डाक्टर से इलाज करा सकेंगे। आसानी से यह भी पता चल सकेगा कि देश में कुल कितने डाक्टर हैं। किसका लाइसेंस रद कर दिया गया है। दरअसल जल्द ही देश के हर डाक्टर का विशिष्ट पहचान पत्र बनेगा। इससे देश का डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। आप अच्छे डाक्टर से आनलाइन परामर्श ले सकेंगे। देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने अपने पोर्टल पर भारत में प्रैक्टिस करने के लिए पात्र सभी एमबीबीएस डाक्टरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत सभी डाक्टरों के पास विशिष्ट आइडी होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर) पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था।

प्रतीकात्मक

एनएमआर पोर्टल पर मिलती हैं कई सुविधाएं

एनएमआर पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इनमें आवेदनों को ट्रैक करने, लाइसेंस निलंबित करने और एनएमआर आइडी कार्ड और डिजिटल डाक्टर प्रमाण पत्र जारी करने की क्षमता शामिल है।

एनएमआर डाटाबेस है। इसमें डाक्टरों का पंजीकरण होगा। उनकी प्रामाणिकता आधार आइडी द्वारा सत्यापित की जाएगी। एनएमआर के लांच होने से 13 लाख से अधिक डाक्टरों का डाटा उपलब्ध होगा।

एनएमसी के सचिव डा. बी. श्रीनिवास ने कहा, एनएमआर तत्काल प्रभाव से डाक्टरों के पंजीकरण के लिए तैयार है। एनएमसी ने हाल ही में नोटिस में कहा कि इंडियन मेडिकल रजिस्टर (आइएमआर) पर पंजीकृत सभी एमबीबीएस डाक्टरों को एनएमआर पर फिर से पंजीकरण कराना होगा। सभी मेडिकल कालेज/संस्थान, राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) पोर्टल पर आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ डाटा आम लोग भी देख सकेंगे, वहीं अन्य डाटा केवल एनएमसी, एसएमसी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई), चिकित्सा संस्थानों और डाक्टरों को ही दिखेंगे।

इस तरह होगा पंजीकरण पेज>>10

मेलबर्न विश्वविद्यालय भी देश में देगा दस्तक, दिल्ली में खोलेगा केंद्र

नई दिल्ली: विदेशी विश्वविद्यालयों का देश में दस्तक देने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के साउथहेम्पटन विश्वविद्यालय के बाद आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भी देश में अपना एक केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जो दिल्ली में स्थापित होगा। इसके जरिये विश्वविद्यालय सभी शैक्षणिक व शोध गतिविधियां संचालित करेगा। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय इसी हफ्ते अधिकारिक घोषणा करेगा। (पेज-3)

हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, सीएम का दावा पेश करूंगा : विज

अंबाला: अंबाला छावनी से छह बार के विधायक,पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा है कि सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, इसलिए वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया गया तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। मेरे पास पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। उनका मत है कि वरिष्ठता के नाते मुझे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। (पेज-4)

बड़ा सोच

पीएम मोदी की जन्मतिथि पर कल पूरे हो रहे नई सरकार के सौ दिन, छह माह पहले शुरू हो गया था तीसरे कार्यकाल के लिए होमवर्क, कई महत्वपूर्ण निर्णयों से मिला संदेश, विकसित भारत के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी, किसान के साथ हर वर्ग को साधने का प्रयास

मोदी 3.0 के लिए तैयार था ट्रैक, 100 दिन में ही पकड़ी सरकार ने रफ्तार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि पर पूरे हो रहे हैं। अभी सरकार जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रही है, उसका दूरगामी लक्ष्य तो 2047 तक विकसित भारत बनाने का बताया जाता है, लेकिन ट्रैक रिकार्ड स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोडमैप बिल्कुल तैयार है। पहले 100 दिनों के लिए तो लोकसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी चल रही थी। किसान और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता पर रखते हुए तो सरकार ने हाल में जो बड़े निर्णय लिए, ये छह महीने पहले से की गई तैयारी का ही नतीजा है। साथ ही सरकार ने महिला, युवा, अनुसूचित जाति-जनजाति से लेकर हर वर्ग को भी साधने का प्रयास किया है।

आम चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के रोडमैप पर काम करने को कह दिया था। यह तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर उनका आत्मविश्वास ही था। इसलिए मोदी ने नौ जून, 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो तमाम मंत्रालयों ने 100 दिन के तैयार एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया। सरकार की प्राथमिकताओं में किसान सबसे ऊपर हैं, इसका संकेत इस बात से मिलता है कि तीसरे कार्यकाल के पहले निर्णय में पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, डिजिटल कृषि मिशन सहित कई निर्णय किए।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसान सम्मान निधि तय करने से पहले एक अध्ययन कराया गया जिसमें पता चला कि लघु व सीमांत किसानों की कृषि लागत लगभग 5,600-5,700 रुपये आती है, जिसके लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था। छह हजार रुपये सम्मान निधि देकर किसानों को इस संकट से उबारा।

नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित किए तीन लाख करोड़ रुपये पेज>>5

प्रतीकात्मक

तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी

सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को वरीयता देते हुए तीन लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से पीएम जनमन योजना चल रही है। कचरा बीनने वालों के सशक्तीकरण के लिए उन्हें नमस्ते योजना में शामिल कराया। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन व संरक्षण को मजबूत करने और विवादों के निपटारे के लिए वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 भी लोकसभा में पेश हो चुका है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत के तहत पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का एलान हो गया है। कौशल विकास मिशन की निरंतरता बनाए रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ का प्रधानमंत्री पैकेज बजट में घोषित किया। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप, 28,600 करोड़ के निवेश संग 12 औद्योगिक नोड्स को मंजूरी व 10,600 करोड़ की विज्ञान धारा योजना जैसे फैसले लिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में जादू-टोने के संदेह में परिवार के पांच लोगों की हत्या

- मृतकों में हेड कांस्टेबल, उसकी पत्नी, माता-पिता और बहन शामिल
- हत्या के बाद आरोपित युवकों ने किया थाने में समर्पण

नईदुनिया न्यूज, कोंटा

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोंटा थानांतर्गत इतकल गांव में ग्रामीणों ने जादू-टोने के संदेह में रविवार को पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल मौसम बुच्चा, उसकी पत्नी, माता-पिता, व बहन की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने बैठक करने के बाद गत एक सप्ताह से परिवार को बहिष्कृत कर रखा था। रविवार को उन्होंने फिर बैठक की और पांच युवकों को परिवार को जान से मारने के लिए भेज दिया। गांव के ही युवक घर में घुसे और लाठी-डंडों से पीटकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक कोंटा थाने पहुंचे और समर्पण भी कर दिया।

परिवार में अब प्रधान आरक्षक की छोटी बहन व दो बच्चे ही बचे हैं। तीनों इसलिए बचे, क्योंकि बहन कोंटा में रहती है व दोनों बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। युवकों ने पुलिस को बताया कि 36 घरों वाले गांव में पिछले दो वर्षों में 30 से अधिक लोगों की बीमारी व अन्य कारणों से मृत्यु हुई है। पिछले तीन दिनों से गांव में किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। उन्हें प्रधान आरक्षक की मां पर जादू-टोना करने का संदेह था। उल्लेखनीय है कि इसके पहले गुरुवार को बलौदाबाजार जिले में 11 माह के बच्चे समेत एक ही परिवार के चार लोगों की जादू-टोने के संदेह में पीटकर निर्ममतापूर्वक हत्या की गई थी। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया था।

4 माह भी नहीं चला लुटियंस दिल्ली में पीएम आवास से चंद कदमों की दूरी पर साढ़े चार करोड़ की लागत से बना साइकिल ट्रैक, कई जगह आ गई हैं दरारें

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर, 2024

आज का मौसम

आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
16 सितंबर	35.0	24.0
17 सितंबर	34.0	23.0
नोएडा		
16 सितंबर	35.0	24.0
17 सितंबर	35.0	25.0
गुरुग्राम		
16 सितंबर	31.0	23.0
17 सितंबर	31.0	23.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

दिल्ली में डेंगू से इस साल की हुई पहली मौत

नई दिल्ली: वेक्टर (परजीवी, वायरस और बैक्टीरिया) जनित बीमारी के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली में इस साल डेंगू से पहली मौत दर्ज हुई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते लोक नायक अस्पताल में 54 वर्षीय एक व्यक्ति की डेंगू से मौत हो गई। पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर के रहने वाले इस व्यक्ति को 27 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आधिकारिक रिकार्ड के अनुसार, उसे आठ सितंबर को मृत घोषित कर दिया गया। (जासं)

हत्या के मामले में 31 साल से फरार आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली: नरेला में युवक की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 31 साल बाद आरोपित दयाराम को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस तीन आरोपितों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। आरोपित दयाराम यूपी के बांदा जिले के गांव भिदौरा का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अमित गोयल के अनुसार बीती 18 सितंबर 1993 को नरेला निवासी बाबू लाल की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। (जासं)

धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली: कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के निर्देश पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व यूपी में प्रापर्टी डीलर, दुकानदार व ज्वेलर्स को धमकी देकर व उनके कार्यालयों पर फायरिंग कर रंगदारी मांगने वाले नंदू गिरोह के दो बदमाश दीपक और शेखर को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से नंदू गिरोह द्वारा रंगदारी वसूलने की योजनाओं को विफल कर दिया। (जासं)

'कट्टर ईमानदार' छवि को बचाने की कोशिश

इस्तीफे का दांव खेल विपक्षियों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया

केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा के साथ ही उठाए जा रहे सवालों का भी जिक्र किया

वी के शुक्ला ● जागरण

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने की घोषणा कर केजरीवाल ने विरोधियों को जवाब देने के साथ जनता को अपने साथ और मजबूती से जोड़ने का प्रयास किया है। भाजपा के इस आरोप का जवाब दिया है कि वह कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं जनता में भी संदेश दे दिया है कुर्सी से उन्हें बहुत लगाव नहीं है। केजरीवाल ने यह दांव खेलकर लगातार हमलावर विपक्षियों का मुंह बंद करने की कोशिश की है।

इस घोषणा के साथ उन्होंने अपनी 'कट्टर ईमानदार' की छवि को मजबूत करने का प्रयास किया है। आप इसका लाभ हरियाणा और आगे चलकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश करेगी। 2013 के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलने पर पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर 49 दिन की सरकार चलाने के बाद केजरीवाल के इस्तीफा देने पर 2015 में हुए चुनाव में आप को विशाल बहुमत के साथ 70 में से 67 सीटें मिली थीं। इससे पहले 2013 के चुनाव में आप को 28 और कांग्रेस को 8 सीट मिली थीं। भाजपा को 32 सीटें मिली थीं।

तिहाड़ जेल से छुटने के बाद रविवार को पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। चंद्र प्रकाश मिश्र

इसे भले ही आम आदमी पार्टी न माने, मगर जेल जाने से केजरीवाल की छवि पर असर पड़ा है। केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल को खुद एक पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो आम आदमी पार्टी की छवि ही केजरीवाल से है। विपक्षी दलों की साजिश बताकर आप के नेता यह बात पिछले एक साल से हर मंच पर कह रहे हैं कि केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।

रविवार को अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित जिस कार्यक्रम में इस्तीफा देने की घोषणा की है, इसमें उन्होंने छवि पर उठाए जा रहे सवालों का भी जिक्र किया। इससे पहले केजरीवाल ने अपने बारे में भी लोगों को बताया कि वह दिल्ली की जनता के लिए काम इसलिए करा सके क्योंकि वह ईमानदार थे। उन्होंने स्कूल अच्छे किए हैं, अस्पताल अच्छे किए हैं, बिजली-पानी फ्री दे रहे है, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा दे रहे हैं। यह सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ईमानदार सरकार है।

केजरीवाल के सामने इसलिए आई इस्तीफा देने की नौबत

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

साढ़े पांच महीने से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने दो दिन बाद ही पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उनके सामने यह नौबत क्यों आई है? इसके पीछे के कारणों में जाएं तो आबकारी घोटाला ऐसा मामला है, जिसने आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल भी इसी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पांच माह से अधिक समय तक जेल में रहे और दोनों को कई नाकाम कोशिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकी है। उस पर भी कोर्ट ने प्रतिबंध लगाए हैं। क्या है आबकारी घोटाला, आइये डालते हैं इस पर एक नजर

बात मार्च 2021 की है, जब दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की। सरकार ने इस नीति से राजस्व बढ़ने का दावा किया था। दिल्ली वालों को सस्ते में शराब मिल रही थी। उस साल मार्च आते-आते आधे दाम पर भी लोगों को शराब मिली थी। इस नीति में एक नया प्रयोग यह किया गया था कि शराब बेचने का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया। यही वह मुद्दा था जो केजरीवाल ही नहीं पूरी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बना। हालांकि आप हमेशा ही इसे फर्जी घोटाला बताती रही। पार्टी का दावा है कि जांच एजेंसियों को आज तक एक भी सुबूत नहीं मिला है।

एलजी वीके सक्सेना को मिली शिकायतों पर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मामले की जांच की। उन्होंने एलजी को सौंपी रिपोर्ट में इसमें बड़े घोटाले की बात कही और यहीं से यह मामला बढ़ता चला गया। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने इस मामले में सीबीआइ जांच की सिफारिश कर दी। केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले मीडिया प्रभारी विजय नायर को 27 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया। यह मामले में पहली गिरफ्तारी थी। 26 फरवरी 2023 को सीबीआइ ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नौ घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद ईडी ने चार अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 21 मार्च को आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया।

अरविंद के साथ मैं भी जनता की अदालत में जाऊंगा : सिसोदिया

राज्यू, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में कोई पद लेने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी मैं उपमुख्यमंत्री-शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। हालांकि अब शीर्ष अदालत तक ने कह दिया है कि जाओ अपना काम करो, लेकिन मैं कुर्सी के लालच में राजनीति में नहीं आया हूं। मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन मुझ पर टुच्ची राजनीति के तहत झूठे आरोप लगाकर मुझे बेईमान सिद्ध करने की कोशिश की गई और 17 महीने झूठे आरोप में जेल में रखा गया। इसलिए मैंने फैसला किया कि केजरीवाल के साथ मैं भी जनता की अदालत में जाऊंगा और पूछूंगा कि वह मुझे ईमानदार मानती है या नहीं।

मनीष सिसोदिया

अगले तीन-चार महीने में दिल्ली में चुनाव होना है। अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी, तभी मैं कुर्सी पर बैठूंगा और शिक्षा के लिए काम करूंगा। सिसोदिया ने कहा कि आबकारी विभाग से दिल्ली सरकार को पहले छह हजार करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन नई नीति के तहत नौ हजार करोड़ मिलने की गारंटी हो गई थी। ये कहते हैं कि अरविंद और मनीष ने भ्रष्टाचार कर दिया।

पार्टी में विरोध के चलते अरविंद दे रहे इस्तीफा : भाजपा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- कहा, बहुमत होने के बाद भी नवंबर में विधानसभा चुनाव की मांग हास्यास्पद
- केजरीवाल ने नैतिकता की निम्नता के लिए बनाया कीर्तिमान : सुधांशु

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और नवंबर में चुनाव कराने की मांग पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी ने कहा कि बहुमत होने के बाद भी सीएम द्वारा नवंबर में चुनाव कराने की मांग हास्यास्पद है। सीएम को कैबिनेट की बैठक बुलाकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी में हो रहे विरोध के चलते वह अपना इस्तीफा दे रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दागदार अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर धुआंधार स्वागत करवा रहे हैं। राजनीति की नई नवेली पार्टी ने उदाहरण पेश किया कि वह सरकार के अधीन आने वाली जेल में रहे हैं और उनके दो मंत्री भी वहां पर रहे हैं। यह नैतिकता की निम्नता है, क्योंकि जेल जाने से पहले कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। 2008 में मधु कोड़ा और उसके बाद शिबू सोरेन झारखंड के सीएम के तौर पर जेल में थे। 1997 में लालू यादव बिहार के सीएम थे और उन्हें जेल हुई थी। 1996 में जयललिता को जेल हुई थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल जल्द इस्तीफा दें और विधानसभा भंग कराकर चुनाव कराएं। दिल्ली की महिलाएं, युवक और बुजुर्ग आबकारी घोटाले से केजरीवाल से बेहद नाराज हैं और जब भी चुनाव होंगे वह केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

सुधांशु त्रिवेदी

वीरेंद्र सचदेवा

सुधांशु त्रिवेदी का सीएम को सजायाफ्ता कहना बेहद गलत : आप

राज्यू, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तीफे की घोषणा पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने यह एलान कर भारतीय राजनीति में नैतिकता की एक बड़ी लकीर खींच दी है।

कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि सबसे बड़ी अदालत ने जमानत देकर केजरीवाल को राहत दी है, लेकिन उनका कहना है कि वो जनता की अदालत में जाकर अपनी अग्नि परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल देश में अकेले मुख्यमंत्री हैं, जो खुद जनता से कह रहे हैं कि अगर वो ईमानदार हैं, तभी उन्हें वोट देना। वहीं, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुधांशु त्रिवेदी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को सजायाफ्ता बताया। उन्होंने कहा कि वह पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ जो 'सजायाफ्ता' शब्द का इस्तेमाल किया है। उस पर मैं घोर ऐतराज करता हूं। वह एक सांसद हैं। सजायाफ्ता का मतलब 'अपराध सिद्ध होना' होता है। जबकि अरविंद केजरीवाल की अभी ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है।

आतिशी पर बड़ा दांव लगा सकती है आप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है सामने
- परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी है चर्चा में

अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने की घोषणा के साथ ही अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आम आदमी पार्टी दो दिन बाद ही स्थिति स्पष्ट करेगी। मगर दिल्ली के अगले सीएम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें इस पद के लिए दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। हालांकि कहा यहां तक जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस पद के लिए किसी चौंकाने वाले नाम को भी सामने ला सकती है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का नाम भी लिया जा रहा है। कुछ लोग इस पद पर दलित चेहरा भी लाए जाने की चर्चा कर रहे हैं।

दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के साथ साथ खाली पड़े एक कैबिनेट मंत्री का पद भी भरा जाना है। यह बात तय है कि मुख्यमंत्री किसे भी बनाया जाए, सत्ता तो केजरीवाल के हाथ में ही रहेगी, क्योंकि वही इस दल के कर्ताधर्ता हैं। पार्टी या सरकार में उनके निर्देश पर ही पत्ता हिलेगा। मगर इस सब के बीच ये प्रक्रियाएं तो पूरी ही की जानी हैं। रेस में आप नेता आतिशी का नाम सबसे आगे इसलिए भी बताया जा रहा है, क्योंकि वह अन्य नेताओं से आप आलाकमान की करीबी मानी जाती हैं। महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। वह केजरीवाल के साथ ही और मनीष सिसोदिया की भी भरोसेमंद सहयोगी हैं। ऐसे में संभावना है कि आतिशी दिल्ली सरकार की कमान संभाल सकती हैं। वह 2013 के विधानसभा चुनावों के लिए आप का घोषणापत्र तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सदस्य थीं। वह आम आदमी पार्टी को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाती रही हैं।

एक कार्यक्रम में संबोधत करतीं शिक्षामंत्री आतिशी। सौ. दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के मुखिया केजरीवाल के बाद आतिशी इस वक्त सरकार में दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री है। वर्तमान में दिल्ली कैबिनेट में उनके पास वित्त, शिक्षा, उच्च शिक्षा, टीटीई, योजना, पीडब्ल्यूडी, जल, बिजली, सेवाएं, सतर्कता, जनसंपर्क, कानून जैसे प्रमुख विभाग हैं। ऐसे में सीएम पद पर उनकी दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता है। आतिशी के अलावा कैलाश गहलोत का नाम भी इस पद के लिए लिया जा रहा है। उनके पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, गृह, महिला एवं बाल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख विभाग हैं। गहलोत ऐसे मंत्री हैं जो सरकार के उलझे हुए काम भी करा पा रहे हैं। उनके विभागों से संबंधित सभी बड़ी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को साधने के लिए पार्टी सीएम की कुर्सी उन्हें सौंप सकती है।

बैनर बनाने वाला हर माह बनाता था 20 से 50 फर्जी वीजा, सात गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर सात को दबोचा
- पांच वर्ष में सैकड़ों लोगों के बना चुका है वीजा, तिलक नगर इलाके में घर से करता था काम

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट थाना पुलिस ने फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य आरोपित 20 वर्ष से बैनर बनाने का काम कर रहा था। वह मात्र 20 से 25 मिनट में किसी भी देश का फर्जी वीजा बना देता है। पांच वर्ष से वह हर माह कम से कम 20 से 50 वीजा ऐसे तैयार कर देता है, जिसे यह बता पाना मुश्किल हो जाता है कि यह नकली है या असली।

आरोपितों की पहचान तिलक नगर के मनोज मोंगा, निलोठी गांव के बलबीर सिंह, हरियाणा के करनाल के असंध के नवीन राणा, नीलोखेड़ी गांव के जसविंद्र सिंह उर्फ मिंटी, जींद के सफीदों गांव के आशिफ अली, कुरुक्षेत्र के दीवाना गांवे के संदीप व नेपाल के काठमांडू के शिवा गौतम उर्फ नेपाली के रूप में हुई है। आरोपितों के पास से 30 फर्जी वीजा स्टीकर, विभिन्न देशों के 23 रबड़ स्टैंप, तीन फर्जी पीआर कार्ड, नेपाल के 14 व भारत के दो पासपोर्ट, डाई मशीन समेत वीजा व पासपोर्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बरामद हुआ है।

प्रतीकात्मक

आइजीआइ एयरपोर्ट के जिला पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि दो सितंबर को संदीप फर्जी वीजा लेकर इटली जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। जांच की गई तो उसके पासपोर्ट पर नकली वीजा मिला। आइजीआए एयरपोर्ट थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

नीट में आल इंडिया पहली रैंक हासिल कर चुके एमडी छात्र ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पारसी अंजुमन धर्मशाला के कमरे में पंखे से लटका मिला शव
- कमरे से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, पुलिस कर रही कार्रवाई

मध्य जिले के आइपी एस्टेट थाना क्षेत्र में स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कालेज से रेडियोलाजी विभाग से एमडी कर रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली। रविवार सुबह छात्र का शव दिल्ली पारसी अंजुमन (पारसी धर्मशाला) स्थित उनके कमरे में पंखे से लटका मिला। मृतक की पहचान डाक्टर नवदीप सिंह के रूप में हुई है।

वह मूल रूप से पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला था। पुलिस ने शाम को ही पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सौंप दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह पारसी धर्मशाला के गार्ड ने बताया कि नवदीप का कमरा अंदर से बंद है। काफी देर खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो अन्य लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया, जहां कमरे में नवदीप का शव पंखे पर लटका मिला। फोरेंसिक की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। 2017 में नीट में आई थी पहली रैंक नवदीप के सीनियर डाक्टर ने बताया कि नवदीप ने नीट 2017 के बैच में आल इंडिया पहली रैंक हासिल की थी। वह पढ़ाई में बहुत होनहार था। नीट पास करने के बाद उसने मौलाना आजाद कालेज में एमबीबीएस में दाखिला लिया था। एमबीबीएस पूरा होने के बाद उसने एमडी में प्रवेश लिया। वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था।

डाक्टर नवदीप सिंह। फाइल

एमबीए छात्र ने आइपीयू के हास्टल से कूदकर दी जान

जासं, पश्चिमी दिल्ली: द्वारका सेक्टर-16 के गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) में रविवार शाम को हास्टल की सातवीं मंजिल से कूदकर एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र ने जान दे दी। छात्र की पहचान बिहार के वैशाली के राजा पाकर के गौतम कुमार सिन्हा के रूप में हुई है। शराब व गांजे के सेवन करने के आरोप में उसे हास्टल से निकाल दिया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि छात्रों को रविवार दो बजे तक हास्टल के कमरों को खाली करने को कहा गया था। गौतम के पास रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। इसी को लेकर वह परेशान था। हास्टल से न निकालने को लेकर उन्होंने हास्टल स्टाफ से भी संपर्क किया था। जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने जान दे दी। इसको लेकर रविवार रात में छात्रों ने प्रदर्शन किया।

फरीदाबाद अंडरपास हादसे का पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू

- शुक्रवार देर रात अंडरपास के जलभराव में बैंक के वाइस प्रेसीडेंट पुन्याश्रय शर्मा व कैशियर विराज द्विवेदी की हुई थी मौत

पानी निकासी के बाद अंडरपास में दिखाई दे रहा कचरा व कीचड़। जागरण

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

शुक्रवार देर रात ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास के जलभराव का शिकार हुए एचडीएफसी बैंक के वाइस प्रेसीडेंट और कैशियर के मामले में पुलिस खुद संज्ञान ले रही है। मामले की जांच शुरू कर दी है। एक टीम का गठन कर दिया है जो देख रही है कि हादसा कैसे और क्यों हुआ। लापरवाह अधिकारी चिन्हित किए जा रहे हैं। पुलिस जल्द मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। उधर, मृतक विराज के भाई विक्रम ने भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत तैयार कर ली है। सोमवार को एनआइटी थाने में शिकायत दी जाएगी।

सहकर्मी बोले, बहुत बड़ी क्षति: एचडीएफसी बैंक में कैशियर विराज के साथ काम करने वाले विवेक पांडे का रो-रोकर बुरा हाल है। दूसरे साथी सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि विराज जैसा कोई नहीं हो सकता। वाइस प्रेसीडेंट पुन्याश्रय शर्मा के बारे में अमित बताते हैं कि बड़ा अधिकारी होने के बावजूद सभी से हर समय प्यार से बात करते थे। हादसे के बाद कई बैंककर्मियों ने उनकी फोटो अपनी डीपी पर लगा ली। सोमवार को बैंक में सामूहिक रूप से शोक भी जताया जाएगा। ग्रेटर फरीदाबाद की ओमेक्स सोसायटी में जहां पुन्याश्रय शर्मा रहते थे, वहां गमगीन माहौल है। मृतकों के शव का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश स्थित उनके पैतृक गांव में किया गया था।

पानी निकाला, आवागमन शुरू नहीं: ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में रविवार को पानी निकाल दिया गया था। लेकिन आवागमन शुरू नहीं हो सका। अंडरपास के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की हुई है। अंडरपास में कचरा व फिसलन है। एनएचपीसी रेलवे अंडरपास में भी जलभराव देखा गया। वाहनों का आवागमन जारी था। अंडरपास में पिछले साल पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अंडरपास का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद इस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ सका।

चश्मदीद बोला, फुटपाथ की ओर बढ़ रहे थे पुन्याश्रय: रविवार को अंडरपास पर मिले प्रदीप ने बताया कि घटना के समय वह मौजूद थे। पानी में डूबी कार से पुन्याश्रय व विराज बाहर निकल गए थे। पुन्याश्रय बाहर निकलने के लिए हाथ-पैर मार रहे थे। वहां मौजूद लोगों ने उनसे फुटपाथ की ओर आने को कहा, ताकि बचाव हो सके। लेकिन पुन्याश्रय डूबते चले गए। दूसरी ओर, विराज तो एक-दो बार ही ऊपर आया, फिर डूब गया था।

> अंडरपास बनाने की तकनीक ही सही नहीं होती। पूरा अंडरपास ऊपर से ढका होना चाहिए। आने-जाने वाली जगह ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वर्षा का पानी अंदर न जाए। यदि जाए तो तुरंत पानी निकासी के इंतजाम होने चाहिए।
>
> – रोहित बलूजा, निदेशक, कालेज आफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, सूरजकुंड रोड

> हादसा बहुत बड़ा है। सूचना मिलते ही मैं घटनास्थल पर पहुंच गया था। इस मामले की रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। लापरवाही सामने आने पर कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ऐसा हादसा दोबारा न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।
>
> – कुलदीप सिंह, डीसीपी एनआइटी

> अधिकतर सड़क हादसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होते हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई बार मुद्दा उठा चुके हैं कि जिम्मेदारों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आरोपित गिरफ्तार होने चाहिए।
>
> – सरदार देवेंद्र सिंह, सदस्य, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, हरियाणा

कार्ययोजना

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने निकाला टेंडर, 30 सितंबर तक मांगे गए प्रस्ताव, एक वर्ष के अनुबंध पर निजी एजेंसी को दिया जाएगा रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी का काम

वायु प्रदूषण की निगरानी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

संजीव गुप्ता ● जागरण

नई दिल्ली: राजधानी में वायु प्रदूषण की निगरानी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। विशेषज्ञ एजेंसी रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी (वास्तविक समय में प्रदूषक तत्वों का अध्ययन) करेगी। मोबाइल मानिटरिंग लैब के संचालन का जिम्मा भी इसी एजेंसी के पास रहेगा। अगले महीने तक एजेंसी को दायित्व सौंपने की संभावना है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने इसे लेकर टेंडर निकाला है। 30 सितंबर तक विशेषज्ञ एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। 18 सितंबर को प्री बिड बैठक रखी गई है। चयनित एजेंसी के साथ एक वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। एजेंसी को वायु प्रदूषण के स्तर और उसके कारकों की हिस्सेदारी पर प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक रिपोर्ट तैयारी करनी होगी। साथ ही मोबाइल मानिटरिंग लैब वैन को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तैनात कर वहां के प्रदूषण और प्रदूषक तत्वों पर भी रिपोर्ट बनानी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जा रहा पानी का छिड़काव। फाइल

शुरू होने के कुछ माह बाद ही विवादों में हो गई थी बंद

दिल्ली सरकार ने 2021 में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले स्रोतों की पहचान करने और प्रभावी नीतियां बनाने के लिए आइआइटी कानपुर के साथ रियल टाइम अपोर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया था। सात जुलाई, 2021 को कैबिनेट ने निर्णय लिया। आइआइटी कानपुर को 12.727 करोड़ रुपये व जीएसटी के साथ वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी और पूर्वानुमान तैयार करने की परियोजना सौंपी गई, लेकिन डीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी कुमार के साथ आप सरकार के विवाद में 30 जून, 2024 को शुरू हुई सुपरसाइट कुछ माह बाद ही बंद कर दी गई।

> बीती 20 फरवरी को हुई बोर्ड बैठक में रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट स्टडी को लेकर कुछ सवाल उठाए गए थे। अब इसे दोबारा शुरू करने के निर्णय की कोई जानकारी बोर्ड सदस्यों को नहीं दी गई है। 27 सितंबर को अगली बोर्ड बैठक होनी है। इसी बैठक में इस संदर्भ में तस्वीर साफ हो पाएगी। – डा. अनिल गुप्ता, सदस्य, डीपीसीसी

****

1881 में हुई थी भारत में जनगणना की शुरुआत। स्वतंत्रता के बाद भारत में 1951 से 2011 तक की जनगणना हुई है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, उस समय भी जातिवार जनगणना की मांग उठी थी।

देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना

केंद्र की तैयारी शुरू, जनगणना प्राधिकरण ने स्वगणना पोर्टल बनाया

दलों की मांग के बाद भी जातीय जनगणना पर फिलहाल फैसला नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने देश में जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जातीय जनगणना पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिये नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लांच नहीं किया गया है। स्वगणना के दौरान आधार नंबर या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा। पूरी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की प्रक्रिया पर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है।

एक सूत्र ने रविवार को अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि हर दशक में होने वाली जनगणना जल्द ही कराई जाएगी। लेकिन दशकीय जनगणना में जाति संबंधी कालम शामिल करने के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, 'इस पर निर्णय होना अभी बाकी है।' राजनीतिक दल जाति जनगणना कराने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं। नए आंकड़े नहीं होने के कारण सरकारी एजेंसियां अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बना रही हैं और सब्सिडी आवंटित कर रही हैं। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। इस दशक की जनगणना का पहला चरण एक अप्रैल, 2020 को शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा।

जनगणना के लिए 31 सवाल किए गए तैयार

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने जनगणना के दौरान पूछने के लिए 31 सवाल तैयार किए हैं। इसमें पूछा जाएगा कि एक परिवार में कितने लोग रहते हैं और परिवार का मुखिया महिला है क्या। इसके अतिरिक्त परिवार के मुखिया अगर एससी/एसटी हैं तो यह जानकारी भी मांगी जाएगी। पूछेंगे कि एक परिवार के पास एक टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या स्मार्टफोन है या नहीं। उनके पास वाहनों में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर कार, जीप या वैन है या नहीं। पूछेंगे आप कौन सा अनाज अधिक खाते हैं। उनके पेयजल, बिजली, शौचालय, गंदे पानी की निकासी, रसोई और रसोई में एलपीजी/पीएनजी आदि की उपलब्धता की भी जानकारी ली जाएगी।

महिला आरक्षण भी जनगणना पर निर्भर

पिछले वर्ष संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन भी इसी दशकीय जनगणना से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने संबंधी कानून इस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा। जनगणना के तहत घरों को सूचीबद्ध करने का चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने का कार्य एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक पूरे देश में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।

ऐसे की जाएगी गणना

- जनगणना पोर्टल खुल जाने के बाद, व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लागइन कर सकता है और अपना विवरण भर सकता है।
- जनगणना पोर्टल में व्यक्तियों को जनसंख्या गणना के लिए फार्म भरना होगा।
- विभिन्न विकल्पों को भरने के लिए स्क्रीन पर कोड डिसप्ले होंगे।
- एक बार स्व-गणना हो जाने के बाद, मोबाइल पर एक पहचान संख्या भेजी जाएगी।
- जब जनगणनाकर्मी घर-घर जाएंगे तो उनके साथ वह आईडी नंबर साझा किया जा सकता है, जो पहले से भरे हुए सभी डेटा को अपने आप आनलाइन सिंक कर देगा।

निर्मला सीतारमण ने की थी डिजिटल जनगणना की घोषणा

एक फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में डिजिटल जनगणना किए जाने की घोषणा की थी। साथ ही बजट में इसके लिए 3,726 करोड़ रुपये भी आवंटित किए थे। जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया था कि कोरोना महामारी की वजह से 2021 की जनगणना और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

मेलबर्न विश्वविद्यालय भी अब देश में देगा दस्तक, दिल्ली में खोलेगा केंद्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इस केंद्र के जरिये शैक्षणिक व शोध गतिविधियां होंगी संचालित
- दो आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय पहले ही गिफ्ट सिटी में खोल चुके हैं अपना परिसर
- इंग्लैंड का साउथहेम्प्टन विश्वविद्यालय भी अगले साल से गुरुग्राम में अपना परिसर शुरू करने जा रहा है

मेलबर्न यूनिवर्सिटी। फाइल

विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजा खोलने के बाद दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों का देश में दस्तक देने का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड के साउथहेम्प्टन विश्वविद्यालय के बाद आस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भी अब देश में अपना एक केंद्र बनाने का फैसला लिया है, जो दिल्ली में स्थापित होगा। इसके जरिये विश्वविद्यालय सभी शैक्षणिक व शोध गतिविधियां संचालित करेगा। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय इसी हफ्ते अधिकारिक घोषणा करेगा।

मेलबर्न विश्वविद्यालय वैसे भी मौजूदा समय में क्यू रैंकिंग में आस्ट्रेलिया का नंबर एक व दुनिया का 13वां सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। ऐसे में देश में इसकी दस्तक से उच्च शिक्षा के क्षेत्र को एक नई मजबूती मिलेगी। मेलबर्न विश्वविद्यालय के इस फैसले से देश में दस्तक देने वाला यह चौथा विदेशी विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले आस्ट्रेलिया के ही दो विश्वविद्यालय डीकिन व बोलोंगांग गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कर चुके हैं। वहीं इंग्लैंड का साउथहेम्प्टन विश्वविद्यालय भी अगले साल से गुरुग्राम में अपना परिसर शुरू करने जा रहा है। सूत्रों की मानें तो इस साल के अंत तक कुछ और विदेशी विश्वविद्यालय देश में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने का ऐलान कर सकते है।

एनईपी की सिफारिश के बाद तेज हुई पहल

विदेशी विश्वविद्यालयों के देश में दस्तक देने का यह सिलसिला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद शुरू हुई है। इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए दरवाजे खोलने की सिफारिश थी। इसके बाद यूजीसी ने देश में परिसर खोलने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए एक नई गाइडलाइन भी तैयार की है। दुनिया के शीर्ष सौ रैंकिंग में शामिल संस्थानों को देश में परिसर खोलने की अनुमति मिलेगी।

अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में आएगा कमी

शिक्षा मंत्रालय की मानें तो इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए हर साल देश से बड़ी संख्या में छात्रों के विदेश में होने वाला पलायन थमेगा। उन्हें अब देश में कम खर्च पर वह शिक्षा मिलेगी। इसके साथ ही ऐसे छात्र भी अब अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, जो विदेश में रहने-खाने के महंगे खर्च के चलते अब तक दुनिया के इन शीर्ष संस्थानों में पढ़ने नहीं जा पाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में हर साल करीब 10 से 12 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं। इस पहल से देश की प्रतिभा का पलायन भी रुकेगा। अभी पढ़ाई के लिए जाने वाले ज्यादातर छात्र पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं बस जाते हैं।

गृह मंत्री शाह ने जारी किया हिंदी कहावत कोश का दूसरा संस्करण

नई दिल्ली, प्रेट्र: हर भारतीय अपनी बात खत्म करने में किसी न किसी कहावत या लोकोक्ति का उपयोग किया करता था, लेकिन समय के साथ हिंदी की लोकोक्तियां, कहावतें और मुहावरे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। हिंदी कहावतों को संरक्षित करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बरेली के चिकित्सक शरद अग्रवाल द्वारा लिखित हिंदी कहावत कोश के दूसरे संस्करण को गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जारी किया। इसमें 10 हजार से अधिक हिंदी कहावतों और 200 से अधिक कहानियां हैं।

चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शाह ने कहा कि अग्रवाल की किताब पढ़ने से भाषा बोलने की क्षमता में काफी सुधार होगा। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि किताब का विचार उन्हें दादी से आया था। किताबों और इंटरनेट सहित विभिन्न स्रोतों से इन कहावतों को इकट्ठा करने में उन्हें 20 साल लग गए। 5,400 कहावतों वाली पुस्तक का पहला संस्करण 2021 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जारी किया था।

आर्थिक कुप्रबंधन से निकलने की राज्यवार नीति हो प्राथमिकता

जयप्रकाश रंजन ● जागरण

- राज्यों को तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों पर एक साथ काम करने की जरूरत
- खर्च घटाने के साथ-साथ विनिवेश, जमीन के व्यावसायीकरण जैसे कदमों पर विचार

नई दिल्ली : भारत जितनी विविधता वाला देश है, इसके राज्यों की आर्थिक स्थिति भी उतना ही विविध रंग लिए हुए है। पिछले दो आलेखों में यह स्पष्ट दिखा कि खजाने की कीमत पर राजनीति और प्रशासकीय शिथिलता के कारण कुछ राज्य निवेश आकर्षित करने में, राजकोषीय घाटा कम करने में, बाहरी कर्ज का बोझ कम करने, प्रतिव्यक्ति आय जैसे मापदंडों पर पिछड़ते जा रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो इन सभी मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। नतीजा यह है कि राज्यों के बीच आर्थिक फासला भविष्य में और बढ़ने के संकेत हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, बैट्री निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा से जुड़े उद्योग का आकर्षण सिर्फ गुजरात, तमिलनाडु व कुछ हद तक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक ही सीमित रहा है, वह इसका उदाहरण है।

दूसरी तरफ कुछ राज्य खुलकर अपना खजाना खाली दिखा रहे हैं। इन हालात में विशेषज्ञों का कहना है कि हर राज्य के वित्त की अपनी मजबूती व खामियां हैं और इसके आधार पर ही इनकी आर्थिक नीतियों को बनाना होगा। यह काम और इसकी प्लानिंग जितनी जल्दी हो, उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो वर्ष 2047 में जब भारत एक विकसित देश होगा तब भी इसके कुछ राज्य 'बीमारू' होने का तमगा पहने होंगे।

वित्त मंत्रालय के पूर्व आर्थिक सलाहकार व नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहते हैं कि राज्यों को खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कुछ कदम तत्काल उठाने होंगे और कुछ दीर्घकालिक होंगे। जिन राज्यों की वित्तीय स्थिति लचर है उन्हें गैरजरूरी खर्चों पर तत्काल लगाम लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यों को निजी निवेश बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश करना होगा।

कर्ज कम नहीं किया तो नहीं होगा सरकार चलाने के लिए पैसा : सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्य विशेष के लिए किसी बेल आउट पैकेज जैसी व्यवस्था की संभावना तो नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति में जरूर वित्तीय पैकेज दिया जाता है। ऐसे में राज्यों को तात्कालिक रूप से जो कदम उठाए जाने चाहिए उसमें विनिवेश और मौद्रिकीकरण है। जो सरकारी उपक्रम फायदेमंद नहीं है, उसका विनिवेश किया जाए। संपदा के मौद्रिकीकरण के साथ वे घाटे में चल रहे अपने उपक्रमों को बेचकर राजस्व अर्जित कर सकते हैं। राज्यों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग कर राजस्व बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इन माध्यम से जो राजस्व मिले उसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जाए। इन राशियों का कहीं और इस्तेमाल करने से फिर कोई फायदा नहीं होगा। कर्ज कम करने की कोशिश अगर राज्यों की तरफ से नहीं होती है तो एक समय ऐसा आएगा कि इनके पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं बचेगा।

मुफ्त में कोई और सेवा दी तो स्थिति बदतर होगी : आरबीआइ

हाल ही में जब पुरानी पेंशन स्कीम को

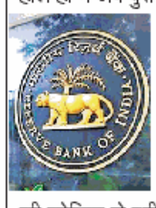

लेकर राजनीति चरम पर थी और राज्य चुनावों में इसे सत्ता पर दोबारा काबिज होने के ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही थी, तब आरबीआइ ने चेताया था कि यह राज्यों के वित्तीय बोझ को 4.5 गुणा तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक ने इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की वकालत की थी। आरबीआइ का मानना है कि राज्य अगर अब कोई भी नई गैर वाजिब सेवा मुफ्त में देते हैं या सब्सिडी, फंड ट्रांसफर की घोषणा करते हैं तो इससे उनकी कुल आर्थिक स्थिति बदतर ही होगी। स्पष्ट है कि एक ऐसा दौर आ चुका है जब केवल सत्ता में आसीन दल को ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को ऐसी राह चुननी होगी जो जनकल्याणकारी होने के साथ राज्य के वित्तीय हित में हो। यानी इस विषय पर पक्ष और विपक्ष को एक बिंदु पर आना होगा।

उच्च शिक्षण संस्थानों में कल चलेगा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया जाएगा नया कीर्तिमान
- सितंबर तक 80 करोड़ पौधे रोपने का है लक्ष्य, अब तक रोपे गए हैं 70 करोड़ पौधे

पौधरोपण से जुड़े 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 17 सितंबर को देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में एक दिन का विशेष अभियान चलेगा। खास बात यह है कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में देश भर सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि वह पौधरोपण से जुड़े इस अभियान से जुड़ें और पौधरोपण का एक नया कीर्तिमान बनाएं।

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश तब दिया है, जब 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि इसके तहत अब तक करीब 70 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। माना जा रहा है कि इस अभियान के जरिये इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश होगी। वैसे भी अभी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए करीब 15 दिन का समय बचा है। इसके साथ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों और सरकारी विभागों को भी पौधरोपण के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिए है। पौधरोपण से जुड़े 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान का शुरुआत पांच जून को पीएम नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके खुद एक पौधा रोप करके की थी। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत इस साल सितंबर तक जहां 80 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मार्च 2025 तक 140 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। यानी अभियान के तहत अगले साल 70 करोड़ पौधे और रोपे जाएंगे। मां से जुड़ा होने के चलते इस अभियान से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं।

वायु सेना में अगले वर्ष तक तेजस एएफ मार्क-2 शामिल होगा

- वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से 324 तेजस खरीदने की योजना बनाई है

नई दिल्ली, आइएएनएस: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देश्यीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान (एलसीए एएफ मार्क-2) को 2025 तक भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा। एयरोनाटिक्स डेवलपमेंट अथारिटी एजेंसी बेंगलुरु के एक अधिकारी वाजी राजपुरोहित ने बताया कि वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से 324 तेजस विमान खरीदने की योजना बनाई है, जिसमें एलसीए एएफ मार्क-2 भी शामिल है।

यह मिसाइल एप्रोच चेतावनी प्रणाली जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस है। उम्मीद है कि अगले दशक में एलसीए मार्क-2 मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 जैसे पुराने विमानों की जगह ले लेगा। भारतीय रक्षा प्रयोगशाला द्वारा विकसित तेजस को पहली बार 1980 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह एक सिंगल-इंजन डेल्टा-विंग, मल्टी-रोल लाइट फाइटर है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के सहयोग से डिजाइन किया गया है। एलसीए को आधिकारिक तौर पर 2003 में तेजस नाम दिया गया था। इसे लड़ाकू श्रेणी में सबसे छोटा और हल्का विमान माना जाता है।

वायु सेना के पायलट ने एआइ-संचालित विमान निरीक्षण प्रणाली विकसित की: एएनआइ के अनुसार, भारतीय वायु सेना एमसीसी के एसयू-30 एमकेआइ पायलट स्क्वाड्रन लीडर भटकरे ने एआइ-संचालित विमान निरीक्षण प्रणाली विकसित की है। यह सुविधा उन दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, जो पहले मानवीय त्रुटियों के कारण होती थीं।

तारिणी जहाज से विश्व परिक्रमा करेंगी नौसेना की दो महिला अफसर, तीन वर्ष से कर रहीं तैयारी

भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. और दिलना के.। दोनों पिछले तीन वर्ष से विश्व परिक्रमा के अभियान के लिए तैयारी कर रही हैं। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. और दिलना के. आइएनएसवी तारिणी जहाज से महासागरों की विश्व परिक्रमा करेंगी। भारतीय नौसेना के अनुसार यह अभियान साबित करता है कि समुद्र में नारी शक्ति भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है।

नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि समुद्री कौशल और रोमांच जारी रखते हुए भारतीय नौसेना की दोनों अधिकारी जल्द ही दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी। दोनों तीन साल से इस अभियान की तैयारी कर रही हैं। सागर परिक्रमा में अत्यधिक कौशल, शारीरिक फिटनेस और मानसिक सतर्कता की जरूरत होगी। इसके लिए दोनों अधिकारी कठोर प्रशिक्षण ले रही हैं और हजारों मील का अनुभव प्राप्त कर रही हैं। दोनों को गोल्डन ग्लोब रेस के हीरो कमांडर अभिलाष टामी (सेवानिवृत्त) प्रशिक्षण दे रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने गत वर्ष गोवा से केपटाउन होते हुए रियो डी जनेरियो और वापस ट्रांस-महासागरीय अभियान में भाग लिया था। साथ ही गोवा से पोर्ट ब्लेयर तक और वापस डबल हैंडेड मोड में नौकायन अभियान चलाया था। दोनों ने गोवा से पोर्ट लुइस, मारीशस तक सफलतापूर्वक यात्रा की थी।

भारत ने तूफान प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को तत्काल मदद भेजी

- पड़ोसी देशों की मदद के लिए आपरेशन सद्भाव लांच
- म्यांमार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 113 हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने तूफान यागी के प्रभाव से निपटने में म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए रविवार को इन तीनों देशों में राहत सामग्री भेजी है। आपरेशन सद्भाव के तहत यह मानवीय सहायता भेजी गई है।इस साल एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान कहे जाने वाले तूफान यागी के आने के बाद म्यांमार, लाओस और वियतनाम बाढ़ से जूझ रहे हैं। इस बीच, म्यांमार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 113 हो गई है। करीब 3,20,000 विस्थापित हुए हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारतीय नौसैनिक जहाज आइएनएस सतपुड़ा पर राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता म्यांमार भेजी गई। भारतीय वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान वियतनाम के लिए 35 टनऔर लाओस के लिए 10 टन राहत सामग्री ले जा रहा है। वायुसेना ने वियतनाम में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान के लिए अपने सी-17 ग्लोबमास्टर विमान को तैनात किया है।

जयशंकर ने कहा कि भारत ने आपरेशन सद्भाव लांच किया है। भारत यागी से प्रभावितों से अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए म्यांमार, वियतनाम और लाओस को सहायता भेज रहा है। वायुसेना का परिवहन विमान वियतनाम के लिए वाटर प्यूरीफायर, पानी के कंटेनर, कंबल, बर्तन सहित 35 टन मदद ले जा रहा है। लाओस के लिए सहायता में जेनसेट, वाटर प्यूरीफायर, मच्छरदानी, कंबल और स्लीपिंग बैग शामिल हैं।

नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के विमान में तूफान टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस के लिए राहत सामग्री रखते सुरक्षा बल के जवान। प्रेट्र

उपाय

पर्यावरण की चिंता में स्क्रैपिंग नीति को प्रोत्साहित कर रही सरकार की व्यावहारिकता पर भी नजर, सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों की कमी के बीच वाहन निर्माता कंपनियों को नई तकनीक का सुझाव

प्रदूषण फैला रहीं निगमों की पुरानी बसें, ईवी किट है विकल्प

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदूषण की समस्या झेल रहे देश में परिवहन निगमों की बसों का पुराना बेड़ा भी बड़ी समस्या बना हुआ है। सार्वजनिक परिवहन के संसाधनों की कमी से जूझ रहे तमाम राज्यों की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय चाहता है कि निगमों की जो बसें अभी संचालन के मानकों के अनुरूप फिट हैं, उनमें ईवी किट लगाने का विकल्प रखा जाए। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों से तकनीक पर काम करने को कहा गया है।

लगातार बढ़ रही वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में अलग-अलग अवधि के वाहनों पर प्रतिबंध लगा भी है, लेकिन अमल को लेकर उतनी गंभीरता नहीं है। मगर, केंद्र सरकार की चिंता पर्यावरण के साथ ही मानव जीवन को लेकर भी है। इसलिए पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने के लिए स्क्रैपिंग नीति पर जोर है। वर्तमान में भारत स्टेज-6 यानी बीएस-6 श्रेणी के वाहन प्रदूषण के मानकों पर फिट घोषित हैं। बीएस-5 वाहन भी चल रहे हैं, लेकिन उससे पुराने वाहन चिंता का सबब हैं। हालांकि सरकारी वाहनों को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं कि 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं होगा। इसके बावजूद एक समस्या यह भी है कि राज्यों में बसों का बेड़ा अधिकतर पुराना ही है और सभी बसों को स्क्रैप करा देने की स्थिति नहीं है। एक अध्ययन के मुताबिक, परिवहन निगमों द्वारा संचालित बसों की संख्या लगभग 2.8 लाख है, जबकि आबादी के अनुरूप आवश्यकता करीब 30 लाख बसों की है। ऐसे में विचार है कि पुरानी फिट बसों को पर्यावरण के मानकों के अनुरूप बनाकर संचालन में रखे जाने के विकल्प पर काम किया जाए।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन का कहना है कि आमजन को स्वयं पर्यावरण और मानव जीवन को ध्यान में रखते हुए अनफिट वाहनों को स्क्रैप करा देना चाहिए, लेकिन सरकार इसे कैसे आगे बढ़ा सकती है, इस पर विचार चल रहा है। आटोमोबाइल कंपनियों के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है। उनसे कहा गया है कि ऐसी तकनीक पर काम करें कि परिवहन निगमों की फिजिकली फिट पुरानी बसों के डीजल इंजन को निकालकर उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक व्हीकल किट लगाई जा सके। यह तकनीक सफल होती है तो पर्यावरण की सुरक्षा रहेगी और राज्य भी बस बेड़े के अधिक स्क्रैपिंग के भार से बच सकेंगे।

****

नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन कल से

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर सुरक्षा परिदृश्य को लेकर मंगलवार से बैठक करेंगे। हाल ही में लखनऊ में आयोजित संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा बलों से अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने के आह्वान किया था। रक्षामंत्री के आह्वान के कुछ ही दिनों बाद नौसेना के शीर्ष अधिकारियों की यह बैठक हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी स्थित नौसेना मुख्यालय में 17 सितंबर से चार दिनों तक होगा। यह सम्मेलन एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के नौसेना प्रमुख का पदभार संभालने के बाद आयोजित पहला सम्मेलन होगा। बैठक में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के कारण उभरती सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। शीर्ष नौसेना अधिकारी नए थियेटर कमांडों के सृजन के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। नौसेना वर्ष में दो बार कमांडर सम्मेलन आयोजित करती है।

कह कर रहेंगे — माधव जोशी

90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1559 उम्मीदवारों ने 1746 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जांच के दौरान इनमें 1221 की उम्मीदवारी वैध पाई गई, जबकि 338 की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर, 2024

भाजपा और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से रोमांचक हुआ चुनाव

सुधीर तंवर • जागरण

चुनावी परिदृश्य

चंडीगढ़: हरियाणा में हैट-ट्रिक बनाने की जिद्दोजहद में जुटी भाजपा और 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से विधानसभा चुनाव रोमांचक हो गया है। 90 में से 36 विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा और कांग्रेस ने एक ही जाति के उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाट बनाम जाट तो 15 सीटों पर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) बनाम ओबीसी मुकाबला होगा।

जातिगत समीकरणों के अनुसार प्रदेश में कोई भी चुनावी किला फतह करने में ओबीसी (33 प्रतिशत आबादी), जाट (25 प्रतिशत) और दलित (21 प्रतिशत) की भूमिका सबसे अधिक होती है। इसके मद्देनजर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा

28 जाट उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने 16 सीटों पर जाट प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। भाजपा ने सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार ओबीसी से बनाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इस वर्ग से 20 प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे हैं। 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनको छोड़कर किसी दल ने सामान्य सीट पर दलित समुदाय को टिकट नहीं दिया है।

बल्लभगढ़ से भाजपा के मूलचंद शर्मा और कांग्रेस की पराग शर्मा तो गन्नौर में भाजपा के देवेंद्र कौशिक और कांग्रेस के कुलदीप शर्मा में टक्कर है। चार सीटों पर पंजाबी आमने-सामने हैं, जिनमें थानेसर से भाजपा के सुभाष सुधा और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा, हांसी में भाजपा के विनोद भयाना व कांग्रेस के राहुल मक्कड़, पानीपत शहरी में भाजपा के प्रमोद विज और कांग्रेस के वरिंदर शाह और रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर तथा कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा भिड़ रहे हैं। फिरोजपुर झिरका में भाजपा ने नसीम अहमद और कांग्रेस ने मामन खान तो पुन्हाना में भाजपा ने ऐजाज खान और कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को आमने-सामने किया है।

जगाधरी में भाजपा के कंवरपाल गुर्जर के मुकाबले कांग्रेस ने अकरम खान, नूंह में भाजपा के संजय सिंह के मुकाबले कांग्रेस ने आफताब अहमद और हथीन में भाजपा के मनोज रावत के मुकाबले में कांग्रेस ने मुहम्मद इजरायल को मैदान में उतारा है।

इन सीटों पर ओबीसी बनाम ओबीसी

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा	कांग्रेस
समालखा	मनमोहन सिंह भड़ाना	धर्म सिंह छौक्कर
आदमपुर	भव्य बिश्नोई	चंद्रप्रकाश
बरवाला	रणबीर गंगवा	रामनिवास घोड़ेला
नारायणगढ़	पवन सैनी	शैली चौधरी
कोसली	अनिल यादव ढ्हीना	जगदीश यादव
रेवाड़ी	लक्ष्मण सिंह	चिरंजीव राव
बादशाहपुर	राव नरबीर सिंह	वर्धन सिंह
सोहना	तेजपाल तंवर	रोहताश खटाना
तिगांव	राजेश नागर	रोहित नागर
इंद्री	रामकुमार कश्यप	राकेश कंबोज
अटेली	आरती राव	अनीता यादव
महेंद्रगढ़	कंवर सिंह यादव	राव दान सिंह
नारनौल	ओमप्रकाश यादव	राव नरेंद्र सिंह
नांगल चौधरी	अभय सिंह यादव	मंजू चौधरी

इन विधानसभा क्षेत्रों में जाट बनाम जाट मुकाबला

विधानसभा क्षेत्र	भाजपा	कांग्रेस
गढ़ी सांपला किलोई	मंजू हुड्डा	भूपेंद्र सिंह हुड्डा
लोहारू	जयप्रकाश दलाल	राजवीर फरटिया
बाढड़ा	उमेद सिंह पातुवास	सोमबीर सिंह श्योराण
कलायत	कमलेश ढांडा	विकास सहारण
पानीपत ग्रामीण	महिपाल ढांडा	सचिन कुंडू
नारनौंद	कैप्टन अभिमन्यु	जसबीर उर्फ जस्सी पेटवाड़
बरोदा	प्रदीप सांगवान	इंदुराज नरवाल
टोहाना	देवेंद्र बबली	परमवीर सिंह
नलवा	रणधीर पनिहार	अनिल मान
बेरी	संजय कबलाना	डा. रघुवीर कादियान
दादरी	सुनील सांगवान	मनीषा सांगवान
तोशाम	श्रुति चौधरी	अनिरुद्ध चौधरी
महम	दीपक हुड्डा	बलराम दांगी
राई	कृष्णा गहलावत	जयभगवान अंतिल

हरियाणा के चुनावी रण में कितने योद्धा, आज हो जाएगा तय

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : हरियाणा में विधानसभा के चुनावी रण में कितने योद्धा, यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी। भाजपा नेताओं का दावा है कि उन्होंने 85 प्रतिशत तक असंतुष्टों को मना लिया है, जिन्होंने टिकट कटने से नाराज होकर नामांकन किया था। इसी तरह कांग्रेस बागियों को मनाने का दावा कर रही है। मान-मनौव्वल के बाद जिद छोड़ने वाले बागियों सहित अन्य कई प्रत्याशी आज दोपहर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब देब सहित अन्य कई बड़े नेता रविवार को भी बागियों को मनाने में जुटे रहे। इसी तरह कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ने असंतुष्टों को मनाने में कसर नहीं छोड़ी।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर आज थम जाएगा चुनाव प्रचार

भाजपा पहले चरण में 16 सीटों पर तो कांग्रेस-नेकां गठबंधन सभी पर लड़ रहा चुनाव

अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

- पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती राजनीतिक पारी की करेंगी शुरुआत
- पूर्व मंत्रियों, सांसदों व विधायकों की किस्मत दांव पर लगी

श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते पार्टी के चुनाव प्रभारी राम माधव। विज्ञप्ति

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 24 सीट पर होने वाले मतदान को लेकर सोमवार को प्रचार थम जाएगा। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जबकि कांग्रेस-नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) गठबंधन सभी सीटों पर उतरा है। कई पूर्व मंत्रियों, सांसदों व विधायकों की किस्मत दांव पर लगी है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी पहली बार मैदान में हैं। अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला है।

पहले चरण में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रामबन तथा कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की 24 सीट पर चुनाव हो रहा है। भाजपा के सुनील शर्मा, शक्ति परिहार, सोफी युसूफ, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, विकार रसूल वानी, नेकां के सज्जाद किचलू, हसनैन मसूदी, शौकत अहमद गनई, पीडीपी की युवा चेहरा इल्तिजा मुफ्ती, वहीद-उर-रहमान परा, सरताज अहमद मदनी जैसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं।

विनाब क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस-नेका गठबंधन आमने-सामने : चिनाब क्षेत्र के डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण को मतदान होना है। यहां 64 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें 25 निर्दलीय हैं। भद्रवाह में सबसे अधिक 10 उम्मीदवार, डोडा और इंद्रवाल में नौ-नौ, डोडा पश्चिम और रामबन में आठ-आठ, किश्तवाड़ और बनिहाल में सात-सात और पाडर-नागसेनी में छह उम्मीदवार मैदान में हैं। डोडा पश्चिम और पाडर-नागसेनी नई विधानसभा सीटें हैं। आठ सीटों पर नेकां और कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों में बनिहाल, भद्रवाह व डोडा में दोस्ताना मुकाबला है। इंद्रवाल से नेकां के एक बागी उम्मीदवार भी कांग्रेस उम्मीदवार के सामने हैं। भाजपा के भी दो बागी रामबन और पाडर-नागसेनी से किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के छह में से चार उम्मीदवार पूर्व महाधिवक्ता मोहम्मद असलम गोनी भद्रवाह, फातिमा बेगम इंदरवाल, आसिफ बनिहाल और गिरधारी लाल रामबन से चुनाव से हट गए। सभी आठ सीट पर भाजपा को कांग्रेस-नेकां गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। पीडीपी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।

कश्मीर में भाजपा आठ सीटों पर मैदान में : कश्मीर की 16 सीटों में से भाजपा सिर्फ आठ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर कांग्रेस-नेकां गठबंधन, पीडीपी सहित कई अन्य दलों के उम्मीदवार चुनाव को रोचक बना रहे हैं। पांपोर से नेकां के हसनैन मसूदी के खिलाफ पीडीपी के जहूर अहमद मीर और भाजपा के इंजीनियर सैयद शौकत अंद्राबी मैदान में हैं। अपनी पार्टी के अल्ताफ मीर और पांच निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 10 चुनाव मैदान में हैं। श्रीगुफवाडा बिजबिहाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां इल्तिजा मुफ्ती अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रही है। उनके सामने भाजपा के सोफी युसूफ और नेकां से बशीर अहमद शाह हैं। इस सीट से तीन ही उम्मीदवार हैं। डीएच पोरा में छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नेकां की सकीना इट्टू, पीडीपी के गुलजार अहमद डार और अपनी पार्टी के अब्दुल मजीद पडर के बीच मुख्य मुकाबला है। यहां से दो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं।

विज बोले- सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, मुख्यमंत्री पद के लिए दावा पेश करूंगा

जागरण संवाददाता, अंबाला

- कहा- अगर मुख्यमंत्री बना तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा
- अंबाला छावनी विधानसभा से छह बार विधायक रह चुके विज सातवीं बार चुनाव मैदान में डटे
- मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, अब लोग कह रहे- मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन जाते

अनिल विज। फाइल

अंबाला छावनी से छह बार विधायक, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी अनिल विज ने कहा कि सबसे वरिष्ठ विधायक हूं, इसलिए वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। अगर मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। मेरे पास पूरे अंबाला ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। इनका मानना है कि वरिष्ठता के अनुसार मुझे ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये बातें अंबाला छावनी में चुनाव कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में ही कही।

विज ने कहा कि मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही वरिष्ठ हो तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। विज ने अंबाला छावनी विधानसभा की उपलब्धियों का बखान किया और बताया कि कैसे उन्होंने विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता पाने के बाद ही लोगों के काम नहीं किए, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई। 20 साल के अपने संघर्ष के दिनों के बारे में उन्होंने बताया कि भूले-बिसरे नायकों की याद में एशिया का सबसे बड़ा स्मारक अंबाला में लाने का काम किया। इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। कई मुख्यमंत्रियों ने अनाज मंडी बनाने के लिए अपने शिलान्यास पट तो लगा दिए, लेकिन मंडी उन्होंने ही बनवाई।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा- नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा

जागरण संवाददाता, कैथल

केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं प्रदेश में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रदेश में सीएम पद का चेहरा नायब सिंह सैनी ही हैं। पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता के आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा 10 सालों में किसानों, महिलाओं, युवाओं के हित में कार्य किए गए हैं। हर वर्ग को ध्यान में रखकर भाजपा आगे बढ़ी है। प्रदेश का आर्थिक विकास हो या प्रदेश के वंचित वर्गों की बात हो, हर एक क्षेत्र में भाजपा सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। नायब सिंह सैनी की सरकार ने प्रदेश में उत्पादित फसलों पर एमएसपी दिया है, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी गईं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आने पर आरक्षण समाप्त करेंगे। पिछड़े लोगों के खिलाफ जो उनकी मानसिक स्थिति है, वह उसे बार-बार प्रकट करते हैं। पांच अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा। भाजपा जीत की हैट ट्रिक लगाएगी। उन्हें पूरा भरोसा है कि हरियाणा की जनता भाजपा को ही जिताएगी। वह रविवार को भाजपा के जिला कार्यालय कर्ण कमल पहुंचे थे।

दूसरे चरण के चुनाव के लिए मोदी का प्रचार कार्यक्रम तय

जागरण टीम, जम्मू

- 19 सितंबर को श्रीनगर और कटड़ा में दो रैलियां करेंगे

नरेन्द्र मोदी। फाइल

पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूसरे चरण के लिए भी प्रचार कार्यक्रम तय हो गया है। 19 सितंबर को श्रीनगर और कटड़ा में दो रैलियां करेंगे। प्रदेश भाजपा ने तीसरे चरण के लिए भी उनके उनकी रैलियां रखने का अनुरोध हाईकमान से किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री ने डोडा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश प्रभारी तरुण चुग श्रीनगर व सह प्रभारी आशीष सूद कटड़ा में रैली की तैयारियों में जुटे हैं। आशीष सूद ने जागरण को बताया कि प्रधानमंत्री पहले श्रीनगर में रैली करेंगे। इसके बाद वह कटड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की इन रैलियों को यादगार बनाने के लिए भाजपा द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 19 सितंबर को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह ग्यारह बजे सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह दोपहर को कटड़ा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में रैली को संबोधित करेंगे।

पहली बार बने श्रीमाता वैष्णो विधानसभा क्षेत्र के लिए भाजपा ने विशेष तैयारी की है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की रैली यहां रखी गई है। पूरे देश की नजर इस सीट पर इसलिए है कि भाजपा इस सीट पर अयोध्या जैसी स्थिति नहीं होने देगी। भाजपा नेताओं के अनुसार 70 हजार लोगों को एकत्रित होने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी 10 वर्ष के बाद कटड़ा पहुंचेंगे। इससे पहले वर्ष 2014 में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटड़ा के उद्घाटन अवसर पर कटड़ा पहुंचे थे।

अवामी इत्तेहाद पार्टी और प्रतिबंधित जमात के नेता एक साथ आए

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बीच लगातार राजनीतिक समीकरण बन-बिगड़ रहे हैं। इसी बीच रविवार को सामने आया कि प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और अलगाववादी इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआइपी) मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। इन संगठनों के प्रतिनिधियों की रविवार को हुई संयुक्त बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दोनों संगठनों के प्रत्याशी मैदान में हैं, वहां वह दोस्ताना मुकाबला लड़ेंगे और जिन क्षेत्रों में एक ही संगठन का प्रत्याशी है, वहां दूसरा उसका साथ देगा।

अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और बारामुला के सांसद इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे। उन्हें पिछले सप्ताह ही प्रचार के लिए अदालत ने जमानत प्रदान की थी। वहीं, जमात-ए-इस्लामी पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। माना जा रहा है कि यह गठजोड़ राजनीति में इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद की राजनीति को जड़ें जमाने का मौका देगा।

रामबन और किश्तवाड़ में आज तीन रैलियों में भाजपाइयों को शाह देंगे जीत का मंत्र

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

क्यों अहम है चिनाब क्षेत्र

चिनाब क्षेत्र सांप्रदायिक कारणों से भी संवेदनशील रहा है और दशकों से आतंक से प्रभावित भी। इस पर कांग्रेस और नेकां का भी प्रभाव रहा है, लेकिन आजाद के अलग होने से कांग्रेस को यहां नुकसान हो सकता है। कुछ बागी भी उनकी चिंता बढ़ा रहे हैं। भाजपा सत्ता की चाबी हाथ में लेने के लिए आठ में ज्यादातर सीटें अपने नाम करना चाहती है।

जम्मू संभाग के रामबन में सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह की होने वाली रैली प्रबंधों का जायजा लेते पूर्व विधायक नीलम लंगेहव अन्य। जागरण

चिनाब क्षेत्र का रण जीतने को भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डोडा में शनिवार को रैली में कार्यकर्ताओं में जोश भरा था, अब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शाह सोमवार को रामबन और किश्तवाड़ में तीन रैलियों में विपक्ष को घेरने के साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। वह किश्तवाड़ जिले के पाडर और उसके बाद किश्तवाड़ मैदान तथा शाम में रामबन में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। इस क्षेत्र के तीन जिले की सभी आठ सीटों पर भाजपा चुनाव मैदान में है और सभी सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनिहाल में सभा कर चुके हैं।

चिनाब क्षेत्र की इन सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है और सोमवार शाम को शाह की रामबन रैली के साथ प्रचार का शोर थम जाएगा। शाह इससे पूर्व जम्मू के नगरोटा में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। यह क्षेत्र भाजपा की रणनीति के अनुसार काफी अहम है और चिनाब क्षेत्र को जीतकर भाजपा सत्ता की कुंजी अपने हाथ में लेना चाहती है। इस सीट पर नेकां और कांग्रेस गठबंधन भी है और कुछ सीटों पर दोनों दल आमने-सामने भी हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान दोनों दलों के रिश्तों में आई खटास का फायदा भाजपा उठाना चाहेगी।

शाह किश्तवाड़ व रामबन की रैलियों में भी विरोधी दलों के आतंक, अलगाववाद को शह देने की नीतियों को निशाना बनाते हुए चिनाब क्षेत्र की खुशहाली व विकास के नाम पर लोगों से समर्थन मांगेंगे। इससे पहले वह 6 सितंबर को जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर आए थे।

भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने बताया कि पार्टी ने इन रैलियों को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की है। जम्मू-कश्मीर में लोगों के सहयोग से भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो जन कल्याण पर केंद्रित घोषणा पत्र पेश कर रही है। विरोधी दल लोगों को गुमराह करने वाले वादे कर प्रदेश को उथल-पुथल लाना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग बहकावे में न आते हुए गुमराह करने की राजनीति करने वाले दलों को कड़ा सबक सिखाएंगे।

जजपा ने की चार प्रत्याशियों की शिकायत

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : जननायक जनता पार्टी ने चार उम्मीदवारों की चुनाव आयोग से शिकायत की है। कहा कि हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रत्याशी बलराज कुंडू, सफीदों से कांग्रेस उम्मीदवार सुभाष गांगोली, समालखा से कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छौक्कर व समालखा से आजाद उम्मीदवार रविंद्र मछरौली ने समाज सेवा के बहाने आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश में हैं।

जजपा के कार्यालय सचिव रणधीर सिंह की ओर से केंद्रीय चुनाव आयोग में भेजी शिकायत में कहा गया कि मतदाताओं को फ्री बस सेवा का लालच देकर प्रभावित कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों तक मुफ्त बस सेवा का लालच मतदाताओं को दिया जा रहा। चारों उम्मीदवारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, जजपा ने कैथल के जिला उपायुक्त की भी शिकायत की है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिला परिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में डीसी द्वारा एजेंडे रखना भी आचार संहिता का उल्लंघन है।

रणनीति

हरियाणा चुनाव में पार्टी का फोकस किसान, जवान, महिला सुरक्षा और रोजगार पर, जाति जनगणना पर राहुल की मुखरता के बावजूद जम्मू-कश्मीर में भी यह प्रमुख मुद्दा नहीं

सामाजिक-सियासी मिजाज के अनुरूप चुनावी मुद्दे तय कर रही कांग्रेस

संजय मिश्र • जागरण

- हरियाणा में किसानों और कृषि के सवाल को पार्टी मान रही है बेहद अहम और संवेदनशील
- जम्मू-कश्मीर में भी रोजगार, सुरक्षा-शांति के साथ राज्य के दर्जे की बहाली पार्टी के प्रमुख मुद्दे

कांग्रेस का बदलता प्रचार ट्रैक।

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव-2024 में सामाजिक मुद्दों का प्रभाव देखते हुए कांग्रेस अब विधानसभा चुनावों में राज्यों के सामाजिक-राजनीतिक मिजाज के अनुरूप मुद्दों की प्राथमिकता तय कर रही है। आम चुनाव के समय से जाति जनगणना का मुद्दा सबसे आगे रखती आ रही कांग्रेस का हरियाणा चुनाव में मुख्य फोकस किसान, जवान, महिला सुरक्षा तथा युवाओं के रोजगार पर है और प्राथमिकता में जाति जनगणना इसके बाद ही दिख रही है। जम्मू-कश्मीर में भी रोजगार, सुरक्षा-शांति के साथ राज्य के दर्जे की बहाली पार्टी के प्रमुख मुद्दे हैं। जाति जनगणना का विमर्श यहां भी मुखर रूप में अब तक सामने नहीं आया है।

हरियाणा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का प्रचार अभियान अगले कुछ दिनों में शुरू होगा और संभावना है कि वह जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाएंगे। मगर राज्य में कांग्रेस जिन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है उसके मद्देनजर राहुल का फोकस भी उन्हीं मुद्दों पर रहने के संकेत हैं। पार्टी रणनीतिकारों की मानें तो किसानों व कृषि के सवाल हरियाणा के लिए बेहद अहम व संवेदनशील हैं और किसान आंदोलनों की मुख्य धुरी हरियाणा-पंजाब के किसान ही रहे हैं। इसी तरह सेना में भर्ती के लिए राज्य के युवाओं का परंपरागत जज्बा रहा है, इसीलिए पार्टी अग्निवीर योजना के बहाने राज्य के नौजवानों के आक्रोश को भुनाने का मौका देख रही है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी विमर्श को गहरे प्रभावित कर रहा है। पार्टी नेताओं का दावा है कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में घिरे कुश्ती फेडरशन के प्रमुख रहे भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह से जुड़े विवाद का हरियाणा के गांवों-खाप पंचायतों पर गहरा असर है। विशेषकर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उनसे हुई बदसलूकी लोगों की स्मृतियों से अभी गायब नहीं हुई है। महिला पहलवानों की इस लड़ाई का सबसे प्रमुख चेहरा रहीं पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारकर महिला सम्मान, अस्मिता और सुरक्षा को राज्य में जन विमर्श की धुरी बना दिया है।

बेरोजगारी के संकट से कोई राज्य अछूता नहीं है और इसीलिए नौजवानों व रोजगार के मुद्दे फिलहाल जाति जनगणना से ज्यादा प्रभावी रहेंगे। राहुल के मुखर होने के बावजूद हरियाणा में पार्टी के पहले तीन एजेंडे में जाति जनगणना का मुद्दा नहीं होने के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय के मीडिया-संचार के प्रभारी राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। किसानों की मुश्किलें, बेरोजगार नौजवानों की बेचैनी और महिलाओं की अस्मिता व सुरक्षा के सवाल इंतजार नहीं कर सकते। प्राथमिकता के हिसाब से इनका तत्काल समाधान अपरिहार्य है। जाति जनगणना कराना केंद्र का विषय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और पार्टी के रुख में किसी तरह के संदेह की गुंजाइश टटोलना मुनासिब नहीं होगा।

****

24 तक हरियाणा में मोर्चा संभाल लेंगे अर्धसैनिक बल

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- सीआरपीएफ की 25, बीएसएफ की 15, सीआइएसएफ की 30, आइटीबीपी की 25 कंपनियां पहुंचेंगी

जम्मू और कश्मीर में पहले व दूसरे चरण के चुनाव के बाद अर्धसैनिक बलों की 155 कंपनियां हरियाणा पहुंच जाएंगी। इनमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 25 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 15, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) की 30, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की 25, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 35 तथा रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की 25 कंपनियां शामिल हैं। यह सभी कंपनियां 24 सितंबर तक हरियाणा में मोर्चा संभाल लेंगी। पांच अक्टूबर को चुनाव होने के बाद ईवीएम, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 30 कंपनियां मतगणना पूरी होने तक तैनात रहेंगी, जबकि शेष 195 कंपनियां वापिस चली जाएँगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती पर गठित राज्य कमेटी के चेयरमैन पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग से 225 कंपनियों की मांग की गई थी। इनमें से 70 कंपनियां 25 अगस्त तक राज्य में पहुंच चुकी थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों का मुख्य कार्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान फ्लैग मार्च व एरिया डोमिनेशन द्वारा मतदाताओं में सुरक्षित माहौल का विश्वास पैदा करना है। मतदान केंद्रों के आसपास आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस, आइआरबी तथा होम गार्ड के जवानों की तैनाती रहेगी।

न्यूज गैलरी

महिला कांग्रेस ने शुरू किया आनलाइन सदस्यता अभियान

नई दिल्ली: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार से नारी वंदन अधिनियम को फौरन लागू करने की मांग की है। अपने स्थापना की 40वीं वर्षगांठ पर महिला कांग्रेस ने आनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संगठन के स्थापना दिवस पर हम अपनी वेबसाइट जारी कर रहे हैं। इसके जरिए देशव्यापी आनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। महिला कांग्रेस अपनी सदस्यों के लिए तीन दिनी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करेगी। (प्रेट्र)

'भारत में विवादों के हल के लिए मध्यस्थता को वरीयता'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि मध्यस्थता की वैकल्पिक विवाद समाधान की प्रणाली देश में विवादों पर समझौते के लिए वरीयता दी जाने वाली प्रणाली बनती जा रही है। भारत की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और विदेशी पंचायती प्रवर्तन की क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं रहा। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और नियमों पर हुए सम्मेलन में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह सम्मेलन 75 सालों के सुप्रीम कोर्ट के योगदान और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए) की 125वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है। आज भारत मध्यस्थता के नए युग की सीमा पर है। यह हमारे देश में नासिर्फ तेजी से वरीयता आधारित समझौते का तरीका बनता जा रहा है बल्कि इसके लिए बुनियादी समर्थन भी बढ़ रहा है। (प्रेट्र)

नीतीश कुमार करा रहे मेरी जासूसी : तेजस्वी

मधुबनी : बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी आभार यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे संवाद कार्यक्रम से घबराए हुए हैं। उनकी जासूसी कराई जा रही है। सीआइडी और स्पेशल ब्रांच के लोग सक्रिय हैं। वह रविवार को मधुबनी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि किस जिले में जासूसी करते सीआइडी और स्पेशल ब्रांच के लोग मिले तो बताया कि वैसे तो सभी जिलों के कार्यक्रम में जासूसी की जा रही है मगर दरभंगा में पार्टी की बैठक में दो लोग पकड़े गए थे। उन्होंने आइकार्ड दिखाया था। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा है। न तो विशेष राज्य का दर्जा मिला न ही विशेष पैकेज, जबकि केंद्र में बिहार के सात मंत्री हैं। (जासं)

सीबीआइ ने कोर्ट में कहा- वारदात के पीछे गहरी साजिश का अंदेशा

डाक्टरों का आंदोलन तेज, निकाली महारैली

डाक्टर से दरिंदगी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या की वारदात के पीछे सीबीआइ को गहरी साजिश देख रही है। केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को घटना में गिरफ्तार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डा. संदीप घोष व टाला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को सियालदह कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने दोनों को 17 सितंबर तक के लिए केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि थानेदार अभी तक मुख्य घटना में आरोपित नहीं है, लेकिन लगता है कि वारदात के पीछे कोई बड़ी साजिश है और थानेदार इसमें शामिल हैं। एजेंसी ने थानेदार द्वारा सुबूतों को नष्ट किए जाने की भी आशंका जताई। सीबीआइ ने दावा किया कि अस्पताल की घटना की पहली सूचना सुबह 10 बजे टाला थाने को मिली लेकिन थानेदार एक घंटे की देरी से 11 बजे मौके पर पहुंचे। रात 11:30 बजे के बाद एफआइआर दर्ज की गई। थानेदार ने उस दिन संदीप घोष से फोन पर बातचीत की थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि दोनों के बीच संबंध है।

सीबीआइ ने दावा किया कि पीड़िता की मां ने थानेदार से अपनी बेटी के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का अनुरोध किया था लेकिन थानेदार ने शव को जलाने में नियमों की अनदेखी कर जल्दबाजी की।

पुलिस आयुक्त से पूछताछ की तैयारी : सीबीआइ अब कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को तलब कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ के पास एक कालरिकार्ड है, जिसमें थानेदार ने पुलिस आयुक्त से बातचीत की है।

महिला चिकित्सक से दरिंदगी मामले में गिरफ्तार किए गए अभिजीत मंडल को रविवार को अदालत ले जाते सीबीआइ अधिकारी। एएनआइ

बंगाल के अस्पताल में फिर महिला से छेड़छाड़

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में फिर एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित स्वास्थ्यकर्मी को गिरफ्तार किया है। उसका नाम तनय पाल है, वह अस्पताल में वार्ड ब्वाय के रूप में काम करता है। महिला की शिकायत के अनुसार घटना शनिवार को उस समय हुई जब वह बाल स्वास्थ्य संस्थान के एक वार्ड में सो रही थी, जहां उसका बीमार बच्चा भर्ती था।

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

कोलकाता के आरजी कर कांड को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ शनिवार को दूसरी बार भी बैठक नहीं हो पाने के बाद जूनियर डाक्टरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। 'अनुरोध नहीं, मांग करेंगे' का नया नारा देते हुए रविवार को डाक्टरों ने महानगर में महारैली निकाली। दूसरी तरफ हड़ताल व स्वास्थ्य भवन के सामने धरना जारी रखने की भी घोषणा की। जूनियर डाक्टरों की महारैली में बड़ी संख्या में आम लोग भी बारिश में भींगते हुए इसका हिस्सा बने। रविवार को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी विरोध में जुलूस निकाला। इनमें सेवानिवृत्त मेजर, ब्रिगेडियर व कर्नल शामिल हुए। वह सभी पुरुलिया सैनिक स्कूल के पूर्व छात्र हैं। डाक्टरों के बाद नर्सें भी सड़क पर उतर गई हैं। कोलकाता के विभिन्न स्कूलों के पूर्व छात्र-छात्राओं की ओर से भी जुलूस निकाला गया।

आंदोलनकारी जूनियर डाक्टरों में मतभेद होने का दावा : तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने रविवार को दावा किया कि अस्पताल कांड को लेकर आंदोलन कर रहे जूनियर डाक्टरों में मतभेद हैं। उन्होंने इस बाबत अपने एक्स अकाउंट पर जूनियर डाक्टरों में आपसी चर्चा का एक आडियो पोस्ट किया है। इसमें कुछ जूनियर डाक्टर मुख्यमंत्री से बातचीत करने तो कुछ नहीं करने के पक्ष में बोल रहे हैं। जूनियर डाक्टरों का एक वर्ग हड़ताल खत्म करके काम पर लौटने के पक्ष में है जबकि दूसरा वर्ग चाहता है कि गतिरोध जारी रहे। 'दैनिक जागरण' ने आडियो की सत्यता की जांच नहीं की है। दूसरी तरफ जूनियर डाक्टरों ने इसे उनके आंदोलन को दबाने का हथकंडा बताया है। पूर्व प्रिंसिपल डा. संदीप घोष की गिरफ्तारी पर टीएमसी के बागी नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य डा. शांतनु सेन ने कहा कि भगवान ने न्याय किया है।

कोलकाता में महिला प्रशिक्षु के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के विरोध में रविवार को बारिश के बीच स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकालते चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी। प्रेट्र

'कोटे पर राहुल की टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता'

आरक्षण को लेकर धनखड़ ने नेहरू, इंदिरा और राजीव के रुख की भी आलोचना की

संविधान का पाकेट संस्करण प्रदर्शित करने के लिए भी राहुल पर साधा निशाना

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण पर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनको इस मुद्दे पर अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन विदेशी धरती पर की गई टिप्पणी उनकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस नेता पर अक्सर संविधान का पाकेट संस्करण प्रदर्शित करने के लिए भी निशाना साधा।

धनखड़ ने आरक्षण पर पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के रुख की भी आलोचना की। उनकी यह टिप्पणी रविवार को मुंबई के एलफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल और जूनियर कालेज में 'संविधान मंदिर' के उद्घाटन के अवसर पर आई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश में कहता है कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि बाबासाहेब आंबेडकर को भारतरत्न पहले क्यों नहीं दिया गया? बाबासाहेब की उपेक्षा की मानसिकता से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मंडल आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद अगले 10 वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उस दौरान देश में दो (कांग्रेसी) प्रधानमंत्री थे- इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मैं इस मानसिकता के बारे में दुख के साथ पंडित नेहरू को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी रूप में आरक्षण पसंद नहीं है। खास तौर पर नौकरियों में आरक्षण। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं, जो अकुशलता को बढ़ावा देता हो। धनखड़ ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण संविधान का अंतरात्मा है। आरक्षण हमारे संविधान में सकारात्मकता के साथ है।

धनखड़ ने कहा कि संविधान को किताब की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। संविधान को समझना चाहिए। संविधान को केवल एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना, उसका प्रदर्शन करना...कम से कम संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा। संविधान के तहत हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी शामिल हैं।

मुंबई स्थित एलफिंस्टन टेक्निकल हाई स्कूल में रविवार को संविधान मंदिर के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एएनआइ

क्या धनखड़ आरक्षण पर राहुल की मांग का समर्थन करते हैं : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस ने रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सवाल किया कि क्या वह एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ का एक पोस्ट टैग करते हुए पूछा, मैं संवैधानिक पद पर बैठे इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि वह किनका समर्थन करते हैं-उनका जो जातिवार जनगणना कराने से इन्कार कर रहे हैं या उनका जो जातिवार जनगणना और एससी, एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने का जोरदार समर्थन कर रहे हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी धनखड़ से पूछा है कि वह आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग का समर्थन करते हैं या नहीं?

देश के सबसे बड़े आतंकवादी राहुल : रवनीत सिंह बिट्टू

जागरण संवाददाता, भागलपुर: भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भागलपुर में रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताया। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वह राहुल गांधी हैं। आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर होना चाहिए। राहुल के समर्थन में आज देश को बांटने वाले, बम-गोला-बारूद वाले, ट्रेन में ब्लास्ट करने वाले खड़े हो रहे हैं। इनके पक्ष में बोल रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी कैसे हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं हैं। उनके दोस्त व रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। राहुल जब मुसलमानों को नहीं तोड़ सके तो अब सीमा पर खड़े सिखों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुमकिन नहीं है। उन्होंने एक बार तो यह तक कह दिया कि देश में सिख लोगों को कड़ा पहनने नहीं दिया जाता है। देशभर के सिखों से पूछ लीजिए कि क्या यह बात सही है! कोई सिख कह दे कि वह पगड़ी और कड़ा नहीं पहनता है तो वह राहुल की बात से सहमत होकर भाजपा छोड़ देंगे।

महाराष्ट्र में चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित : शिंदे

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को अगले आठ से 10 दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। शिंदे ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव बेहतर होगा। भाजपा, शिवसेना (शिंदे) और राकांपा (अजित पवार) की महायुति सरकार विकास और कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

शिंदे ने कहा कि उन्हें महिलाओं के बीच सरकार के लिए समर्थन दिख रहा है। हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। हमने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन बनाया है।

उन्होंने कहा कि कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नौकरियों के लिए 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का वजीफा मिलेगा। 10 लाख युवाओं को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य है। 'लाड़की बहिण योजना' के तहत अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है।

नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए आवंटित किए तीन लाख करोड़ रुपये

प्रथम पृष्ठ से आगे

मोदी सरकार ने इस वर्ष बजट में नारी शक्ति को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण-पत्र वितरित किया है। 2.35 लाख स्वयं सहायता समूहों की 26 लाख सदस्यों की मदद के लिए पांच हजार करोड़ का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया है। मुद्रा ऋण सीमा को दस से बढ़ाकर बीस लाख रुपये किया गया है। मध्यम वर्ग की चिंता साधने के लिए एकीकृत पेंशन योजना के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन की 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन, सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना में संशोधन जैसे कदम भी उठाए हैं।

घोषित अन्य प्रमुख योजनाएं

- महाराष्ट्र के वधावन में मेगा पोर्ट को मंजूरी। यह दुनिया के शीर्ष-10 पोर्ट में शामिल होगा।
- 25 हजार गांवों के लिए 62,500 किमी सड़कों व पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को स्वीकृति।
- लद्दाख से हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी।
- आठ नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी जिनसे 4.42 करोड़ मैन-डेज रोजगार पैदा होंगे।
- बंगाल के बागडोगरा व बिहार के बिहटा में नए सिविल एन्क्लेव को स्वीकृति प्रदान की।
- खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया जिससे 12 करोड़ किसान लाभान्वित।
- 14,200 करोड़ रुपये के खर्च से सात प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मौसम एवं जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी।
- टैक्स राहत- सात लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
- सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की।
- युवाओं में रोजगार व कौशल को बढ़ावा देने के लिए दो लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए।

मुस्लिमों ने वक्फ संशोधन बिल किया खारिज

जागरण संवाददाता, पटना सिटी

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के आह्वान पर इमारत-ए-शरिया का वक्फ संरक्षण सम्मेलन

बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक से हजारों की संख्या में पहुंचे मुस्लिम प्रतिनिधि

केंद्र द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल 2024 को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सचिव सह इमारत-ए-शरिया के अमीर-ए-शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे देशभर में कानून- व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वक्फ की संपत्ति को जब्त कर सरकार इसे पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। सरकार वक्फ को सशक्त और संपत्ति को संरक्षित करने के उद्देश्य के उलट गलत मंशा से काम कर रही है।

आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के प्रस्ताव पर इमारत-ए-शरिया द्वारा पटना स्थित बापू सभागार में रविवार को आयोजित वक्फ संरक्षण सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम शिष्टमंडल से इस बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में साथ न देने का जो वादा किया है, वह उसे निभाएं। जदयू के मुख्यमंत्री और तेलुगु देसम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू अपना हाथ खींच लें तो बिल का मसला ही समाप्त हो जाएगा। कहा कि किसान संशोधन बिल की तरह वक्फ संशोधन बिल भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से देशभर में इसके खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। अब तक पांच करोड़ मुसलमान मेल और क्यूआर कोड के माध्यम से अपना विरोध जता चुके हैं। सम्मेलन में बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक से शिया व सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा विभिन्न मुस्लिम संगठनों के हजारों प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इमारत शरिया द्वारा बापू सभागार में आयोजित वक्फ संरक्षण सम्मेलन को संबोधित करते अमीर-ए- शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी। जागरण

मोदी देश की पहली 'वंदे मेट्रो' ट्रेन को आज गुजरात में दिखाएंगे हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● गांधीनगर

ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट-एक्सपो का करेंगे उद्घाटन

गांधीनगर को मेट्रो का तोहफा, गिफ्ट सिटी जुड़ेगी मेट्रो रेल सेवा से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार को अपने गुजरात दौरे के दौरान भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली 'वंदे मेट्रो' ट्रेन के साथ-साथ कई अन्य वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ गांधीनगर में मेट्रो रेल सेवा का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के अन्य कार्यक्रमों में गांधीनगर में ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो 2024 का उद्घाटन और अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास शामिल है। वंदे भारत ट्रेनों का कोल्हापुर-पुणे, पुणे-हुबली, नागपुर-सिकंदराबाद, आगरा कैंट से बनारस और दुर्ग से विशाखापत्तनम समेत विभिन्न मार्गों पर संचालन किया जाएगा। भारत की पहली 20 कोचों वाली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी और दिल्ली के बीच चलेगी। पीएम मोदी गांधीनगर में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रथम चरण की मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण करेंगे। गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी को दूसरे चरण में मेट्रो रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। प्रथम चरण में गांधीनगर के आठ स्टेशन मेट्रो रेल सेवा से जुड़ेंगे। इनमें मेट्रो ट्रेन सचिवालय, अक्षरधाम, जीवराज मेहता भवन (पुराना सचिवालय), सेक्टर 16, सेक्टर 24 तथा महात्मा मंदिर स्टेशन शामिल होंगे। गांधीनगर में मेट्रो रेल के दूसरे चरण में अहमदाबाद व गांधीनगर के बीच स्थित गुजरात नेशनल ला यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, गुजरात इन्फो टेक सिटी, इन्फोसिटी तथा सेक्टर 1 को जोड़ा जाएगा। मोटेरा से मेट्रो ट्रेन सीधे गांधीनगर के आठ स्टेशनों से होकर चलेगी। प्रधानमंत्री का रविवार शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, 'झारखंड में यादगार कार्यक्रमों के बाद मैं अहमदाबाद पहुंचा। मैं 16 सितंबर को गांधीनगर और अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा।'

फैसला टला

कूनो में कल चीतों के पुनर्वास को दो वर्ष हो रहे हैं पूरे, केंद्रीय वन मंत्री ने चीता सफारी तैयार करने का प्रस्ताव बनाने का दिया था निर्देश

खुले जंगल में अभी नहीं छोड़े जाएंगे चीते

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर

मध्य प्रदेश में श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी शुरू करने की कोशिशों को फिलहाल झटका लगा है। चीते अभी खुले जंगल में नहीं छोड़े जाएंगे। इसकी बड़ी वजह हाल ही में हुई चीता पवन की मौत है। मुख्य वन संरक्षक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि कूनो प्रबंधन चीते की मौत को लेकर चिंतित है, इसलिए चीतों को खुले जंगल में छोड़ने का फैसला टाला गया है। उधर, भारत की धरती पर चीते लाने की दूसरी वर्षगांठ 17 सितंबर को मनाई जाएगी। चीता सफारी के लिए तैयार किए जा रहे सेसईपुरा में इस मौके पर कार्यक्रम होंगे।

बता दें कि नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए आठ चीतों के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जन्मतिथि पर चीतों को बाड़े में छोड़ा था। इसके दूसरे चरण में फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। कुल 20 चीतों में आठ वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। इनमें तीन मादा और पांच नर चीते थे। 17 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें 12 जीवित हैं। वर्तमान में सभी चीते बाड़ों में हैं। उधर, चीता सफारी बनाने की दिशा में काम शुरू है। पहली चीता सफारी सेसईपुरा में कूनो नदी के किनारे और दूसरी विजयपुर क्षेत्र में बनाई जाएगी।

केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो भ्रमण के दौरान सेसईपुरा में चीता सफारी तैयार करने का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर सेंट्रल जू अथारिटी आफ इंडिया के पास भेजा गया था।

खुले जंगल में विचरण का है इंतजार।

चीता प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मांगे 19.76 करोड़ रुपये

चीता प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के वन विभाग ने केंद्रीय पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 19 करोड़ 76 लाख 81 हजार रुपये की सहायता राशि मांगी है। इस राशि से कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। कूनो के बाद अब गांधी सागर में चीतों को बसाया जाना है। सरकार ने कूनो के लिए 10 करोड़ व गांधी सागर के लिए नौ करोड़ 76 लाख 81 हजार रुपये की मदद मांगी है।

****

बिहार के अरवल में दो वर्ष से सात अस्पताल लापता, योगदान के लिए ढूंढ़ रहे चिकित्सक

शिव मिश्रा ● जागरण

2019 में सरकार ने जिले में नौ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की दी थी स्वीकृति, तीन वर्षों में चालू करना था केंद्र

अरवल: बिहार के अरवल जिले में स्वास्थ्य विभाग का रोचक कारनामा सामने आया है। दो वर्ष से कागज पर संचालित सात अस्पताल जमीन पर ढूंढ़े नहीं मिल रहे। ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) जिले के शेरपुर, फखरपुर, खबैनी, इंजोर, बेलसार, बेलाव, रामपुर चाय, पिंजरावा और निधवा में स्थापित होने थे। इन लापता अस्पतालों में नियुक्त चिकित्सक योगदान देने के लिए गांव-गांव भवन ढूंढ़ रहे हैं। अस्पताल भवन नहीं मिलने पर नियुक्त किए गए चिकित्सकों ने थक हारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में योगदान किया है। 2019 में सरकार ने जिले में नौ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की स्वीकृति दी थी। केंद्र में छह बेड, लैब, रजिस्ट्रेशन काउंटर के साथ सातों दिन 24 घंटे चिकित्सकों को सेवा देनी थी। घोषणा के तीन वर्षों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों को चालू कर देना था। स्वास्थ्य विभाग ने पिंजरावा और निधवा में किराये के भवन में केंद्र संचालित कर दिया, शेष सात केंद्र दो वर्ष से कागज पर ही संचालित हैं।

हैरत यह कि इन सात लापता अस्पतालों के लिए तीन माह पहले आयुष चिकित्सक भी नियुक्त कर दिए गए। चिकित्सक जब संबंधित केंद्रों में योगदान देने पहुंचे, तब पता चला कि जमीन पर कोई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। इसके बाद चिकित्सकों ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर निकट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योगदान दिया। भवन के अभाव में इन सात केंद्रों को भी किसी अन्य सरकारी या किराये के भवन में संचालित किया जा सकता था। जिले में अभी भी एक दर्जन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराये के मकान में चल रहे हैं। किंतु जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इन सात केंद्रों के लिए ऐसी पहल नहीं की। वहीं इन केंद्रों पर इन्हीं मरीजों की सुविधा के लिए नियुक्त चिकित्सकों को हर माह लाखों रुपये वेतन मद में भुगतान किया जा रहा है।

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक सलीम जावेद ने कहा कि सभी सात जगहों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए सीओ को जमीन के लिए पत्र लिखा गया है। अगर जमीन नहीं मिलती है, तब किराये के भवन में केंद्र चालू किया जाएगा।

40 से ज्यादा लोगों के यूपी के बहराइच में भेड़िए घायल कर चुके हैं। साथ ही 10 लोगों को शिकार बना चुके हैं। वन विभाग अब तक चार भेड़ियों को पकड़ चुका है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 16 सितंबर, 2024

प्रयागराज और वाराणसी में बाढ़ के हालात

गंगा-यमुना चेतावनी बिंदु के पार, शहरी क्षेत्र में चल रहीं नावें

जागरण टीम, लखनऊ

लगातार बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण प्रदेश में नदियों ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गंगा और यमुना के चेतावनी बिंदु पार करने से प्रयागराज, वाराणसी व अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मार्गों पर पानी भरने से संपर्क कट गया है। फसलें डूब गई हैं। प्रशासन राहत सामग्री वितरण के साथ बाढ़ चौकियां खोलकर राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। अयोध्या, बलिया, आजमगढ़ व मऊ में सरयू भी खतरे के निशान पर बह रही हैं। बाढ़ ने कई गांवों को चपेट में ले लिया है।

दो प्रमुख नदियों गंगा व यमुना के संगम स्थल प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में नावें चलने लगी हैं। रविवार शाम गंगा का जलस्तर 83.92 तो यमुना का जलस्तर 83.78 मीटर पहुंच गया। दोनों का लाल निशान 84.73 मीटर है। हाई अलर्ट घोषित कर 60 से ज्यादा स्टीमर-मोटर बोट व 800 नावें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ-एसडीआरएफ, पीएसी बाढ़ राहत दल व जल पुलिस की एक कंपनी लगा दी गई है।

वाराणसी में गंगा चेतावनी बिंदु से 11 सेमी ऊपर 70.37 मीटर पर बह रही हैं। खतरा बिंदु 71.262 मीटर है। गंगा में उफान के बाद वरुणा में पलट प्रवाह से तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। दर्जनों परिवारों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सभी घाटों का संपर्क कट चुका है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती घाट किनारे बने भवनों की छत पर हो रही है। घाट की सीढ़ियां डूबने से शवदाह भी आसपास की गलियों में हो रहा है।

वाराणसी स्थित नमो घाट पर रविवार को भारी बारिश के चलते उफनती गंगा नदी में दृष्टिगोचर होती प्रणाम की मुद्रा में विशालकाय हाथ की प्रतिमा। एएनआइ

उत्तराखंड और हिमाचल में भारी वर्षा की चेतावनी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड में सोमवार को भी वर्षा से राहत की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि 17 से 19 सितंबर तीन दिन प्रदेशभर में भारी वर्षा की संभावना है। इस दौरान उधमसिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। हिमाचल में भी मौसम विभाग ने 18 से 21 सितंबर तक एक बार फिर से मानसून के अधिक सक्रिय होने और भारी वर्षा की संभावना व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

आदि कैलास में फंसे 46 यात्रियों और 19 ग्रामीणों को हेलीकाप्टर से पहुंचाया धारचूला

जागरण टीम, नई दिल्ली : उत्तर भारत में मानसून अपने चरम पर है। ऐसे में लगातार हो रही वर्षा के कारण उत्तराखंड में चीन सीमा से लगा तवाघाट-लिपुलेख हाईवे चौथे दिन भी बंद रहा। इस कारण ओम पर्वत व आदि कैलास दर्शन को गए 46 यात्रियों और 19 ग्रामीणों को हेलीकाप्टर से धारचूला लाया गया। मुनस्यारी के मिलम ट्रेक पर रलगाड़ी के पास भूस्खलन की चपेट में आकर मलबे में दबे कलेक्ट्रेट कर्मी का शव भी बरामद कर लिया गया है।

हिमाचल में बादल फटा, सेब बगीचों को नुकसान

हिमाचल के शिमला में शनिवार रात करीब 11 बजे बादल फटने के बाद शिकारी नाले में बाढ़ आ गई। इससे जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई बीघा सेब के बगीचों में मलबा घुसने से काफी नुकसान हुआ है। रात को जैसे ही लोगों ने आवाज सुनी तो सभी सुरक्षित स्थान की ओर भाग गए। मलबा मकान के पास तक पहुंच गया। वहीं, पर्यटन स्थल रोहतांग सहित बारालाचा व कुंजम दर्रे में हिमपात होने से ठंड बढ़ गई है।

केरल में निपाह वायरस संक्रमण से एक की मौत

मलप्पुरम, प्रेट्र: केरल के मलप्पुरम में एक प्राइवेट अस्पताल में 24 वर्षीय व्यक्ति की निपाह वायरस संक्रमण से मौत हो गई। यह इस साल राज्य में निपाह संक्रमण का पहला पुष्ट मामला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जार्ज ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मौत के कारणों की जांच करने पर निपाह संक्रमण का संदेह हुआ। मंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उपलब्ध नमूनों को तुरंत परीक्षण के लिए भेजा गया और परिणाम में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

बेंगलुरु से केरल पहुंचे मलप्पुरम निवासी की नौ सितंबर को मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके उपलब्ध नमूनों को कोझिकोड मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मेडिकल कालेज के नतीजों में संक्रमण पाया गया, जिसके बाद शनिवार रात को ही स्वास्थ्य मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और प्रोटोकाल के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। इस बीच, रविवार को पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के नतीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। शनिवार रात को ही 16 समितियां बनाई गईं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए 151 की सूची भी बनाई गई। व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर चुका था और उसके करीबी संपर्क में आए लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है।

असमानता व छुआछूत को रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आएं : भागवत

समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुम्ब प्रबोधन, स्व का भाव व अनुशासन को जीवन में उतारने का दिया मंत्र

अलवर स्थित मातृ वन में रविवार को 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण करते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। प्रेट्र

जागरण संवाददाता, जयपुर

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि हम अपने धर्म को भूलकर स्वार्थ के अधीन हो गए हैं, इसलिए समाज में छुआछूत चला, ऊंच-नीच का भाव बढ़ा। हमें इस भाव को पूरी तरह मिटा देना है। देश में समरसता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारत का नागरिक समझें। असमानता और छूआछूत को रोकने के लिए स्वयंसेवक आगे आएं। कहां पिछड़ रहे हैं, इस बारे में चर्चा की जरूरत है। गरीब के साथ जुड़ाव रखें। उन्हें घर लेकर आएं और उनके घर भी जाएं। गांव के गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। भागवत इन दिनों राजस्थान में अलवर जिले के प्रवास पर हैं। रविवार सुबह इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों से संवाद करने के साथ ही उन्होंने पौधारोपण भी किया।

उन्होंने स्वयंसेवकों से सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुम्ब प्रबोधन, स्व का भाव और नागरिक अनुशासन इन पांच विषयों को जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता के माध्यम से परिवर्तन लाना है। जहां संघ का काम प्रभावी है, वहां कम से कम मंदिर, पानी व श्मशान सभी हिंदुओं के लिए खुले हों। हमने प्रार्थना में ही कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र में अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है। जो लोग विरोध करते हैं, वे भी मानते हैं। उन्होंने कहा कि रण में जाए बिना भी देश सेवा की जा सकती है। अपने आसपास सफाई कर, समाज को उन्नतिशील बनाकर, चरित्र और शिक्षा को बेहतर कर देश सेवा हो सकती है।

न्यूज गैलरी

मुंबई-दोहा उड़ान में तकनीकी खराबी से यात्री परेशान

मुंबई : मुंबई से दोहा के लिए उड़ान भरने जा रहे विमान में सवार यात्रियों को रविवार को चार घंटे तक परेशान होना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। कुछ यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर उड़ान में देरी की शिकायत की। विमान रविवार सुबह उड़ान भरने वाला था। उतारे जाने से पहले चार घंटे तक यात्री विमान में बैठे रहे। सूत्रों ने बताया कि बाद में कहा गया कि यह विमान शाम 7:45 बजे रवाना होगा। (प्रेट्र)

लातूर में दंपती की हत्या के लिए दो को दोहरी उम्रकैद

लातूर : महाराष्ट्र के लातूर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने दंपती की हत्या के लिए दो लोगों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपने फैसले में निशांत और नितिन यादव को नौ नवंबर, 2014 को अशोक राउत और उनकी पत्नी अश्विनी यादव की हत्या करने का दोषी करार दिया। दोनों को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई। (प्रेट्र)

पीएम मोदी ने अभियंता दिवस पर इंजीनियरों को बधाई दी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अभियंता दिवस पर इंजीनियरों को बधाई देते हुए कहा कि वे हर क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं और महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि सर एम विश्वेश्वरैया का इंजीनियरिंग में योगदान सर्वविदित है। विश्वेश्वरैया की जयंती के रूप में अभियंता दिवस मनाया जाता है। पूर्ववर्ती मैसूर राजघराने के दीवान विश्वेश्वरैया को कई महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्यों का श्रेय दिया जाता है। (प्रेट्र)

केंद्रीय गृह सचिव ने अंडमान एवं निकोबार का दौरा किया

पोर्ट ब्लेयर : केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने रविवार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप का दौरा किया। गोविंद ने मुख्य सचिव केशव चंद्रा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 72000 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल समेत विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। शाम में केंद्रीय गृह सचिव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का दौरा किया। इस द्वीप पर वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित जापानी बंकर भी गए। (प्रेट्र)

माडल को तंग करने पर आंध्र के तीन आइपीएस निलंबित

- निलंबित आइपीएस में डीजीपी रैंक के अधिकारी अंजनेयुलु भी शामिल
- माडल को बिना उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तार करने का आरोप

अमरावती, प्रेट्र : आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें एक डीजी रैंक का अधिकारी हैं। सरकार ने आइपीएस अधिकारियों को निलंबित करने के लिए रविवार को अलग-अलग आदेश जारी किए।

इन अधिकारियों पर मुंबई की एक माडल को उसके खिलाफ दर्ज मामले में बिना उचित जांच जल्दबाजी में गिरफ्तार करने और परेशान करने का आरोप है। निलंबित अधिकारियों में पूर्व खुफिया प्रमुख पी. सीताराम अंजनेयुलु (डीजी रैंक), विजयवाड़ा के पूर्व पुलिस आयुक्त क्रांति राणा टाटा (आइजी रैंक) और तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (विजयवाड़ा) विशाल गुन्नी (एसपी रैंक) शामिल हैं।

माडल ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मुंबई में एक निगम के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला वापस नहीं लिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माडल को इस वर्ष की शुरुआत में पिछली सरकार के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। माडल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

रिकार्ड के अनुसार, माडल के खिलाफ एफआइआर दो फरवरी को दर्ज की गई थी, जबकि अंजनेयुलु ने 31 जनवरी को राणा टाटा और विशाल गुन्नी को उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। माडल ने हाल ही में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया तथा उसे परेशान किया गया। ये तीनों अधिकारी उन 16 आइपीएस अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें निर्देश दिया गया था कि वे बिना किसी पद के दिन में दो बार डीजीपी कार्यालय में हाजिरी दर्ज कराएं।

ई-कॉमर्स कंपनियों की त्योहारी सेल स्थगित करने का आग्रह

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की आगामी 'त्योहारी सेल' को स्थगित करने का आग्रह किया। खंडेलवाल ने कहा है कि इससे घरेलू व्यापारियों को नुकसान होगा। उन्होंने देश के छोटे खुदरा विक्रेताओं को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए ई-कामर्स नियमों और नीति को तुरंत लागू करने को भी कहा है।

मंत्री को लिखे पत्र में चांदनी चौक से लोकसभा सदस्य और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआइटी) के महासचिव खंडेलवाल ने उन मीडिया रिपोर्टों के बाद त्वरित कार्रवाई करने को कहा, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की रिपोर्ट में पाया गया था कि बड़े ब्रांड 'एंटी-ट्रस्ट' कानूनों का उल्लंघन करते हुए आनलाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ मिलीभगत कर रहे हैं।

कठुआ में पुलिस के जवानों पर गोलीबारी कर आतंकी जंगल में भागे

- सेना के कमांडो भी अभियान में उतरे, ड्रोन से जंगल को खंगाला जा रहा
- पहाड़ी क्षेत्र में छाए घने कोहरे का आतंकी उठा रहे हैं लाभ

जागरण संवाददाता, कठुआ

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में खलल डालने के लिए आतंकी बार-बार कोशिशें कर रहे हैं। कठुआ जिले के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र बनी में चार महीने बाद रविवार को एक बार फिर मुठभेड़ हुई। घने जंगलों में छिपे आतंकी रुक-रुक कर रहे गोलीबारी कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में छाए घने कोहरे का आतंकी लाभ उठा रहे हैं। सुरक्षाबल भी पूरे एहतियात के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। सेना की पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो को भी अभियान में उतारा गया है। बता दें कि 11 सितंबर को ऊधमपुर-कठुआ जिलों की सीमा से सटे बसंतगढ़ क्षेत्र में मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए थे।

पिछले दो सप्ताह से बनी से सटे बसंतगढ़ और डोडा क्षेत्र की पहाड़ियों में लगातार आतंकियों की गतिविधियां देखी जा रही थीं। रविवार को दोपहर करीब तीन बजे जैसे ही बनी में दो से तीन आतंकी देखे जाने की सूचना मिली, सुरक्षा बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस जवानों को देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। यह अभियान कठुआ से 150 किमी दूर बनी के दुर्गम क्षेत्र में चल रहा है। ड्रोन से भी आतंकियों के छिपने के ठिकाने का पता लगाया जा रहा है। जबकि अतिरिक्त सुरक्षाबलों को भी मौके पर भेजा है। कुछ दिन पहले जम्मू-सांबा-कठुआ रेंज के डीआइजी शिव कुमार शर्मा ने कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए थे। तब से पुलिस भी लगातार बनी क्षेत्र में गश्त कर रही है। यह वही क्षेत्र है जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह में छह आतंकी देखे गए थे, जो गुज्जर-बक्करवालों की भेड़ को मारकर खाने के बाद वहां से निकल गए थे। हाल के हमलों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि आतंकी सुरक्षाबलों के सामने आने से बच रहे हैं। अब वे छिपकर हमले कर रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों के हाथ में अत्याधुनिक हथियारों से मणिपुर पुलिस चिंतित

इंफाल, प्रेट्र : मणिपुर पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल पर रविवार को चिंता जताई। डीआइजी (रेंज 1) हीरोजीत सिंह ने कहा, प्रदर्शनकारी स्वचालित हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शनों के दौरान स्वचालित हथियारों से फायरिंग किए जाने का साक्ष्य है। खाबेइसोई में हाल ही में स्वचालित हथियारों से की गई गोलीबारी में इंफाल ईस्ट कमांडो के एक अधिकारी और एक अन्य कर्मी घायल हो गए। डीआइजी ने कहा, हम लोगों से अपनी मांगों के लिए लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हैं। पुलिस को निशाना बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को तुरंत बंद किया जाए। कानून- व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एएनआइ के अनुसार मणिपुर सरकार ने पांच जिलों में इंटरनेट निलंबन और मोबाइल डाटा सेवाओं को 20 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

सुकमा में नक्सलियों ने की शिक्षादूत की हत्या

दुधी अर्जुन। फाइल

नईदुनिया न्यूज, सुकमा : छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के गोंदपल्ली में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर गांव के स्कूल में पदस्थ शिक्षादूत दूधी अर्जुन की हत्या कर दी। मुखबिरी का आरोप लगाकर शिक्षादूत को लाठी से जमकर पीटा गया, फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई।

नक्सलियों के भय से मृतक के स्वजन ने इसकी सूचना तक पुलिस को नहीं दी। रविवार को युवक के अंतिम संस्कार की सूचना पुलिस को मिली। एसपी सुकमा किरण चव्हाण ने बताया कि अंदरुनी क्षेत्रों में सुरक्षा बल के कैंप खुलने से नक्सलियों का जनाधार खत्म हो रहा है। इस वर्ष सीधी मुठभेड़ में नक्सलियों को लगातार क्षति हुई है। इसी बौखलाहट में वे अब ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं।

तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने स्कूटर सवार दो युवतियों की ले ली जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

- टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर के हो गए दो टुकड़े

दीक्षा। स्वजन मां के साथ लक्ष्मी।

मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार रात तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार चालक ने स्कूटर सवार दो युवतियों की जान ले ली। खजराना थाना क्षेत्र में महालक्ष्मीनगर रोड पर बेकाबू कार ने गलत दिशा से स्कूटर को सामने से टक्कर मारी। इससे स्कूटर और सवार दोनों युवतियां करीब 20 फीट हवा में उछलीं। स्कूटर बिजली के खंभे से जा टकराया, जबकि एक युवती कार के बोनट से टकराकर करीब 75 फीट दूर जा गिरी। दूसरी लड़की सड़क की दूसरी तरफ गिरी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटर के दो टुकड़े हो गए। हादसे के बाद चालक कार खड़ी कर भाग गया।

उधर, हादसे के बाद लोग एक युवती को पहले बांबे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं होने के कारण वे उसे मेदांता लेकर पहुंचे। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस युवती की पहचान ग्वालियर के शिवनगर घोसीपुरा लश्कर निवासी दीक्षा के रूप में हुई। दूसरी युवती को धीरुभाई अंबानी कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, रविवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। उसकी पहचान शिवपुरी निवासी लक्ष्मी के रूप में हुई है।

पुलिस ने रविवार शाम ग्वालियर निवासी आरोपित कार चालक गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वह इंदौर की एक कंपनी में काम करता है। उसने आफिस के साथियों के साथ शराब पार्टी की थी और एक महिला मित्र के साथ एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था। दोस्त के घर जल्दी पहुंचने को उसने कार रांग साइड ले ली। रविवार दोपहर इंटरनेट मीडिया पर हादसे की खबर पढ़ी तो अपने स्थान पर किसी और को चालक दर्शाने का प्रयास किया, लेकिन इसके पहले ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान में एकादशी यात्रा पर पथराव में एक दर्जन लोग हिरासत में, दो मस्जिदों को नोटिस

जागरण संवाददाता, जयपुर

राजस्थान में शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को जलझूलनी एकादशी पर निकली यात्रा पर पथराव के बाद दूसरे दिन रविवार को तनावपूर्ण शांति रही। घटना के विरोध में जहाजपुर समेत आसपास के गांवों में बाजार बंद रहे। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने फिर यात्रा निकालने को लेकर अनुमति मांगी है। इस बीच, पुलिस ने पथराव करने के आरोप में एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने कस्बे की दो मस्जिदों को नोटिस देकर उनकी जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने को भी कहा है। जांच में पता चला है कि दोनों मस्जिदें अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कस्बे में पुलिस बल तैनात है।

बता दें कि जहाजपुर में एकादशी पर निकली यात्रा पर पथराव के बाद शनिवार को माहौल बेहद गर्म हो गया था। यात्रा जैसे ही बाजार पहुंची, एक स्थान पर कुछ लोगों ने आवाज लगाई कि रोको इसे और इसके बाद पथराव शुरू हो गया, जो करीब 20-25 मिनट तक चला। इसमें कई लोगों को चोटें आईं। इसके बाद बड़ी संख्या में एकत्रित भीड़ ने पथराव करने वाले दूसरे संप्रदाय के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रहा खतरनाक खेल : गिरिराज सिंह

जागरण संवाददाता, बेगूसराय

केंद्रीय मंत्री ने की अपील- एकत्रित होकर विरोध करें सनातनी

केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर खतरनाक खेल हो रहा है। लोग वक्फ बोर्ड को लेकर माइक लेकर गलियों में घूम रहे हैं और समाज में दुर्भावना व तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर भी वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलती है। वह रविवार को बेगूसराय में मीडिया से बात कर रहे थे।

गिरिराज ने कहा कि जब से बांग्लादेश में हिंदुओं से लूट, आगजनी आदि की घटनाएं हुई हैं, तब से कांग्रेस और टुकड़े-टुकड़े गैंग के नेताओं ने कहा है कि यही स्थिति भारत में होगी। हमारा एक ही आग्रह है कि देश के सनातनी एकत्रित होकर विरोध करें। हमने कभी भी उनके ताजिया पर पत्थर नहीं फेंका तो फिर हमारी पूजा पद्धति में अड़चन क्यों। भागलपुर में पकड़े गए मुस्लिम युवक ने जिस तरह से अयोध्या के राममंदिर को उड़ाने की बात कही है, ऐसी स्थिति में आज हमें फिर से पूर्वजों की गलतियों की याद आती है कि यदि नेहरू या और जो भी थे, वह मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिए होते तो हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती।

जागरण विशेष

जल वितरण व भूजल की बर्बादी रोकने में तकनीक बनेगी सहायक

अजय राय ● जागरण

प्रगति मैदान में आयोजित वाटर एक्सपो में सामने आए नवोन्मेष, उद्योगों में 99 प्रतिशत पानी का होगा उपयोग, बूंद-बूंद बचाना लक्ष्य

नई दिल्ली: जल की बर्बादी रोकने के साथ, जहां जरूरत है वहां आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तकनीक मददगार बन रही है। देश में कई जगह तकनीक की मदद से शहरों में नल से जल और गांवों में खेतों तक पानी की निगरानी के लिए बेहतर तंत्र विकसित किया है। सेंसरयुक्त तकनीक के माध्यम से जल वितरण आसान हुआ है। एक तकनीक ऐसी है, जिससे नदियों के जल की गुणवत्ता पर 24 घंटे नजर रखने के साथ यह पता लगाया जा सकता है कि कहां पानी सर्वाधिक प्रदूषित हो रहा है। प्रगति मैदान में संपन्न हुए वाटर एक्सपो में विभिन्न तकनीक को प्रदर्शित किया गया। इसमें तीन तकनीक ऐसी थी, जिनसे जल स्रोत, जल वितरण, सही उपयोग और उसकी गुणवत्ता पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।

प्रगति मैदान में हाल ही में आयोजित हुए वाटर एक्सपो में विभिन्न तकनीक को किया गया प्रदर्शित ● जागरण

पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण सिस्टम: घर-घर नल से जल वितरण को सुनिश्चित करने के साथ लीकेज का भी पता लगा सकते हैं। इस सेंसरयुक्त तकनीक से पानी के प्रेशर व फ्लो को एक ही जगह से कंट्रोल किया कर सकते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि किस पंप से कितना पानी और कितने फ्लो से कहां तक जा रहा है। इससे लो प्रेशर का भी निदान होगा। पंप को चालू या बंद किया जा सकता है। पंप में खराबी का भी तुरंत पता चलता है। क्षेत्र विशेष में लीकेज या चोरी का पता लगाने के लिए वहां घरों में लगे पानी के स्वचालित मीटर रीडिंग मशीन और क्षेत्र में कितना पानी सप्लाई किया जा रहा है, इसमें भारी अंतर होने पर सेंसर से पता लगाया जा सकता है कि कहां पानी की बर्बाद हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 52 प्रतिशत पानी लीकेज या चोरी में बर्बाद होता है। ऐसी स्थिति में यह तकनीक सहायक है। इसके साथ ही इस तकनीक के माध्यम शहर के सभी जलस्रोत जहां से पानी की सप्लाई की जा रही है, वो एकीकृत कमांड रूम से जुड़े होते हैं। इस तकनीक को उप्र स्थित प्रयागराज और फिरोजाबाद में लगाया गया है।

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम: उद्योग जितना भूजल दोहन करते हैं उसका 50 प्रतिशत ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी 50 प्रतिशत पानी शुद्ध करने के दौरान भाप बनकर उड़ जाता है। इससे जरूरत का दोगुना भूजल दोहन करना पड़ता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम से भूजल दोहन से निकले पानी का सिर्फ एक प्रतिशत हिस्सा बर्बाद होगा। नई तकनीक में पानी को शुद्ध करने के दौरान बायलर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे भाप को संग्रहित किया जाएगा। इसे कम तापमान पर वाष्पीकरण करने बाद पानी बना लिया जाता है और इसे दोबारा भूजल में डाल दिया जाएगा या किसी अन्य कार्य में उपयोग किया जा सकेगा। इससे 99 प्रतिशत पानी का उपयोग सुनिश्चित होता है। इसी क्रम में अगर पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो उसे शोधित भी किया जाता है। इसी तकनीक के आधार पर कूड़े के लीचेट (वह तरल पदार्थ है जो लैंडफिल से रिसता रहता है) से भी पानी निकाला जाता है और उससे स्टोर करके शौचालय में उपयोग करने लायक बना दिया जाता है।

नदी जल गुणवत्ता निगरानी सिस्टम

नदियों में लगातार नाला या औद्योगिक कचरा जाने से रोकने के लिए मल्टीपैरामीटर सोंडे सिस्टम तैयार किया गया है। इसमें छह सेंसर का इस्तेमाल होता है। इसे नदी के जिस हिस्से में डाला जाएगा वहां के करीब एक किमी के दायरे में नदी जल में कौन-कौन से पदार्थ हैं, उसका पता लगाया जा सकता है। इसमें घुलित आक्सीजन, फास्फेट, क्लोरीन, अमोनिकल नाइट्रेट, तेल या ग्रीस समेत 11 तरह की जानकारियां मिल सकती है, जिससे पता लगाने में आसानी होगी कि नदी सबसे अधिक किस क्षेत्र में किस पदार्थ के कारण प्रदूषित हो रही है।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

वक्फ बोर्ड को खुद अवैध निर्माण तोड़ने की अनुमति दे सकता है निगम

संजौली मस्जिद विवाद

- मस्जिद निर्माण कमेटी व वक्फ बोर्ड ने अवैध हिस्से को सील करने या तोड़ने की मांगी है अनुमति

जागरण संवाददाता, शिमला

शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी ने खुद ही सील करने या तोड़ने की अनुमति मांगी है। इस पर नगर निगम प्रशासन सोमवार को निर्णय ले सकता है। दूसरी ओर मंडी की जेल रोड मस्जिद में रविवार को भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लोक निर्माण विभाग की जमीन पर किए अतिक्रमण को हटाने का काम जारी रखा। इसके अलावा निगम प्रशासन ने संजौली समेत कई क्षेत्रों में अवैध तरीके से बैठे तहबाजारियों पर भी कार्रवाई की है।

संजौली में 2010 से मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। इस पांच मंजिला मस्जिद की तीन मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई हैं, जिन्हें हिंदू संगठन तोड़ने की मांग कर रहे हैं। मामला नगर निगम आयुक्त कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर पांच अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ उठी आवाज के बाद मस्जिद निर्माण कमेटी व वक्फ बोर्ड ने अवैध हिस्से को सील करने या स्वयं तोड़ने की अनुमति देने के लिए निगम आयुक्त को पत्र दिया गया था। उनकी मांग थी कि अवैध रूप से बने ढांचे को तोड़ने के साथ ही 1947 से पहले जो मस्जिद का ढांचा बना था, उसे वैधता दी जाए। निगम प्रशासन ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। मंडी की जेल रोड पर स्थित मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने का कार्य मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रविवार को तीसरे दिन भी जारी रखा।

****

ट्रायल में देरी विलंबित न्याय

कानूनी कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। हाल में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी को लेकर जांच एजेंसी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इस आधार पर जमानत दे दी कि 17 महीने बाद भी मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मामलों में ट्रायल में देरी के लिए सिर्फ जांच एजेंसियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं, जिनमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण वर्षों तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया और आरोपित जमानत पर घूमता रहा। कई मामले राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अदालती प्रक्रिया के बीच में ही दम तोड़ देते हैं। आखिर ट्रायल में देरी से किसको फायदा होता है, जांच एजेंसी को या फिर आरोपित को। यह बड़ा सवाल है कि आखिर न्याय मिलने में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? जांच एजेंसियों की कोताही, अदालतों में लंबा खिंचता ट्रायल या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी। इस इस बात की पड़ताल ही आज का मुद्दा है।

जांच की समय सीमा से बाहर की जाए स्टे की अवधि

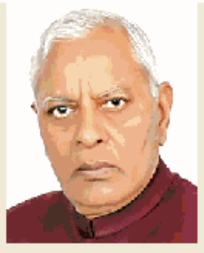

एसआर सिंह
पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि स्टे की अवधि को जांच की समय सीमा की अवधि में न गिना जाए। इस सिद्धांत को नए आपराधिक कानून, 2023 में लागू किया जा सकता है। इससे न्यायिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकता है।

नए आपराधिक कानून, 2023 का लक्ष्य तेजी से जांच पूरी करके एक तय समय सीमा में पीड़ित को न्याय दिलाना है। मामले का तेजी से ट्रायल का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। तेजी से ट्रायल का अधिकार भी इसी से जुड़ा हुआ है। नए आपराधिक कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों के निस्तारण को भी प्राथमिकता देते हैं। समस्या यह है कि नए कानून ऊपरी अदालतों द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश की वजह से ट्रायल में होने वाली देरी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं।

मेरी राय में इस समस्या के समाधान के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 (3) में मौजूद प्रविधान की तरह ही एक प्रविधान की जरूरत है। यह प्रविधान कहता है कि जब हाई कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा, स्टे या किसी अन्य साधन से एक पक्ष के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया जाता है तो वह पक्ष ऐसे आदेश को हटाने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है और अदालत को तय शर्तें पूरी होने पर दो सप्ताह के अंदर ऐसे आवेदन का निस्तारण करना चाहिए। मेरा यह भी मानना है कि यह न्याय के अनुरूप होगा कि मजिस्ट्रेट द्वारा अदालती कार्रवाई के योग्य समन के मामलों में केएम मैथ्यू बनाम केरल राज्य और अन्य, 1992 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा और कैलाश चौधरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 1993 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के तहत आरोपित को समन की वैधता के खिलाफ अपील का अधिकार होना चाहिए। दुर्भाग्य से अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल और अन्य, 2004 के मामले में इन फैसलों को खारिज कर दिया गया। मेरा यह भी मानना है कि अगर आखिरी लक्ष्य अदालतों के कानून के जरिये न्याय करना है तो मजिस्ट्रेट को भी कुछ निश्चित आधारों पर समन वापस लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। भारतीय न्यायपालिका ने ऐसे कई मामलों का निपटारा किया है, जिनमें स्टे आर्डर ने जांच को प्रभावित किया है। सीआरपीसी के तहत इसी तरह के मामले कुछ गाइडेंस मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र राज्य बनाम शरदचंद्र विनायक डोंगरे, 1955 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस अवधि में स्टे आर्डर प्रभावी था, उस अवधि को चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा में नहीं गिना जाना चाहिए। इस सिद्धांत को नए आपराधिक कानून, 2023 में इस सुझाव के साथ लागू किया जा सकता है कि स्टे की अवधि को जांच की तय समय सीमा से बाहर रखा जाए। कामन काज बनाम भारत संघ, 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तय समय सीमा में जांच और ट्रायल की जरूरत पर जोर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले के निस्तारण में ज्यादा देरी न्यायिक तंत्र के प्रभाव को कम करती है।

आपकी आवाज

वर्षों तक खिंचते मुकदमों और न्याय में देरी के लिए न्यायपालिका में कुछ कमियां जिम्मेदार हैं, जैसे कि किसी भी मुकदमे को टालने के लिए तारीख पर तारीख डालना। अगर न्यायालय में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि किसी भी मुकदमे की सुनवाई दो-तीन बार से ज्यादा नहीं होगी तो शायद न्याय में देरी न हो। खास कर प्रभावशाली लोगों के मामले में।

राजेश कुमार चौहान

दोषी छूट जाए पर निर्दोष को सजा न मिले। यह मंशा तभी पूरी हो सकती है जब मामलों को तारीख पर तारीख की बजाय फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए निपटाया जाए, जिससे ताकतवर आरोपित को पीड़ित पक्ष को डरा धमकाकर मामले को रफादफा करने का मौका न मिले। इससे गवाहों को प्रभावित करना आसान नहीं होगा। **अमृतलाल मारू रवि**

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की कुल संख्या लगभग 60,000 है। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या लगभग 42 लाख से अधिक है। जांच एजेंसियां और अन्य संस्थाओं का न्यायालय के साथ समन्वय नहीं बैठ पाता है। सही सबूत जुटाने में देरी होने न्याय की उम्मीद धूमिल हो जाती है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके न्याय में देरी से बचा जा सकता है। **सूर्यदीप कुशवाहा**

मिल कर काम करें जांच एजेंसियां और अदालतें

करनाल सिंह
इंडी के पूर्व निदेशक, सेवानिवृत आइपीएस

जांच एजेंसियों और अदालतों को कुशलतापूर्वक और सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। इससे निर्दोष को मुकदमे की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अपराधी व निहित स्वार्थ वाले लोग आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे।

हाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जमानत का निर्णय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है, किंतु अभी भी मुकदमा शुरू नही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी द्वारा अंतिम अभियोजन शिकायत या अंतिम आरोपपत्र दाखिल न किए जाने के कारण आरोपित जेल में ही रहता है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा शुरू नहीं हो पाता। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि इससे आरोपित के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसलिए उसे जमानत दे दी गई।

आम धारणा यह है कि खराब जांच के कारण अपराधी मामलों में बरी हो जाते हैं। यह समझना आवश्यक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में केवल जांच एजेंसी ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें अभियोजन पक्ष, सीएफएसएल जैसी वैज्ञानिक सहायता प्रणाली, बचाव पक्ष के वकील, अदालतें और जेल भी शामिल हैं। ये सभी एजेंसियां (जेल को छोड़कर) किसी न किसी तरह से न्याय में देरी में योगदान देती हैं। सबसे पहले, जांच एजेंसी में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण जांच अधिकारी पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे जांच में देरी होती है। खास तौर पर, थानों में तैनात पुलिस अधिकारी जांच करने के अलावा कानून-व्यवस्था प्रबंधन और इलाके में गश्त सहित कई अन्य काम भी करते हैं। जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करने की जरूरत है। दूसरा, फोरेंसिक रिपोर्ट, साइबर फोरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट आने में भी काफी समय लगता है, कभी-कभी दो से तीन साल तक लग जाते हैं। इन रिपोर्टों में देरी के कारण जांच को अंतिम रूप देने में देरी होती है। हमें निश्चित रूप से और अधिक प्रयोगशालाओं की जरूरत है। तीसरा, सीमा पार जांच में बहुत समय लगता है। ऐसे मामलों में, लेटर रोगेटरी की प्रक्रिया के जरिए विदेशी देश से सबूत हासिल किए जाते हैं। हालांकि, कई बार जवाब तीन से चार साल के अंतराल के बाद मिलता है। इसके बाद, हम न्यायपालिका और बचाव पक्ष के वकीलों की भूमिका के बारे मे विश्लेषण करते हैं। एक, विभिन्न अदालतों में 3.45 करोड़ (लगभग) आपराधिक मामले लंबित हैं। 16,694 जिला न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 5,300 न्यायाधीशों की कमी है। न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबी तारीखें लगती हैं और इस तरह मुकदमों में देरी होती है। दूसरा, वकीलों द्वारा बार-बार स्थगन मांगे जाने से न केवल मुकदमों मे देरी होती है, बल्कि कई मामलों में यह खूंखार अपराधियों के लिए वरदान साबित होता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग गवाहों को धमकाने में किया जाता है, जिससे उनका समझौता हो जाता है और आरोपी बरी हो जाता है। तीसरा, समन प्रक्रिया सेवा प्रणाली धीमी है और अधिकांश बार गवाहों को अंतिम समय पर समन प्राप्त होता है, उस समय तक वे उस शहर में नहीं होते हैं, जहां उन्हें गवाही देनी होती है। चौथा, अदालतें कभी-कभी चल रही जांच के दौरान हस्तक्षेप करती हैं और स्थगन आदेश जारी करती हैं, जो अस्थाई रूप से जांच कार्यवाही को रोक देती हैं। आरोपी पक्षों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले ये हस्तक्षेप वर्षों तक खिंच सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट को संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने में समय लगता है। नतीजतन, जांच एजेंसियों को अदालतों द्वारा स्थगन हटाने तक इंतजार करना पड़ता है।

उदाहरण के लिए बीकानेर जमीन मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में महेश नागर नामक व्यक्ति ने 2019-20 में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उसकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और परिणामस्वरूप मामले की जांच रुक गई। इसी तरह 2जी मामले में सीबीआइ और ईडी ने 2017-18 में सत्र न्यायालय के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी जो अभी तक लंबित है। आपराधिक न्याय प्रणाली को कुशलतापूर्वक और सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए ताकि निर्दोष को मुश्किलों का सामना न करना पड़े और अपराधी या निहित स्वार्थ वाले लोग अपने लाभ के लिए प्रणाली का दुरुपयोग न कर सकें।

वर्षों तक ट्रायल का इंतजार करते मामले

आइये अदालतों में लंबित ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं, जिनमें वर्षों बीत जाने के बावजूद अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

नेशनल हेराल्ड मामला

2012 में सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा अदालत में दाखिल केस में ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 2015 से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपितों को निजी तौर पर अदालत में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने से छूट दे रखी है। ईडी ने मनी लांड्रिंग मामले में 2023 में नेशनल हेराल्ड की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली थी।

2जी घोटाला

2009 में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की। 2011 में आरोपपत्र दाखिल। 2017 में सभी आरोपित बरी। सीबीआइ और ईडी दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की। छह साल के इंतजार के बाद हाई कोर्ट ने 2024 में कहा कि ईडी और सीबीआइ की अपील सुनवाई योग्य है। अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है।

बीकानेर जमीन घोटाला

2016 में बीकानेर जमीन घोटाले में स्थानीय पुलिस की एफआइआर के बाद ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया। 2019 में राबर्ट वाड्रा और उनकी माता से ईडी की पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपित महेश नागर ने राजस्थान हाई कोर्ट में ईडी की जांच रोकने की याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने ईडी पर आरोपितों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी। 2022 में हाई कोर्ट ने ईडी की जांच रोकने से इन्कार कर दिया, लेकिन राबर्ट वाड्रा समेत अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है।

आइआरसीटीसी घोटाले में लंबे समय तक लटका रहा ट्रायल

2016 में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की और 2018 में लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन रेल मंत्रालय के तीन आरोपित अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में तकनीकी आधार पर चार्जशीट को चुनौती दी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर चार्जशीट का संज्ञान लेने पर रोक लगा दी। पांच साल बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सीबीआइ की चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू करने की इजाजत दी, तब जाकर ट्रायल शुरू हो सका।

ऐसे भी खत्म हो जाते हैं केस: कई चर्चित मामलों में जांच एजेंसियों ने एफआइआर दर्ज करके जांच शुरू की लेकिन अदालतों में यह मामले टिक नहीं पाए।

लालू यादव के खिलाफ मामला

1998 में सीबीआइ ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया और 2000 में चार्जशीट दाखिल की। 2006 में लालू यादव को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। तत्कालीन संप्रग सरकार में रेल मंत्री के रूप में शामिल लालू यादव के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की इजाजत नहीं मिली। हालांकि बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन सीबीआइ लालू यादव के बचाव में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपील का अधिकार सिर्फ जांच एजेंसी का बताते हुए बिहार सरकार की हाई कोर्ट में अपील को खारिज कर दिया। वैसे 2020 में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य बेंच ने स्वीकार किया कि 2010 के फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है।

झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड

1993 में पैसे लेकर नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के मामले में 1996 में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की। सीबीआइ ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ 1997 में चार्जशीट दाखिल कर दी। ट्रायल कोर्ट ने उसका संज्ञान भी ले लिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने को सही ठहराया। लेकिन 1998 सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने संसदीय विशेषाधिकार का हवाला देकर आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया। वैसे 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का अहसास हुआ और 2024 में नई संविधान पीठ ने पुराने फैसले को पलट दिया। लेकिन इससे जेएमएम घूसकांड को संजीवनी नहीं मिल सकी। इस बीच घोटाले के एक मुख्य आरोपित कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली केंद्र में कानून मंत्री भी बने और प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी।

बोफोर्स घोटाला

1986 में हुए बोफोर्स घोटाले में 1996 में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की और 1999 में चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में राजीव गांधी और 2005 में हिंदुजा बंधुओं को केस से बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआइ ने 2009 में क्वात्रोची के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई और 2011 में इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन राजीव गांधी और हिंदुजा बंधुओं को बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआइ ने 12 वर्ष तक अपील नहीं की। 2017 में सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन इतने लंबे समय बाद दाखिल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

आइएएस टापर ललित वर्मा फर्जी जन्मतिथि मामला

1984 बैच के आइएएस टापर ललित वर्मा पर आइएएस बनने के बाद यूपीएससी में जाकर अपने दस्तावेजों में जन्म की तारीख बदलने का आरोप था। सीबीआइ ने इस मामले में जांच कर ललित वर्मा के खिलाफ 2006 में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया। लेकिन ललित वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सीबीआइ की चार्जशीट को ही निरस्त करा लिया, जबकि दिल्ली का तीस हजारी कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता ही नहीं है। सीबीआइ ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहा, लेकिन तत्कालीन सरकार से अनुमति नहीं मिली। इस मामले में ललित वर्मा का बच निकलना सिस्टम के लिए केस स्टडी का विषय हो सकता है।

ताज कारिडोर घोटाले में एफआइआर को अवैध बताया गया

2003 में ताज कारिडोर घोटाले में सीबीआइ ने एफआइआर दर्ज की। सीबीआइ ने 2007 में आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तत्कालीन राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने सीबीआइ को मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। ताज कारिडोर घोटाले के दौरान ही सीबीआइ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट को लगातार इसकी जांच की प्रगति रिपोर्ट देती रही। लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की एफआइआर को अवैध करार दे दिया।

भूषण स्टील बैंक धोखाधड़ी केस

2019 में बैंकों से 56 हजार करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में सीबीआइ और ईडी ने केस दर्ज किया। अदालती पेंच में फंसकर चार वर्ष तक जांच रुकी रही। 2023 में ईडी ने भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल और 2024 में कंपनी के पांच अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए नीरज सिंघल को जमानत दे दी।

राष्ट्रीय फलक

मप्र में अब जातियों के आधार पर नहीं बनेगी अपराधियों की हिस्ट्रीशीट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया ● भोपाल

सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए फैसले का शासन ने लिया संज्ञान

मध्य प्रदेश सचिवालय। फाइल

मप्र में अब जाति के आधार पर अपराधियों की हिस्ट्रीशीट नहीं बनाई जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक आपराधिक अपील अमानतुल्लाह विरुद्ध पुलिस आयुक्त दिल्ली एवं अन्य में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करने में बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में गत दिनों आदेश पारित किया है। इसी के तहत यह कदम उठाया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि अपराधियों की हिस्ट्रीशीट तैयार करते समय ध्यान रखा जाए कि पिछड़े समुदायों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अलावा आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम केवल इस कारण से दर्ज न हो कि वे उस जाति, जनजाति या समाज के हैं। यह उनके आत्म सम्मान के साथ जीने के अधिकार को बाधित कर सकता है। परिपत्र के अनुसार, हिस्ट्रीशीट तैयार करते समय अपराधी के नाबालिग रिश्तेदार अथवा उसके पुत्र, पुत्री, भाई, बहन का कोई विवरण तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक इस बात का साक्ष्य न हो कि संबंधित नाबालिग द्वारा अपराधी को आश्रय दिया गया है या दे सकता है, जब वह पुलिस से भाग रहा था।

अपराधी से जुड़े व्यक्तियों का पुलिस रखेगी रिकार्ड : अपराधी की हिस्ट्रीशीट में उससे जुड़े व्यक्तियों की विशेष प्रकृति के संबंध में नोट कर टिप्पणी लिखी जाएगी। उनके फोन नंबर, ई-मेल आइडी, इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जानकारी भी रिकार्ड में रखी जाए। हिस्ट्रीशीट की समय-समय पर पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाएगी। बाद में ऐसे व्यक्तियों, किशोर, बच्चों के नाम हिस्ट्रीशीट से हटाया जाएंगे जो जांच में निर्दोष पाए गए हैं।

सजा में छूट पाने के लिए अदालत में गलत बयानी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

कहा, ऐसे मामलों से रूबरू होने पर डगमगा जाता है विश्वास

अदालत सुनवाई के दौरान बार के सदस्यों पर करती है भरोसा

सुप्रीम कोर्ट फाइल

नई दिल्ली, प्रेट्र: दोषियों की समयपूर्व रिहाई हासिल करने के लिए वकीलों द्वारा अदालत व याचिकाओं में बार-बार गलत बयानी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब-जब वह ऐसे मामलों से दो-चार होती है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ हालिया आदेश में अपनी चिंता दर्ज की और कहा, 'इस अदालत में बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं जिनमें सजा में स्थायी छूट (रेमिशन) नहीं प्रदान करने के बारे में शिकायत की गई है। पिछले तीन हफ्तों में यह छठा या सातवां मामला है जिसमें हमें पता चला है कि याचिकाओं में झूठे बयान दिए गए हैं।' हाल में अपलोड 10 सितंबर के आदेश में शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मिसलेनियस-डे में हर पीठ के समक्ष 60 से 80 मामले होते हैं और जजों के लिए हर सूचीबद्ध मामले के प्रत्येक पृष्ठ को देख पाना संभव नहीं होता, यद्यपि इसका प्रयास किया जाता है। हमारी व्यवस्था विश्वास पर काम करती है। जब हम मामलों को सुनते हैं तो बार के सदस्यों पर भरोसा करते हैं।

ऐसे ही एक मामले में पीठ ने कहा कि सजा में छूट के लिए दाखिल रिट याचिका में न सिर्फ झूठे बयान दिए गए, बल्कि इस अदालत के समक्ष भी झूठा बयान दिया गया जो 19 जुलाई, 2024 के आदेश में दर्ज है। याचिकाकर्ताओं के तत्कालीन वकील द्वारा जेल अधिकारियों को 15 जुलाई, 2024 को भेजे गए ई-मेल में भी झूठे बयान दोहराए गए। पीठ ने कहा, ''जुर्माना लगाने का यह उपयुक्त मामला है, लेकिन हम याचिकाकर्ताओं को उनके वकीलों की गई गलतियों के लिए दंडित नहीं कर सकते।''

शीर्ष अदालत ने एक मामले पर कहा कि रिट याचिका में कहा गया कि सभी चार याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी छूट के 14 वर्ष की सजा काट ली है। जबकि दिल्ली सरकार ने हलफनामे में बताया कि चार में से दो कैदियों ने छूट पाने के लिए आवश्यक 14 वर्ष की सजा पूरी नहीं की है। इस प्रकार रिट याचिका में गलत बयानी की गई। याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग मामलों में अलग-अलग अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। पीठ ने दिल्ली सरकार को चार याचिकाकर्ताओं में से एक के सजा में छूट के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसने वर्तमान नीति के अनुसार 14 वर्ष जेल में काट लिए हैं, जबकि दो अन्य को राहत देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष की सजा पूरी नहीं की है। चौथे दोषी को राज्य सरकार ने छूट देने से इन्कार कर दिया था, उसके संबंध में पीठ ने कहा कि उसे निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती देनी होगी।

अमेरिका से पांच वर्ष पहले ही क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा भारत

जागरण संवाददाता, लखनऊ

भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक व पद्म भूषण डा. विजय पांडुरंग भातकर लखनऊ में दी जानकारी

राजभवन में शनिवार को पत्रकारों से बात करते डा. विजय पांडुरंग भातकर। जागरण

एक समय था, जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलाजी देने से इन्कार कर दिया था, लेकिन देश ने स्वदेशी तकनीक से न केवल सुपर कंप्यूटर 'परम' बनाया बल्कि अब क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दहलीज पर है। देश में सुपर कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर विज्ञानी एवं पद्म भूषण डा. विजय पांडुरंग भातकर ने कहा कि पांच वर्ष में क्वांटम कंप्यूटर बनाकर भारत सबको पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि दुनिया में अभी इसके प्रोटोटाइप पर ही काम चल रहा है। यह मौजूदा कंप्यूटर से कई हजार गुना शक्तिशाली होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने आए डा. पांडुरंग ने रविवार को राजभवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी।

डा. पांडुरंग ने पिछले दिनों को याद करते हुए कहा कि अमेरिका ने जब टेक्नोलाजी देने से मना किया तो भारत निराश नहीं हुआ। अमेरिका ने कुछ शर्तों पर पिछली जेनरेशन की टेक्नोलाजी देने पर सहमति दी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। इसके बाद सुपर कंप्यूटर बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। उस समय अमेरिकी सुपर कंप्यूटर की कीमत 37 करोड़ रुपये थी। इतनी कीमत में तो भारत ने स्वदेशी तकनीक से 100 विज्ञानियों की टीम के साथ एक नया सेंटर और सुपर कंप्यूटर परम दोनों तैयार कर लिए। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने क्वांटम तकनीक को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम मिशन की शुरुआत की है। मैं इस समय क्वांटम कंप्यूटर के सूक्ष्म पार्टिकल तैयार कर रहा हूं। इसके बनने के बाद हम मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकेंगे।

दैनिक जागरण

उदारता से ही व्यक्तित्व विराट बनता है

चौंकाने वाला निर्णय

अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए चर्चित दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर एक बार फिर चौंकाया कि वह दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे देंगे। उन्होंने जिस तरह यह स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उससे यह स्पष्ट है कि अगले दो दिन तक अटकलबाजी का दौर चलता रहेगा और इससे देश भर में केजरीवाल और दिल्ली की चर्चा होती रहेगी। यह स्पष्ट ही है कि केजरीवाल यह चाह रहे होंगे कि वह चर्चा के केंद्र में बने रहें। उन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया कि वह आम जनता के समक्ष अग्निपरीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि त्यागपत्र के मूल कारण कुछ और ही हैं। पहला कारण तो यही दिखता है कि आबकारी नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन उन पर कई कठोर शर्तें लगा दीं। इन शर्तों के कारण मुख्यमंत्री के रूप में उनके लिए कार्य करना असंभव सा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोका, बल्कि उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करने से भी रोक दिया। इतना ही नहीं, यह भी शर्त लगाई कि वह आबकारी नीति घोटाले पर कुछ नहीं कह सकते।

हैरानी नहीं कि केजरीवाल ने यह पाया हो कि उनके पास त्यागपत्र देने के अलावा और कुछ उपाय नहीं, लेकिन यदि उन्हें राजनीतिक शुचिता और नैतिकता की परवाह होती तो उन्हें तभी त्यागपत्र दे देना चाहिए था जब आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने की जिद पकड़ी। इस दौरान वह और उनके साथी भले ही यह कहते रहे हों कि नई आबकारी नीति लाकर कहीं कोई अनियमितता नहीं की गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं कि अगर इस नीति में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी तो उसे वापस क्यों लिया गया। यह ठीक है कि इस घोटाले में अन्य अनेक लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है, लेकिन जमानत क्लीन चिट का पर्याय नहीं हो सकती। भले ही केजरीवाल कह रहे हों कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और वह जनता से ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेने के बाद मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन आबकारी घोटाले का सच-झूठ जनता को नहीं, देश की अदालतों को तय करना है। केजरीवाल के त्यागपत्र देने का एक कारण यह भी दिखता है कि वह हरियाणा और फिर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता की सहानुभूति पाना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली के चुनाव करीब तीन माह पहले नवंबर में कराने की मांग भी की है। यह समय ही बताएगा कि उन्हें सहानुभूति का लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलती है या नहीं, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में जिस तरह कई बार अपने ही कहे को नकारकर फैसले लिए हैं, उससे उनकी वह छवि नहीं रह गई जो पहले थी।

डिजिटल मिशन से लाभ

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना से राज्य के अधिसंख्य निजी अस्पताल अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। झारखंड इस मामले में अन्य कई राज्यों से पीछे है। हालांकि देर से ही सही, स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र की इस योजना से निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों को न सिर्फ अवगत कराया है, बल्कि उन्हें इस योजना से जुड़ने तथा इसका लाभ उठाने की अपील भी की है। कई मामलों में देखा गया है कि जानकारी के अभाव में स्वास्थ्य प्रदाता के साथ-साथ मरीज भी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। योजना के तहत सभी निजी अस्पतालों में शत-प्रतिशत हेल्थ प्रोफेशनल्स तथा स्वास्थ्य सेवाओं का पंजीकरण कराने पर प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान किया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों के अलावा क्लिनिक, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक लैब आदि को प्रति माह आनलाइन एक हजार रुपये के डिजिटल लेनदेन पर प्रति हजार 20 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ अस्पतालों को ही मिलेगा, बल्कि मरीज भी इससे लाभान्वित होंगे। अस्पतालों में पंजीकरण से लेकर चिकित्सकों से परामर्श तक की प्रक्रिया डिजिटल होने से जहां मरीजों को लाभ होगा, वहीं अस्पतालों पर अनावश्यक बोझ भी घटेगा। ऐसे में तय है कि इस योजना के सही क्रियान्वयन से स्वास्थ्य सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। यह सुलभ साक्ष्य आधारित तथा उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में मदद करेगा। अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के आपसी समन्वय से यह योजना मूर्त रूप लेगी।

सहमति की राह पर सरकार

ए. सूर्यप्रकाश

मोदी सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगा रहे लोग भूल जाते हैं कि पूर्व में पूर्ण बहुमत के बावजूद पीएम मोदी ने कई नीतिगत मुद्दों पर अपने कदम पीछे खींचे

अवधेश राजपूत

कड़े फैसलों के लिए खास पहचान बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कार्यशैली तीसरे कार्यकाल में कुछ बदली हुई लग रही है। प्रतीत होता है कि वह स्वयं को नई राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में पहली बार गठबंधन सरकार चला रहे पीएम मोदी की सरकार पर मौजूदा कार्यकाल में कई मुद्दों को लेकर पलटी मारने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे आरोप लगाने वाले लोग संभवतः इस तथ्य को अनदेखा कर रहे हैं कि दो बार पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार चलाने के दौरान भी मोदी कई फैसलों को वापस ले चुके हैं। विपक्षी नेताओं को शायद यह अपेक्षा नहीं थी कि मोदी गठबंधन के समीकरणों को समझते हुए अपनी शैली में बदलाव करेंगे, लेकिन इस मामले में भी मोदी उन्हें गलत साबित कर चुके हैं कि वह गठजोड़ की राजनीति में आमसहमति के साथ आगे बढ़ने में सक्षम हैं। हालिया घटनाक्रम यही संकेत करता है कि सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। अगस्त की शुरुआत में सरकार ने प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024 वापस लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस विधेयक के प्रारूप पर जनता से प्रतिक्रियाएं मंगाई हैं। उसके बाद सरकार ने सिविल सेवा में विशेषज्ञों की भर्ती से जुड़ा लेटरल एंट्री का कदम पीछे खींचा। लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसके विरोध में कहा कि आरक्षण के प्रविधान के बिना ऐसा कोई भी कदम स्वीकार्य नहीं होगा। जदयू नेताओं ने भी चिराग के सुर में सुर मिलाए। परिणामस्वरूप, संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री से जुड़ी अधिसूचना रद कर दी। ऐसा करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसी नियुक्तियों के मामले में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए। स्पष्ट रूप से उनका संकेत आरक्षण के प्रविधान को लेकर था।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर भी सरकार को सहयोगियों के साथ ही यदाकदा समर्थन करने वाले मित्र दलों की आपत्तियों के चलते कदम पीछे खींचने पड़े। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड के ढांचे को और व्यापक बनाते हुए उनमें महिलाओं, बोहरा और आगाखानी के अलावा मुस्लिम समुदाय के अन्य पिछड़ा वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की पहल की गई है। साथ ही, बोहरा और आगाखानियों जैसे इस्लामिक वर्गों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड स्थापित करने की भी बात है। हालांकि, सहयोगी दलों ने इस विधेयक का पूरी तरह विरोध नहीं किया, लेकिन उसे संसदीय समिति को भेजने का सुझाव जरूर दिया। इस मामले में तेलुगु देसम, जन सेना और लोजपा जैसी पार्टियों ने व्यापक चर्चा को प्राथमिकता दी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। चूंकि संसद में विपक्षी दलों द्वारा इस विधेयक की राह में अवरोध खड़े करना तय था तो सरकार ने विधेयक के परीक्षण के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया।

इन मामलों को देखते हुए मोदी सरकार पर पलटी मारने का आरोप लगा रहे लोग भूल जाते हैं कि संसद में दमदार बहुमत के बावजूद उन्होंने कई मुद्दों पर अपने कदम पीछे खींचे हैं। गठबंधन राजनीति के इस दौर में उन उदाहरणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता जब पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार कुछ विरोधी स्वरों के बीच भी झुक गई थी। अपने रुख से पीछे हटने की सबसे बड़ी मिसाल तीन कृषि सुधार कानूनों की वापसी थी, जिन कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लंबे समय तक किसानों की घेराबंदी रही। समय-समय पर उस आंदोलन के हिंसक होने के बावजूद सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। जबकि भाजपानीत राजग के पास तब लोकसभा में 350 से अधिक सांसदों का समर्थन था। वर्ष 2015 में भूमि अधिग्रहण कानून को भी वापस ले लिया गया, जिसके लिए लगातार अध्यादेश का सहारा लिया जा रहा था। कारोबारी सुगमता के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान बनाने की मंशा से उठाए गए इस कदम का विपक्षी दलों और किसान संगठनों की ओर से भारी विरोध हुआ। उक्त कानून लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। अंत में, मोदी को घोषणा करनी पड़ी कि इस अध्यादेश को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।

कदम वापसी की इस सूची में एक नाम अगस्त 2022 में डाटा प्रोटेक्शन बिल से जुड़ा है, जो कई साल पहले प्रस्तावित किया गया था। सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति के सुझावों को समायोजित करते हुए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसने उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए। इसके बाद मोदी सरकार ने विधेयक को वापिस लेने का फैसला किया। करीब साल भर बाद सरकार ने संसद में नया विधेयक रखा। डाटा प्रोटेक्शन बिल पर उतार-चढ़ाव की यह स्थिति दर्शाती है कि पूर्ण बहुमत के बावजूद विधि निर्माण को लेकर मोदी सरकार का रवैया कितना उदार एवं लचीला रहा।

अब स्थिति अलग और खासी जटिल है। जब कोई सरकार अस्तित्व के लिए अन्य दलों पर निर्भर होती है तो उसे गठबंधन धर्म को समझते हुए सलाह-मशविरे के साथ काम करना पड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए सफलतापूर्वक गठबंधन सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव परिणाम के कुछ महीने गुजरने के बाद मोदी की प्रतिक्रिया से भी यही संकेत मिलते हैं कि वह इन पहलुओं के प्रति सचेत हैं और अपेक्षित सामंजस्य में लगे हैं। जहां तक लचीलेपन का सवाल है तो वह व्यापक बहुमत के बावजूद अपनी नीतियां बदल चुके हैं। ऐसे में अब कई नीतियों को लेकर रुख-रवैये में परिवर्तन को लेकर उन्हें निशाना बनाने वाले नेता शायद प्रकृति के उस सबक को अनदेखा कर रहे हैं कि तूफान में वही पेड़ बचते हैं, जो हवा के रुख के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। जो पेड़ हवा के रुख से तालमेल नहीं बिठा पाते वे उखड़ जाते हैं। ऐसे में, मोदी सरकार के अस्तित्व का प्रश्न भी इसी पहलू में निहित है कि वह बदली हुई परिस्थितियों से किस प्रकार तालमेल बिठाए रखने में सफल रहती है।

(लेखक लोकतांत्रिक मामलों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

मत प्रचार की स्वतंत्रता पर हो पुनर्विचार

आरके सिन्हा

लोगों को मतप्रचार-प्रसार से जुड़ी छूट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि यह कोई दुकान या व्यापार नहीं है

मत प्रचार की आड़ में मतांतरण का सिलसिला। फाइल

भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी मत या पंथ को मानने या न मानने या फिर किसी भी मत से जुड़ने का अधिकार संविधान देता है, पर किसी प्रलोभन या गलतफहमी में योजनाबद्ध रूप से किसी तरह के मतांतरण को अपराध माना गया है। इस आलोक में उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत द्वारा हाल में अवैध मत परिवर्तन के मामले में दोषी करार दिए गए 12 लोगों को उम्रकैद और चार अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाना महत्वपूर्ण है। कोर्ट के मुताबिक, उमर गौतम और अन्य अभियुक्त एक साजिश के तहत धार्मिक उन्माद, वैमनस्य और नफरत फैलाकर देशभर में अवैध मतांतरण का गिरोह चला रहे थे। उनके तार कई दूसरे देशों से भी जुड़े थे। वे हवाला के जरिये विदेश से धन भेजे जाने के मामले में भी लिप्त थे। वे देश में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और दिव्यांगों को लालच देकर और उन पर अनुचित दबाव बनाकर बड़े पैमाने पर उनका मत परिवर्तन करा रहे थे। उमर गौतम को मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी के साथ 2021 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। वह एक ऐसे अवैध संगठन का संचालन कर रहा था, जो उत्तर प्रदेश में मूक-बधिर छात्रों और गरीब लोगों को इस्लाम में मतांतरित कराने में शामिल था। उमर गौतम पहले हिंदू था, लेकिन उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया और मतांतरण कराने के अवैध धंधे में सक्रिय हो गया। उसने करीब एक हजार गैर-मुस्लिम लोगों को इस्लाम में मतांतरित कराया।

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें स्वेच्छा या स्वविवेक से मत बदलने का अधिकार भी शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता और मत बदलने के अधिकार की बात तो कही गई है, पर उमर गौतम और उसके साथी गरीबों को लालच देकर और जोर-जबरदस्ती से मतांतरण करवा रहे थे। गौतम और उसका गिरोह भूल गया था कि मत परिवर्तन सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है और समाज में भयंकर नफरत पैदा कर सकता है। भारत में मत परिवर्तन एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें कानूनी, धार्मिक और सामाजिक सभी पहलू शामिल हैं। कुछ साल पहले केरल के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता-निर्देशक अली अकबर और उनकी ईसाई पत्नी लूसी अम्मा ने आर्य समाज में हवन के जरिये हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया था। आर्य समाज के स्वामी जी द्वारा उनका नया नामकरण भी कर दिया गया। अली अकबर को नया नाम मिला था राम सिम्हन। हिंदू धर्म ही क्यों? यह प्रश्न पूछे जाने पर अली अकबर ने कहा था, 'क्योंकि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। यहां नर्क में जाने का डर नहीं है। आप एक इंसान की तरह जी सकते हैं, क्योंकि भगवान आपके अंदर हैं। अपने भीतर ईश्वर को देखना एक महान विचार है।' कहते हैं कि राम सिम्हन केरल में हिंदू धर्म अपनाने वाले पहले मुसलमान थे, लेकिन यह राम सिम्हन के स्वविवेकपूर्ण निर्णय को दर्शाता है। इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

किसी को लालच देकर या जोर जबरदस्ती मतांतरण करवाना तो कतई सही नहीं माना जा सकता है। समझ नहीं आता कि कुछ मतों से जुड़े लोग क्यों इसी फिराक में रहते हैं कि उनके मत से अन्य मतों को मानने वाले जुड़ जाएं। कई इस्लामिक और ईसाई संगठन इसी कोशिश में रहते हैं कि दूसरे मत को मानने वाले उनके मजहब का हिस्सा बन जाएं? यह कोई बात हुई क्या? फिर यदि बाकी मतों को मानने वाले लोग भी यही करने लगें तो समाज में भाईचारा कहां और कैसे बचा रहेगा। अगर कोई अपने मन से उस मत को त्याग देता है, जिसमें उसका जन्म हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। संगीत निर्देशक एआर रहमान का ही उदाहरण लें, जिन्होंने खुद ही हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया। उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने भी इस्लाम अपना लिया। यहां तक तो सब ठीक है, पर कुछ तत्व सुदूर इलाकों में रहने वालों को अपने पाले में लाने के जुगाड़ में रहते हैं। इस सबकी तो हमारा संविधान अनुमति नहीं देता। जब उमर गौतम जैसों पर कार्रवाई होती है तो कुछ कथित बुद्धिजीवी प्रलाप करने लगते हैं। पिछले कई वर्षों से पंजाब से खबरें आ रही हैं कि राज्य में दलित सिखों को लालच देकर ईसाई मत से जोड़ा जा रहा है।

यह सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या भारत में मत प्रचार की अनुमति जारी रहनी चाहिए? कभी-कभी लगता है कि इस मसले पर देश में बहस हो ही जाए कि क्या भारत में मत प्रचार की स्वतंत्रता जारी रहे अथवा नहीं? देखा जाए तो केवल मत पालन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मत के प्रचार-प्रसार की छूट की कोई आवश्यकता ही नहीं। मत कोई दुकान या व्यापार तो है नहीं जिसका प्रचार-प्रसार करना जरूरी हो। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो देखते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने सभी धार्मिक समुदायों को अपने मत के प्रचार की छूट दी थी। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? बेशक भारत में ईसाई मत की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ठोस और ईमानदारी से काम किया गया है, पर कहने वाले कहते हैं कि उस सेवा की आड़ में मतांतरण का ही उसका मुख्य लक्ष्य रहा है। उधर इस्लाम का प्रचार करने वाले बिना कुछ किए ही मतांतरण करवाने के मौके खोजते हैं। अब आप देखें कि आर्य समाज, सनातन धर्म और सिखों की तरफ से देश में सैकड़ों स्कूल, कालेज और अस्पताल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसी ईसाई या मुसलमान के मतांतरण का कभी प्रयास नहीं किया। लोगों को अपने मत को मानने की तो अनुमति होनी चाहिए, पर अपने मत का प्रचार करने या मतांतरण करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मधुर वाणी

मधुर वाणी जीवन के सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है। इसका वैशिष्ट्य है, यदि कोई शोकाघात अथवा कुसंग के प्रभाव से पाषाणवत् हो गया हो, तो वह भी प्रसन्न और संवेदना से युक्त हो जाता है। यदि हम सर्वत्र सुख और प्रसन्नता का परिवेश चाहते हैं, तो समाज में विनम्रता के साथ परस्पर मधुर वार्तालाप करना चाहिए। लोक में सुख, शांति और समुल्लास की सुप्रतिष्ठा का मुख्य हेतु है-मधुर वचन का सप्रेम दान। कोई कितना भी कष्ट में हो, यदि उससे दो मीठे बोल लें तो संभवतः वह कुछ देर के लिए अपनी पीड़ा भूल जाएगा। वाणी से किसी के भी हृदय में स्थान बनाया जा सकता है।

एक सूक्ति है-वचने किं दारिद्र्यम्' अर्थात बोलने में भी क्यों कंजूसी करना? आज समाज में जो परस्पर विद्वेष और उपेक्षित व्यवहार देखने-सुनने में आता है, उसका एकमात्र कारण है हमारी जीवनशैली मधुर-स्नेह वार्ता से कृपण हो गई है। हमारे कवियों ने तदर्थ उपदेशित किया है-वाणी ऐसी निकलनी चाहिए, जिसको सुनने वाले का मन प्रसन्नता से भर जाए। मीठा बोलने में न ही कोई कष्ट होता है और न ही कुछ धनादि की हानि होती है। मधुर वाणी ही विनम्रता का आधार है। कटुभाषण अत्यंत अनर्थकारी और विवाद का मूल है। आज कहीं परस्पर विद्वेष और द्वंद्व दिखाई-सुनाई पड़ता है, तो उसके पीछे उसका मूल कारण होता है कटु तीखे वचन। तीखे बाणों से मनुष्य के हृदय में उतनी पीड़ा नहीं होती है, जितनी कठोर वचनों से। शस्त्रादि के घात से कटा हुआ बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, किंतु कटुवचन रूपी शस्त्र से हुआ घाव जीवन भर नहीं भरता है। वाणी का मधुर प्रयोग सदा करना चाहिए, इससे पराए भी अपने हो जाते हैं और रूठे लोग भी साथ देने वाले हो जाते हैं। अतः हम सदा-सर्वत्र मधुर-स्नेहयुक्त वचनों का आदान-प्रदान करें, जिससे समाज में बंधुत्व और प्रेम का सुंदर साम्राज्य स्थापित हो।

आचार्य नारायण दास

देश का नाम बदलने की जटिल प्रक्रिया

डा. महेश परिमल

आमतौर पर ऐसे देश भी अपना नाम बदलते हैं, जो पूर्व में किसी अन्य देश के गुलाम थे

हम सबने देखा कि कैसे मद्रास चेन्नई, बेंगलोर बेंगलुरु, उड़ीसा ओडिशा, कलकत्ता कोलकाता, इलाहाबाद प्रयागराज, हबीबगंज रानी कमलापति, होशंगाबाद नर्मदापुरम, उत्तरांचल उत्तराखंड, पांडिचेरी पुदुचेरी, बंबई मुंबई हो गए। हमारे कई पड़ोसी देशों के नाम भी बदले हैं। जिसे हम बर्मा कहते थे, वह अब म्यांमार हो गया है। तुर्की ने अपना नाम तुर्किये कर लिया है। चेक रिपब्लिक अब नए नाम चेकिया से पहचाना जाने लगा है।

2011 में आस्ट्रेलिया के एक शहर ''स्पीड'' के निवासियों ने एक महीने के लिए अपने शहर का नाम बदलकर ''स्पीडकिल्स'' रखा था। इसकी वजह यही थी कि उस शहर में लोग बहुत तेजी से अपने वाहन दौड़ाते थे। इससे दुर्घटनाएं बढ़ने लगी थीं। वाहन चालकों में जागृति लाने के लिए ऐसा किया गया था। ऐसे देश भी अपना नाम बदलते हैं, जो भूतकाल में किसी अन्य देश के गुलाम थे। गुलामी की कड़वी यादों को भुलाने के लिए वे ऐसा करते हैं। ब्रिटेन की गुलामी करने वाले ''सिलोन'' ने आजादी प्राप्त करने के बाद अपना नाम बदलकर ''श्रीलंका'' कर दिया। ''अपर वोल्टा'' ने अपना नाम बदलकर ''बुर्किना फासो'' कर लिया। 2019 में ''मेसेडोनिया'' ने अपना नाम बदलकर ''नार्थ मेसेडोनिया'' कर लिया था। ग्रीस में भी ''मेसेडोनिया'' नामक प्रदेश है। इससे ग्रीस काफी समय से उससे अपना नाम बदलने को कह रहा था।

नया नाम देने की आखिर प्रकिया क्या होती है? वास्तव में यह प्रक्रिया जटिल और काफी खर्चीली भी है। सबसे पहले तो नाम बदलने के लिए देश के भीतर ही मतदान होता है। इसके बाद नया नाम संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को भेजा जाता है। यूएन की छह अधिकृत भाषा (अरबी, मंदारिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश) में यह नाम किस तरह से लिखा जाएगा, यह बताना होता है। यह सब ठीक-ठाक रहा, तो प्रस्तावित नाम यूएन द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद ही वह देश नया नाम प्राप्त करता है। रही बात खर्च की, तो नया नाम मिलने के बाद उस देश की सेना की वर्दी, देश की मुद्रा, सरकारी दस्तावेज और कई चीजों का नाम भी बदलना होता है। इसमें पेपरवर्क, वेबसाइट, सरकारी कार्यालयों में साइनेज और सभी आफिसों के लेटरहेड बदलने होते हैं। इस सभी कार्यों को संपादित करने में काफी खर्च होता है। 2018 में अफ्रीकी देश ''स्वाजीलैंड'' का नाम बदलकर ''इस्वातिनी'' किया गया। इस पर करीब 50 करोड़ रुपये का खर्च आया। वह भारत के क्षेत्रफल से करीब 10 गुना छोटा है। भारत की 140 करोड़ से अधिक की आबादी के मुकाबले उस देश की आबादी केवल 12 लाख ही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अब यदि भारत जैसे विशाल देश का नाम बदलना हो, तो कितनी बेशुमार दौलत खर्च होगी?

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खतरनाक राह पर राहुल गांधी

'कांग्रेस को अलग राह पर ले जाते राहुल' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने राहुल गांधी के पार्टी के सिद्धांतों से भटकाव का विवेचन किया है। राहुल गांधी के हालिया वक्तव्यों और भाषणों से ऐसा अहसास होता है कि उन्हें कांग्रेस की विचारधारा और उसकी पुरानी रीतियों-नीतियों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सत्ता प्राप्ति को ही अपना अंतिम लक्ष्य बना लिया है, जिसके लिए वह कुछ भी करने को आमादा हैं। यहां तक कि उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों से मेलजोल से भी परहेज नहीं रह गया है। जिस खालिस्तानी आतंक के कारण उनकी दादी इंदिरा गांधी और अन्य कई नेताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, उन खालिस्तानियों का वैचारिक समर्थन करना एक बड़ी त्रासद स्थिति को दर्शाता है। यही नहीं, बार-बार जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का उनका एलान देश में जातिवाद की आग में घी डालने का कुत्सित प्रयास ही कहा जाएगा। प्रतीत होता है कि वह सत्ता पाने के लिए देश को अराजकता की भट्ठी में झोंक रहे हैं। चाहे भविष्य में इसके लिए देश को इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

जमानत मिलने का उत्साह

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले केस में जमानत देने के तुरंत बाद ही सीबीआइ का प्रवेश संशय पैदा करता है। दूसरी ओर यह भी पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के आरोपों से कोर्ट ने क्लीन चिट कतई नहीं दी है, वरन जमानत देते समय सख्त शर्तें लगाई गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जा सकते। उपराज्यपाल की अनुमति के बगैर कोई पेपर साइन नहीं कर सकते आदि शर्तें निश्चित ही कठोर शर्तों के दायरे में आती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। दिल्ली में किसी भी दुकानदार के पास पटाखों की खेप मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। यहां तक कि दिल्ली में विवाह उत्सवों में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जैसे ही जमानत पर बाहर आए देश की राजधानी दिल्ली पटाखों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। आखिरकार जनसाधारण के लिए बनाई गई दिल्ली सरकार की नीतियां स्वयं की पार्टी पर लागू नहीं होतीं? जमानत मिलना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार होता है। इसलिए छोटे-बड़े नेताओं को अति उत्साह से बचना चाहिए।

दीपक गौतम, सोनीपत

विभाजनकारी राजनीति

संजय गुप्त का आलेख 'कांग्रेस को अलग राह पर ले जाते राहुल' एकदम सटीक है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने अच्छे-बुरे जो भी कार्य किए हों, लेकिन देश के बाहर देश, देश के संस्थानों की बुराई कभी नहीं की। चीन में उन्हें सब हरा-हरा दिखता है और उसका महिमामंडन करते हैं। इस अमेरिका दौरे में तो राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दीं। भारत विरोध के लिए कुख्यात अमेरिकी सांसद से ही मिले। सिखों के बारे तो ऐसा बयान दिया, जैसा भारत के किसी राजनीतिक विरोधी सिख ने भी नहीं दिया। उन्होंने 100 प्रतिशत झूठ बोला कि भारत में सिख पगड़ी, कड़ा पहनने से और पहन कर गुरुद्वारा जाने से डरते हैं। जाहिर है खालिस्थान समर्थक पन्नू को आग में डालने के लिए घी दे दिया। उनके पूर्वजों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति तो अवश्य की, लेकिन जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आरक्षण को भी मुख्य एकमात्र मुद्दा नहीं बनाया। यह देश को विभाजित करने का काम राहुल गांधी जोर-शोर से कर रहे हैं। इसका प्रमाण है जातिगत जनगणना पर बेहद जोर। क्षेत्रवाद बढ़ाने के लिए कहा कि भारत में तमिल, तेलुगु भाषियों से कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति और खानपान हिंदी भाषियों से कमतर है।

सीपी बंसल, दिल्ली

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

117.6 अरब बार लेनदेन संपन्न हुए यूपीआइ के माध्यम से भारत में पिछले वर्ष यानी 2023 में, जिसमें इसके पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 81 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है।

आजकल

यूपीआइ की बढ़ती वैश्विक मान्यता

भारत में यूपीआइ यानी 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' आधारित भुगतान प्रक्रिया अत्यंत लोकप्रिय हो चुकी है। समूचे विश्व में होने वाले डिजिटल भुगतानों में यूपीआइ की लगभग आधी हिस्सेदारी हो गई है। इस प्रकार डिजिटल भुगतान में हमारा देश अमेरिका और चीन से आगे निकलते हुए इस मामले में ग्लोबल लीडर बन गया है। यूपीआइ का आरंभ अब मालदीव में भी होने जा रहा है। इस संबंध में एमओयू भी हो चुका है। यह यूपीआइ की बढ़ती वैश्विक मान्यता को ही दर्शाता है

ऋषभ मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर, कानपुर इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर

प्रतीकात्मक

आज से लगभग एक दशक पहले तक आम आदमी के लिए यह कल्पना से परे की बात थी कि हमारा मोबाइल ही हमारा पर्स या वालेट बन जाएगा। लेकिन वर्ष 2016 में यूपीआइ यानी 'यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' की लांचिंग ने इसे संभव कर दिखाया। वैसे तो वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी को कई मामलों में नकारात्मक असर के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन कम से कम 'यूपीआइ' के लिए तो यह कहा ही जा सकता है कि यह कदम एक तरह से वरदान बन गया। अब एक रुपये से लेकर हजारों रुपये के पेमेंट में यूपीआइ का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाने लगा है। डिजिटल लेनदेन के आंकड़ों में भारत 117.6 अरब ट्रांजेक्शन के साथ दुनिया का नंबर वन देश बन चुका है। साल 2021 में यूपीआइ पहली बार देश की सीमाओं को पार करके भूटान गया था। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि इसका उपयोग भारत से आगे बढ़ते हुए अन्य कई देशों में भी होने लगा है। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, मारीशस, फ्रांस और श्रीलंका में भी यूपीआइ को भुगतान की एक प्रणाली के रूप में मान्यता मिल चुकी है। अभी हाल ही में मालदीव ने भी इससे जुड़ने की घोषणा की है।

यूपीआइ की सफलता के चार प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। इसमें पहला है, स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या पिछले आठ साल में हमारे देश में दोगुना से अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में यह संख्या 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। यूपीआइ की सफलता की एक मुख्य वजह भारत में सस्ते और आसानी से मिलने वाले स्मार्टफोन हैं। वर्ष 2016 में हमारे देश में डिजिटल तकनीक और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आम आदमी की पहुंच में आ चुकी थीं। उस समय स्मार्टफोन की संख्या 30 करोड़ के आसपास थी, जो अब 60 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका सीधा असर यूपीआइ की प्रगति पर पड़ा है।

दूसरा कारण, हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में इंटरनेट का सस्ता होना भी है। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कंपनियों ने वर्ष 2016 से तेज गति की इंटरनेट सेवा दी और वह भी बेहद सस्ते दामों पर। पहले एक जीबी डाटा के लिए लगभग 225 रुपये खर्च करने पड़ते थे। धीरे-धीरे यह सस्ता होता गया और वर्तमान में मोबाइल इंटरनेट डाटा की कीमत महज दस या बीस रुपये प्रति जीबी की हो गई है। वर्ष 2015 तक प्रत्येक भारतीय महीने में औसतन 700 एमबी डाटा इस्तेमाल करते था। लेकिन 2023 तक यह बढ़कर औसतन 21.4 जीबी महीना हो गया। इसका सीधा फायदा यूपीआइ को हुआ। जहां अगस्त 2016 में यूपीआइ के जरिए केवल 93 हजार पेमेंट हुए थे, वहीं साल 2023 में 11,765 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुए।

तीसरा कारण, देश में स्टार्टअप की संख्या का बढ़ना भी रहा है। साल 2016 में यूपीआइ के शुरू होने के बाद से भारत में 50 से भी ज्यादा यूपीआइ एप आ गए। इससे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम और भी मजबूत हुआ है। डिजिटल पेमेंट की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि छोटे से छोटा दुकानदार, यहां तक कि रेहड़ी-पटरी वाले, फल-सब्जी वाले, रिक्शा वाले आदि भी यूपीआइ से रकम प्राप्त करने की व्यवस्था अपने पास रखते हैं।

चौथे कारण के रूप में वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी को भी शामिल किया जा सकता है। नोटबंदी के संदर्भ में भले ही तमाम प्रकार के ऐसे तर्क दिए जाएं कि यह पूरी तरह से सफल नहीं रही, परंतु इतना तो तय है कि इसने देश में डिजिटल पेमेंट को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया। पहले तो मजबूरी में लोग डिजिटल पेमेंट से जुड़े और फिर धीरे-धीरे यह आदत में शामिल होता गया। इससे यूपीआइ के जरिए होने वाले भुगतान की संख्या और मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही।

पर्यटकों के लिए आसानी : भारत से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 लाख लोग विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे में यूपीआइ का आसान और जाना पहचाना तरीका विदेश में भी काम आ रहा है। जिन सात देशों में यूपीआइ का प्रचलन आरंभ हो गया है, वहां तो पर्यटकों को यूपीआइ से पेमेंट करने में आसानी हो रही है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय अपने विदेशी मोबाइल नंबर को भारतीय बैंक खाते (एनआरआइ/ एनआरओ) से जोड़कर यूपीआइ से पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही विदेशी लोग भी भारत आने पर 'यूपीआइ वन वर्ल्ड एप' से यूपीआइ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

वर्ष 2025 के अंत तक यूपीआइ वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण भुगतान स्विच बनने के लिए तैयार है, जिसका अनुमानित वार्षिक वाल्यूम लगभग 264 अरब लेनदेन होगा। यह चौंका देने वाला आंकड़ा मास्टरकार्ड और वीजा के लेनदेन की मात्रा को पार कर जाएगा, जो वैश्विक भुगतान परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। वस्तुतः यूपीआइ लेनदेन की वृद्धि अभूतपूर्व रही है। अकेले 2023 में यह लेनदेन 2022 की तुलना में 81 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ 117.6 अरब लेनदेन तक पहुंच गया। मजबूत बुनियादी ढांचा, वास्तविक समय प्रसंस्करण क्षमताएं और संबंधित बैंकों व फिनटेक कंपनियों के व्यापक नेटवर्क ने यूपीआइ के तहत लेनदेन की बढ़ती संख्या को कुशलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाया है।

यूपीआइ को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें लेनदेन की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना, बढ़ते लेनदेन की मात्रा का प्रबंधन करना और सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना शामिल है। इसके बावजूद वैश्विक भुगतान का परिदृश्य निस्संदेह नया रूप लेगा, जिसमें यूपीआइ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरेगा। नवाचार और प्रतिस्पर्धा से प्रेरित इस भुगतान प्रणाली का भविष्य रोमांचक दिखाई दे रहा है।

अमेरिका के आर्थिक माडल पर उठते सवाल

प्रह्लाद सबनानी
आर्थिक मामलों के जानकार

अमेरिका विश्व के लगभग समस्त देशों अपना वर्चस्व कायम करता रहा है। पूरे विश्व में, एक तरह से लगभग समस्त क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की नीतियों को प्रभावित करने में अमेरिका सफल रहा है एवं इस प्रकार अपनी प्रसारवादी नीतियों को भी लागू करता रहा है। परंतु हाल ही के वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अमेरिका की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रीय ऋण 35 लाख करोड़ डालर के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर लगभग 25 लाख करोड़ डालर का है। इसका आशय यह है कि आय की तुलना में ऋण अधिक ले लिया गया है। अमेरिकी वित्त व्यवस्था पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि अमेरिकी सरकार को अपने सामान्य खर्चों को चलाने के लिए भी बाजार से और अधिक ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है और इस उद्देश्य से प्रति वर्ष अमेरिकी संसद में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पहुंचना होता है।

पिछली सदी के चौथे दशक में पूरे विश्व के विनिर्माण क्षेत्र में अमेरिका की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक थी, परंतु अब यह घटकर 17 प्रतिशत से भी कम हो गई है। कई उद्योगों के मामले में उत्पादन का जो एकाधिकार अमेरिका के पास होता था, वह अब अन्य देशों के पास चला गया है। अमेरिकी कंपनियों ने कुशल कर्मचारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के स्वास्थ्य खर्चे की पूरी लागत स्वयं वहन करना प्रारंभ किया था। अमेरिका में दो करोड़ कर्मचारी विनिर्माण कार्यों में कार्यरत थे जो घटकर 1.2 करोड़ रह गए हैं। अमेरिका में जब प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली थी, उस समय 10 में से नौ श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे, जबकि आज केवल दो प्रतिशत श्रमिक ही कृषि क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस प्रकार अमेरिका में रोजगार की दृष्टि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में बहुत अधिक संकुचन हुआ है।

पिछली सदी के पांचवें दशक से यदि तुलना करें तो अमेरिका में स्टील, कपड़ा (वस्त्र, परिधान एवं टेक्सटाइल), उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगभग समाप्त से हो गए हैं। वाहन उद्योग के क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी विनिर्माण इकाइयों को चीन आदि देशों में स्थापित किया है। साथ ही, जापान की कई कंपनियों ने वाहन के क्षेत्र में अमेरिका में आकर अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की है। उक्त उद्योगों में अमेरिकी मूल के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं या लगभग समाप्त हो गए हैं। अमेरिका में उपयोग हो रहे स्मार्टफोन के 50 प्रतिशत से अधिक उपकरण आयात किए जा रहे हैं यानी इनका उत्पादन वहां नहीं हो रहा है।

ब्यूरो आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के दिसंबर 2016 के एक आंकड़े के अनुसार, अमेरिका में प्रति घंटा वास्तविक मजदूरी दर वर्ष 1947 में 5.35 डालर थी जो वर्ष 1973 में बढ़कर 9.26 डालर हो गई। परंतु उसके बाद से लगभग उसी स्तर पर बनी हुई है जो वर्ष 2015 में 9.07 डालर थी। अमेरिका में समय के साथ साथ विनिर्माण इकाइयां बंद होती गईं एवं उच्च तकनीकी, सूचना आधारित सेवा क्षेत्र एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उभरते गए। आउटसोर्सिंग के चलते सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। अतः अमेरिका में विनिर्माण इकाइयों के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है। अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों में इस प्रकार के हालात देख कर अब तो कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक विकास के पूंजीवादी माडल पर ही प्रश्नचिह्न लगाया जाने लगा है एवं यह कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिकी स्वप्न का अंत निकट तो नहीं है।

खरी-खरी

हिंदी पखवाड़ा

विनोद कुमार विक्की

भारत की एकमात्र भाषा हिंदी ही है, जिसे सितंबर में गौरवान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जहां अन्य भाषाओं के लिए कोई एक विशेष दिवस तक मयस्सर नहीं है, वहीं हिंदी के लिए सितंबर में एक पूरे पखवाड़ा का प्रविधान किया गया है। हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह एवं हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में हिंदी के तमाम साहित्यकार, अधिकारी, मंत्री-संतरी को बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने एवं हिंदी भाषा पर गौरव करने का परम सुख प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता हैं। हिंदी पखवाड़ा के दौरान हर किसी की रक्त नलिकाओं में रक्त के बजाय हिंदी भाषा का प्रवाह होने लगता है। हर कोई हिंदी की बातें और हिंदी में बातें करने को आतुर दिखाई देता है।

आधुनिकता के नाम पर हिंदी की गद्दी पर अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा चाहे जितना आधिपत्य जमा लें, लेकिन बहुआयामी भाषा हिंदी कई मायनों में आज भी प्रासंगिक है और हमेशा रहेगी। यथा, राजनीतिक पार्टियों की दुकान हिंदी एवं गैर हिंदी भाषी कस्टमर के नाम पर खूब चल रही है और हमेशा चलती रहेगी।

सरकारी कार्यालयों एवं रेलवे स्टेशन की दीवारों पर स्लोगन लिखने के काम में आज भी हिंदी भाषा का व्यापक प्रयोग किया जाता है। वाह-वाह और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन हिंदी की बुनियाद पर ही सफलीभूत होते हैं। मजे की बात है कि हिंदी भाषा में माता-बहन के संबोधन वाले शब्दों के साथ किसी को गरियाने में जो सुकून मिलता है, वह अंग्रेजी भाषा के इडियट, नानसेंस, स्टुपिड आदि शब्दों के उच्चारण करने से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता।

हिंदी की समृद्धि का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी भाषा को अपनाया नहीं, बल्कि दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बहरहाल, हिंदी में लेखन प्रतियोगिता, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं, कवि-कवयित्री, लेखक पत्रकारों ने हिंदी के प्रचार-प्रसार का बीड़ा जब तक उठा रखा है, तब तक हम हर्षोल्लास के साथ हिंदी पखवाड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं।

पोस्ट

अरविंद केजरीवाल को जिन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, उनमें स्पष्ट था कि वह मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का अपेक्षित रूप से निर्वाह नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की उनकी पेशकश 'आपदा में अवसर' तलाशने का राजनीतिक प्रयास ही कही जा सकती है। अब सवाल यही है कि क्या इससे उन्हें लाभ मिलेगा?

संकेत उपाध्याय@sanket

हवाला कांड में नाम आने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने एलान किया था कि जब तक अदालत से उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती, तब तक वह संसद में कदम नहीं रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को भी ऐसी ही कोई घोषणा करनी चाहिए थी। इससे भारतीय राजनीति में नैतिकता का एक नया प्रतिमान स्थापित होता।

आशुतोष@ashutosh83B

एशियाई चैंपियंस ट्राफी में पाकिस्तान को हराकर भारतीय हाकी टीम ने यही साबित किया कि मानसिक दृढ़ता में उसका कोई सानी नहीं। बाल टैपिंग, गोलकीपिंग से लेकर पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदलना-तीनों मोर्चों पर भारत ने चमत्कारिक सुधार किया।

सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत कल का परिणाम

बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डाक्टरों का धरने पर रहना सही है?

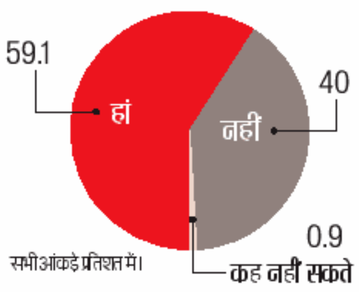

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

शासन करना है नहीं बंधन में आसान,
तभी केजरीवाल जी छोड़ भगे मैदान।
छोड़ भगे मैदान आप हैं नेता शातिर,
मारा तगड़ा दांव आज सिंपैथी खातिर!
अब रो-रो कर रोज दिया जाएगा भाषण,
सीएम पद फिर पाय करें जिस्से वह शासन!!

- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

अपराधियों के एनकाउंटर में जातियों की सियासत

अजय जायसवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तर प्रदेश

कहा तो यही जाता है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी केवल अपराधी होता है, लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराधियों के जाति-धर्म की सियासत कुछ ज्यादा ही गर्माई हुई है। अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टालरेंस नीति पर चलने वाली योगी सरकार जहां अपराध की छोटी-बड़ी घटनाओं में लिप्त अपराधियों के खिलाफ बेहद कड़े कदम उठाने में कतई पीछे नहीं रहती, वहीं विपक्षी दलों में खासतौर से मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सपा मुखिया अखिलेश यादव, सरकार पर जाति-धर्म के आधार पर कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश के आरोपों पर पलटवार करते सत्ताधारी भाजपा नेता कहते हैं कि सपा के डीएनए में ही गुंडई है। अपराधियों की जाति-धर्म को लेकर सपा-भाजपा के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप में बसपा भी कूद चुकी है। बसपा प्रमुख मायावती को लगता है कि अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर सपा-भाजपा जबरदस्ती की राजनीति कर रहे हैं। दोनों ही चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे हैं और दोनों की सरकारों में प्रदेश की कानून-व्यवस्था बदतर रही है। मायावती तो प्रदेशवासियों को सपा-भाजपा से सजग रहने की हिदायत देते हुए कहती हैं कि बसपा सरकार में ही कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ।

पिछले दिनों सुलतानपुर में डकैती की एक घटना के आरोपित जौनपुर के इनामी अपराधी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मंगेश के एनकाउंटर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसकी हत्या किए जाने का दावा करते हैं। सवाल उठाते हैं कि 'कैसा दिमाग है लोगों का, चप्पल में एनकाउंटर कर दिया?... उनको मंगेश की मां का दर्द और बहन के आंसू समझ नहीं आ रहे।' सपा अध्यक्ष, भाजपा पर पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए एनकाउंटर के आंकड़े एक्स पर पोस्ट करते हैं। कहते हैं कि मंगेश का एनकाउंटर भी पुलिस ने जाति देखकर किया। वह मंगेश के स्वजनों से मिलते हैं। पुलिस अभिरक्षा में हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की बात कहते हैं और तीखे स्वर में बोलते हैं, 'भाजपा सरकार ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है।' अखिलेश की सांसद पत्नी डिंपल यादव भी मंगेश के एनकाउंटर को मानवता और संविधान की हत्या बताती हैं। कांग्रेस भी मंगेश के एनकाउंटर पर राज्यपाल को पत्र लिख हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराए जाने की मांग कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश के स्वजन से मिलकर पुलिस पर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। मंगेश के एनकाउंटर पर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कि सपा और अखिलेश यादव अपराधियों में जाति ढूंढ़ते हैं, के जवाब में अखिलेश ने यहां तक कह दिया कि 'मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता।' सपा प्रमुख के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित योगी सरकार के कई मंत्रियों ने अखिलेश पर चौतरफा हमला बोला। पाठक ने तो सपा शासनकाल में हुए अपराधों की सूची सामने रखते हुए आरोप लगाया कि सपा के डीएनए में ही गुंडई है। पिछड़ों की राजनीति करने वाले एनडीए के सहयोगी सुभासपा व निषाद पार्टी के मुखिया भी सपा प्रमुख पर बरसे कि अखिलेश को केवल यादव की चिंता सता रही है। सपा प्रमुख के बयान पर संत भी क्षुब्ध नजर आए और इसे धर्म का अपमान बताते हुए कहा कि अखिलेश माफी मांगें। विपक्ष के गंभीर आरोपों पर पहला मौका रहा कि प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार खुद जवाब देने सामने आए।

योगी आदित्यनाथ। फाइल

अखिलेश यादव। फाइल

वर्ष 2017 में योगी के मुख्यमंत्री बनने से अब तक राज्य में रिकार्ड 12,964 मुठभेड़ में 207 अपराधियों को पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। चार वर्ष पहले कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी व हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे, प्रवीण दुबे उर्फ बउवा से लेकर मर चुके माफिया अतीक अहमद के बेटे असद व शूटर मु. गुलाम, एक लाख का इनामी मेहरबान, ढाई लाख का इनामी आदित्य राणा उर्फ रवि आदि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। एनकाउंटर में मारे जाने वालों में कोई भी निर्दोष नहीं है, सभी का आपराधिक इतिहास रहा है लेकिन ज्यादातर एनकाउंटर में विपक्ष, अपराधियों की जाति को देख योगी सरकार पर हमलावर रहा है। वर्ष 2020 में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे व अन्य जब पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तब भी यही सवाल चर्चा में था कि योगी सरकार में खासतौर से ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। अब डकैती में लिप्त मंगेश का एनकाउंटर फर्जी है या नहीं, यह तो जांच का विषय हो सकता है लेकिन प्रदेश में जाति की सियासत का पारा चढ़ता दिख रहा है।

छत्तीसगढ़ डायरी

खुशहाल प्रदेश बनाने का संकल्प

डा. सुनील गुप्ता
संपादकीय प्रभारी, बिलासपुर

छत्तीसगढ़ सरकार एक्शन मोड में आ गई है। यह हम नहीं सरकार के कामकाज और लिए जा रहे ठोस निर्णयों को देखकर, समझकर और अनुभव करके लोग कह रहे हैं। जनता की जुबान पर जब कोई बात चढ़ जाती है या फिर मन में कोई बात आ जाए, तब यह मानना ही पड़ेगा कि वह सरकार को कामकाज के बिना परखने लगी है। मापदंड के अपने तराजू पर तौलने लगी है। जनता का तराजू ही असली है। काम उनका ही होना है। जाहिर है, संतुष्टि भी उनकी जरूरी है। जब सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट हो जाए और अपना समर्थन देना शुरू कर दे, तब मानिए सरकार काम अच्छा कर रही है।

जनता की संतुष्टि इस बात पर निर्भर करती है कि निचली पंक्ति के लोगों के बीच काम का प्रभाव दिखाई दे, मैदानी और दूरस्थ इलाके में सरकार कामकाज करती दिखाई दे, तभी न। जी हां, ऐसा हो रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। दो ऐसे काम हैं जो सीधे तौर पर समाज में खुशहाली बिखेरते नजर आ रहे हैं। वनांचल के आदिवासी अब झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में चैन की नींद सो रहे हैं। 18 लाख गरीबों के अपने आशियाने का सपना शीघ्र पूरा होने वाला है। केंद्र सरकार ने अपना फंड जारी कर दिया है। दीपावली में एक बेहतरीन उपहार गरीबों को केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला है। यह भी संभव है कि इस दीपावली अपने आशियाने में मां लक्ष्मी की पूजा हो। लक्ष्मी के शुभागमन के साथ ही सुख समृद्धि का वास होगा। किसानों की झोली सरकार पहले ही भर चुकी है। केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है। गरीबों के चेहरे पर संतुष्टि का भाव हो, किसानों के चेहरे खिले हों और खेत व खलिहान अन्न से भरे हों। यही तो समृद्धि और विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी निशानी है।

कृषि प्रधान देश और कृषि प्रधान प्रदेश में किसान समृद्ध होंगे तो प्रदेश की आर्थिकी अपने आप बढ़ेगी। औद्योगिक गतिविधियों का विकास भी तेजी के साथ होगा। यह सब होते दिखाई दे रहा है और इसके लिए इसी अंदाज में सरकार एक्शन मोड में नजर आने लगी है। बीते साढ़े नौ महीने की सरकार के कामकाज का यह चमकदार आईना है, जिसे दिखाना और सरकार की समीक्षा करना भी उतनी ही जरूरी है। जब तक सिंहावलोकन न हो, कामकाज को परखने का एक मापदंड न हो तो आप और हम भला कैसे और किस अंदाज में परखेंगे? सरकार के एक ठोस कदम की ओर अपने नजरिए से आपके बीच उन बातों को रखने की कोशिश करते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस। दो दिन चली कान्फ्रेंस का पहला दिन। साढ़े नौ महीने का परफारमेंस दिखाने का अवसर था कलेक्टरों को। प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर की परफारमेंस रिपोर्ट सरकार के पास पहले से ही मौजूद थी। एक-एक जिले के कलेक्टर ने अपने कामकाज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। दूसरे दिन प्रदेशभर के एसपी की बारी थी। राजस्व के प्रकरणों से लेकर कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा और परफारमेंस को लेकर पैनी नजर। कुछ को सीएम की तरफ से शाबाशी और कुछ कलेक्टर-एसपी के कामकाज को लेकर नाराजगी। दोनों ही तरह के नजरिए और अंदाज सामने आए। कान्फ्रेंस के तत्काल बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कमजोर परफारमेंस वाले कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए। इस कार्रवाई से नौकरशाहों को साफ संदेश है कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अफसर और जनता दोनों को सरकार का बड़ा संदेश : कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस के 24 घंटे के भीतर सरकार एक्शन मोड में आ गई। कड़ा रुख नजर आया। ऐसे आइएएस व आइपीएस जिनका परफारमेंस सरकार के मापदंड के अनुसार फिट नहीं बैठ पाया, उन्हें हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। कुछ कलेक्टर और एसपी को हटाकर नए आइएएस व आइपीएस को जिम्मेदारी सौंप दी गई। विष्णुदेव साय के इस कड़े अंदाज की चर्चा होनी भी स्वाभाविक है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, केंद्र और राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई कहें या फिर लापरवाही नहीं बरतने का संदेश। इस प्रकार सुशासन की दिशा में सरकार के बढ़ते मजबूत कदम का इशारा मुख्यमंत्री ने दिया है। यह संदेश एकतरफा नहीं है। आम जनता और सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर रखने वाले अफसरों के लिए भी बड़ा संदेश है। कड़ाई के पीछे खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का एक ईमानदार संकल्प भी दिखाई दे रहा है।

कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जनसंपर्क विभाग

माफिया के लिए कड़ा इशारा: कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस का बड़ा इंपैक्ट भी अब आने लगा है। माफिया पर सख्ती बरतने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लैंड से लेकर सैंड माफिया तक की कुंडली सरकार ने तैयार कर ली है। बीते शनिवार को बिलासपुर में यह दिखाई भी दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लैंड माफिया को बेदखल करते हुए निर्माण कार्य पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। लिहाजा यह भरोसा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और भी बेहतर होगी।

****

पांच हजार करोड़ का हुआ आडियो उपकरण बाजार

नई दिल्ली : भारत के आडियो उपकरण बाजार के आकार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिसर्च फर्म जीएफके की एक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में आडियो उपकरण बाजार की आफलाइन खुदरा बिक्री पांच हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। व्यक्तिगत आडियो श्रेणी में 61 प्रतिशत की सालाना वृद्धि से समग्र बाजार में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू और व्यक्तिगत दोनों श्रेणियों में उच्च गुणवत्ता वाले आडियो उत्पादों की मांग बढ़ी है। (प्रेट्र)

हम नौ हजार करोड़ रुपये की लागत से कर्नाटक में एनोड संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 90 हजार टन प्रति वर्ष होगी।

— विक्रम हांडा, ग्रबंध निदेशक, एथिल्सन समूह

एक नजर में

स्टार्टअप्स के लिए नए पोर्टल की लांचिंग आज

नई दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को स्टार्टअप्स के लिए नए पोर्टल की लांचिंग करेंगे। इस पोर्टल का नाम भारत स्टार्टअप नालेज एक्सेस रजिस्ट्री (भास्कर) रखा गया है। यह पोर्टल एक केंद्रीय हब के तौर पर काम करेगा, जहां पर स्टार्टअप, निवेश, सेवा प्रदाता और सरकारी संस्थान समझौतों, विचारों के आदान-प्रदान और विकास में तेजी के लिए एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। (प्रेट्र)

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान दे भारत

नई दिल्ली : रिसर्च फर्म एलारा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में ऊर्जा की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में आपूर्ति संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भारत को सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ऊर्जा मांग को सौर घंटों में स्थानांतरित करने पर जोर देना चाहिए। (एएनआइ)

2026-27 तक 13% होगी ई-दोपहिया की हिस्सेदारी

नई दिल्ली : देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया अपनाने का चलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। वैश्विक निवेश फर्म जेफरीज ने एक रिपोर्ट में उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2026-27 तक कुल दोपहिया में इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत हो जाएगी। 2023-24 में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत थी। केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए हाल में प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। (एएनआइ)

ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप खुद को ढालें बैंक

चेन्नई : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ग्राहकों की बदलती जरूरतों और बाजार में आ रहे बदलावों के अनुरूप खुद को ढालना चाहिए। इंडियन बैंक की ओर से शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए कृषि की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। (प्रेट्र)

फेडरल रिजर्व के फैसले पर रहेगी निवेशकों की नजर

विशेषज्ञ बोले, इस सप्ताह अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती तय, इससे भारत जैसे उभरते बाजारों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह निवेशकों की नजरें अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर रहेंगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि यदि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो इससे डालर में कमजोरी आएगी और बांड पर यील्ड घटेगा। ब्याज में कटौती भारत जैसे उभरते वैश्विक बाजारों के लिए एक सकारात्मक कदम होगी और बाजार नए रिकार्ड स्तर पर पहुंच सकते हैं। फेडरल रिजर्व के बाद आरबीआइ भी अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है।

स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड के शोध प्रमुख संतोष मीणा का कहना है कि इस सप्ताह साल का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक 18 सितंबर को होगी। यह लगभग तय है कि इससे ब्याज दर में कटौती चक्र की शुरुआत होगी। अमेरिका में आम सहमति ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती को लेकर है। हालांकि, कुछ बाजार भागीदार दरों में आधा प्रतिशत की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। ब्याज में कटौती से भारतीय शेयर बाजार में संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) का प्रवाह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जापान के मुद्रास्फीति आंकड़े शुक्रवार को आने हैं, जिसके बाद बैंक आफ जापान (बीओजे) मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा।

मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की निदेशक पल्का अरोड़ा चोपड़ा ने कहा कि बाजार का परिदृश्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों मसलन भारत की थोक महंगाई दर, अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन, अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ब्याज दर पर निर्णय तथा अमेरिका के बेरोजगारी दावों के आंकड़ों से तय होगा।

- 18 सितंबर को होगी अमेरिका के केंद्रीय बैंक के फैसले की घोषणा
- ब्याज दरों में 0.25 या 0.50 प्रतिशत तक की हो सकती है कटौती

ब्याज दरों में कटौती से भारत में विदेशी निवेश में होगी बढ़ोतरी

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार का कहना है कि बीते सप्ताह एफआइआइ ने सभी दिन खरीदारी की है। इसके दो कारण है कि एफआइआइ ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहला कारण यह है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू होने वाले है जिससे अमेरिकी बांड पर यील्ड घट जाएगा। इससे उभरते बाजारों में निवेश बढ़ेगा। दूसरा कारण यह है कि भारतीय बाजार काफी लचीले हैं। यदि एफआइआइ यहां निवेश नहीं करते हैं तो यह एक खराब रणनीति होगी।

बीते सप्ताह पहली बार 83 हजार के पार पहुंचा था सेंसेक्स

बीता सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों के लिए काफी बेहतर रहा है। गत गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। इसी दिन बीएसई के मानक सूचकांक सेंसेक्स ने पहली बार 83 हजार अंक के स्तर को पार किया था। बीते सप्ताह सेंसेक्स में 1,707.01 अंक और निफ्टी में 504.35 अंक की बढ़ोतरी रही थी।

नौ कंपनियों का पूंजीकरण दो लाख करोड़ रुपये बढ़ा

बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में रही तेजी का असर कंपनियों के बाजार पूंजीकरण पर भी दिखा है। इस दौरान बीएसई में सूचीबद्ध शीर्ष-10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी रही है। बीते सप्ताह भारती एयरटेल के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 54,282.62 करोड़ रुपये की वृद्धि रही। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), हिंदुस्तान यूनीलिवर, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आइटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसबीआइ के पूंजीकरण में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर, एलआइसी के पूंजीकरण में गिरावट रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष पर बनी हुई है।

जल्द 700 अरब डालर के पार होगा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार : जेफरीज

नई दिल्ली, आइएएनएस : वैश्विक फर्म जेफरीज ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक आर्थिक बाधाओं और भूराजनीतिक तनाव के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अनुमान से पहले 700 अरब डालर के पार पहुंच जाएगा। छह सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 689.235 अरब डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा है। कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 66 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। जेफरीज का कहना है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अब भारतीय रुपया सबसे ज्यादा स्थिर मुद्रा बना हुआ है। इस समय भारत को घरेलू और विदेशी मोर्चे से मजबूत निवेश मिल रहा है। सितंबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआइ) इक्विटी बाजारों में 27,856 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं। डेट बाजारों में भी एफपीआइ निवेश बढ़ा है। 2024 में अब तक इक्विटी में एफपीआइ निवेश 70 हजार करोड़ और डेट बाजारों में एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

जीवन बीमा प्रीमियम पर कर की दर के लिए जीओएम गठित

नई दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा प्रीमियम पर लगने वाले कर की समीक्षा के लिए रविवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन कर दिया। यह समूह 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस 13 सदस्यीय जीओएम का संयोजक बनाया गया है। जीओएम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। अभी सभी प्रकार के बीमा प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जीओएम की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर में होने वाली बैठक में जीएसटी काउंसिल कर की दरों पर फैसला करेगी। वहीं, एक अधिकारी ने बताया कि वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर काम कर रहे मंत्री समूह (जीओएम) के संयोजक हो सकते हैं। इसमें राज्यों के सदस्य भी शामिल होंगे।

नकदी जरूरतों के लिए मुद्रा प्रबंधन ढांचे में सुधार करेगा आरबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरबीआइ अपने मुद्रा प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार करने की योजना बना रहा है। यह सुधार अगले 4-5 वर्षों के दौरान किए जाएंगे। इन सुधारों का उद्देश्य बढ़ती अर्थव्यवस्था की भविष्य की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण और प्रबंधन क्षमता सुनिश्चित करना है। आरबीआइ ने इसके लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं को लेकर रुचि पत्र (ईओआइ) भी आमंत्रित किए हैं।

ईओआइ के अनुसार, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अत्याधुनिक मुद्रा प्रबंधन केंद्रों का निर्माण, गोदाम स्वचालन की शुरुआत, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों की स्थापना, एक भंडार प्रबंधन प्रणाली और एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र पर विचार किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बीते तीन वर्षों के दौरान चलन में मुद्रा (एनआइसी) की वृद्धि दर में नरमी रही है। इसके बावजूद एक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में चलन में मुद्रा में वृद्धि सकारात्मक रहेगा। हालांकि, अगले दशक में इसकी गति धीमी रहने की उम्मीद है।

आरबीआइ के अनुसार, 31 मार्च 2024 को 136.21 अरब नोट चलन में थी, जिनकी संख्या 31 मार्च 2024 को बढ़कर 146.87 अरब हो गई है। चलन में मौजूद सिक्कों की संख्या भी बढ़ी है।

- आरबीआइ ने कहा, निकट भविष्य में चलन में मुद्रा की वृद्धि सकारात्मक रहेगी
- 146.87 अरब नोट चलन में थे 31 मार्च 2024 को, सिक्कों की संख्या भी बढ़ी

किराये में वृद्धि व कंटेनर की कमी चिंताजनक

नई दिल्ली, प्रेट्र : आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) का कहना है कि माल की बढ़ती ढुलाई लागत और कंटेनर की कमी भारतीय निर्यात के लिए काफी चिंताजनक है और यह गंभीर चुनौतियां पेश कर रहे हैं। भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

जीटीआरआइ के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत घरेलू कंटेनर उत्पादन को बढ़ावा देकर, स्थानीय स्तर पर निर्मित कंटेनर के उपयोग को प्रोत्साहित करके और माल परिवहन के लिए भारतीय कंपनियों के उपयोग को बढ़ाकर वैश्विक सप्लाई चेन व्यवधान के अपने जोखिम को कम कर सकता है। साल 2022 और 2024 के बीच, 40 फिट वाले कंटेनर के लिए निर्यात दरों में काफी उतार-चढ़ाव आया है। जीटीआरआइ ने कहा है कि वर्ष 2022 में कोरोना महामारी के चलते औसत निर्यात लागत 4,942 डालर थी। 2024 तक यह दर 4,775 डालर के आसपास स्थिर हो गई थी। ये दरें अब भी महामारी से पहले के स्तार से काफी अधिक हैं। 2019 में यह लागत 1,420 डालर थी।

श्रीवास्तव ने कहा कि माल ढुलाई की ज्यादा दरें सप्लाई चेन की लगातार चुनौतियों को दर्शाती हैं, जो वैश्विक व्यापार पर बोझ बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा अमेरिका और यूरोप को अपने निर्यात को अधिकतम करने के लिए कंटेनर की जमाखोरी करने की भी अपुष्ट खबरें हैं।

आशंका है कि संभावित व्यापार प्रतिबंधों और चीन या अन्य देशों में स्थित चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, इस्पात और एल्युमीनियम पर शुल्कों में वृद्धि से पहले ये जमाखोरी की गई है।

जीटीआरआइ ने कहा, भारतीय निर्यात के लिए यह बड़ी चुनौती, इससे निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता

बीते एक वर्ष में दोगुना हुई माल ढुलाई की लागत

लाल सागर संकट के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए बीते एक वर्ष में यूरोप और अमेरिका के लिए माल ढुलाई की लागत दोगुना से ज्यादा हो गई है। जीटीआरआइ का कहना है कि यदि आने वाले महीनों में अमेरिका व चीन के बीच ट्रेड वार बढ़ता है तो भारतीय निर्यातकों को एक और व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है।

भारी छूट से त्योहारों में वाहन व इलेक्ट्रानिक्स की बिक्री बढ़ी

नई दिल्ली, आइएएनएस : चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में आटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की बिक्री में नरमी रही है। अब गणेश चतुर्थी और ओणम के साथ त्योहारी सीजन शुरू होते ही कार, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कंपनियों की ओर से दी जा रही भारी छूट और विभिन्न प्रोत्साहनों के कारण बिक्री बढ़ी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, ओणम, नवरात्र, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों को देखते हुए इलेक्ट्रानिक्स, आटोमोबाइल और स्मार्टफोन कंपनियों अपने ग्राहकों को 30 प्रतिशत तक की छूट दे रही हैं। ओणम से पहले केरल में मारुति सुजुकी की बुकिंग में 10 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसी तरह, गणेश चतुर्थी के पहले दिन मारुति के वाहनों की डिलिवरी में महाराष्ट्र और कर्नाटक में 10 प्रतिशत बढ़ी है। ओणम के दौरान दोपहिया की बिक्री में 15-16 प्रतिशत की वृद्धि रही है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में यात्री वाहनों की औसत मासिक बिक्री 3.30 लाख इकाई रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, त्योहारी सीजन में यात्री वाहनों की बिक्री इससे 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। वहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों की बिक्री में 7-8 प्रतिशत की वृद्धि रह सकती है। हाल ही में एनएलबी सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा था कि त्योहारी सीजन में 10 लाख से ज्यादा अस्थायी नौकरियां सृजित हो सकती हैं।

- 30% तक छूट दे रही हैं आटो और इलेक्ट्रानिक्स कंपनियां
- ओणम के दौरान दोपहिया की बिक्री 15-16 प्रतिशत तक बढ़ी

राष्ट्रीय फलक

जब तक आखिरी भेड़िया नहीं पकड़ा जाता तब तक टीमें रहेंगी

जागरण संवाददाता, बहराइच

- भेड़ियों के हमले से प्रभावित बहराइच पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- बोले- जंगल में पानी भरने के बाद बढ़ा आबादी क्षेत्र में खतरा

भेड़ियों के हमलों से प्रभावित उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के महसी क्षेत्र में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने के साथ सभी को आश्वस्त किया कि जब तक जंगली जानवरों का खतरा रहेगा तब तक वन व अन्य विभागों की टीम यहां से नहीं हटेंगी। साथ ही कहा कि जंगल में पानी भर गया है। ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों का खतरा आबादी क्षेत्र में बढ़ जाता है। शिकार की तलाश में वे मानव बस्ती के बीच आ जाते हैं। जिला प्रशासन, पुलिस, वन विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधि समन्वय बनाकर हमले के नियंत्रण में लगे हैं।

महसी के सर्वाधिक प्रभावित गांव सिसैया चूरामणि पहुंचे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने भेड़िये के हमले में मृत व घायलों के परिवारवालों को राहत सामग्री सौंपी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान चलाकर, कैंप लगाकर पात्रों को आवास, शौचालय, राशन कार्ड दिलाए जाएंगे। आमजन की सेवा और सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेड़ियों के हमलों में अब तक आठ लोगों की जान गई है। पांच भेड़िये पकड़े गए हैं। एक अब भी पकड़ से बाहर है।

पहली सितंबर को अंतिम घटना घटी थी। इसके बाद जनहानि की सूचना नहीं है। दो-तीन सितंबर को एक बच्चे पर हमले की सूचना थी। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हिंसक भेड़िये को मारने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यह अंतिम विकल्प है। 165 टीमें वन विभाग की लगी हैं। पहली प्राथमिकता भेड़िये को पकड़ना है।

बहराइच में महसी के सिसैया चूरामणि में प्रेस वार्ता करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

जिनके घर खुले, वहां लगवाए जा रहे दरवाजे

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके परिवार में हमले हुए हैं, उनमें अधिकांश के आवास तो बने हैं, लेकिन उनमें दरवाजे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में लोग घर के बाहर लेटते थे। इस वजह से भी दुर्घटनाएं हुईं। अब दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। यहां 712 परिवारों को शौचालय दिए गए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे आवास न मिला हो, उसे आवास दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास एवं शौचालय के मद्देनजर सभी गांवों का सर्वे किया गया है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ व यहां की स्थितियों का जायजा भी लिया। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की।

अब हमीरपुर में लकड़बग्घों का हमला, मार डालीं 26 भेड़ें

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ, बहराइच में भेड़िया व सुलतानपुर में सियारों के हमले के बाद अब हमीरपुर में लकड़बग्घों ने हमला किया है। शनिवार रात लकड़बग्घों के झुंड ने पशुबाड़े में घुसकर 26 भेड़ों को मार डाला। भेड़ों के शव गांव के बाहर तक पड़े मिले। वन विभाग की टीम ने पग चिह्न का परीक्षण कराकर लकड़बग्घों के होने की पुष्टि की है। इनकी संख्या तीन से चार होने का अंदेशा है। लकड़बग्घों को पकड़ने के लिए पांच सदस्यीय टीम बनाई गई है। ग्रामीणों के अनुसार आसपास जंगली क्षेत्र जरूर है, पर लकड़बग्घे होने की बात पहली बार सामने आई है। जिले के पाटनपुर गांव निवासी जयवीर व शिववीर शनिवार शाम भेड़ों को चराने के बाद पशुबाड़े में बांधकर घर चले गए। छोटे भाई शिववीर खाना खाने के बाद पशुबाड़े वाले मकान में ही पीछे के हिस्से में बने कमरे में सो रहे थे।

बिहार से सिलीगुड़ी जा रही ट्रेन के इंजन में लगी आग

बिहार में ट्रेन के इंजन में लगी आग को बुझाते अग्निशमन दस्ता। जागरण

जासं, किशनगंज : बिहार से सिलीगुड़ी जा रही डीएमयू (डीजल मल्टीपल यूनिट) के इंजन में रविवार दोपहर आग लग गई। चालक ने धुआं देख इमरजेंसी ब्रेक लगाई। सूचना मिलते ही ट्रेन में सवार उतरने लगे। रेलकर्मियों, घटनास्थल पर मौजूद एसएसबी के जवान व अग्निशमन दस्ता ने डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीच ट्रैक पर ट्रेन के खड़ी होने के बाद करीब डेढ़ घंटे तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इंजन में तकनीकी खराबी के कारण घटना हुई है।

आनलाइन गेमिंग से निपटने के लिए बन सकती है अंतर-विभागीय समिति

नयी दिल्ली, प्रेट्र : जीएसटी खुफिया महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार आनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों से निपटने के लिए अंतर-विभागीय समिति गठित की जा सकती है। इस समिति में ईडी, आरबीआइ, कर और उपभोक्ता मामलों के विभागों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। गेमिंग कंपनियों को कर के दायरे में लाना कठिन कार्य बना हुआ है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की जीएसटी खुफिया शाखा ने 118 घरेलू आनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। 34 करदाताओं को 1,10,531.91 करोड़ की कर राशि के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। इन गेमिंग कंपनियों को नोटिस इसलिए जारी किए गए क्योंकि वे जीएसटी भुगतान नहीं कर रही थीं। 167 यूआरएल/वेबसाइटों को ब्लाक करने की सिफारिश की गई है। ऐसी कई कंपनियां माल्टा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप, साइप्रस जैसे टैक्स हैवन देशों में बनाई जाती हैं, जिससे कंपनियों के मालिक का पता लगाना मुश्किल होता है।

धान की जगह दूसरी फसलें उगाने से ऊपर आ जाएगा भूजल स्तर

प्रेट्र, नई दिल्ली : अगर उत्तर भारत में कुल धान की खेती के 40 प्रतिशत हिस्से पर भी दूसरी फसलें उगाई जाएं तो तेजी से नीचे जा रहे भूजल स्तर को ऊपर लाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार इससे वर्ष 2000 के बाद समाप्त हुए 60-100 क्यूबिक किलोमीटर भूगर्भ जल को हासिल किया जा सकता है। फसलों का पैटर्न बदलने से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। इससे इन राज्यों में भूजल के स्तर को ऊपर लाने और किसानों को खेती से लाभ सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

शोधकर्ताओं के एक दल का कहना है कि फसलों के मौजूदा पैटर्न में धान का दबदबा है। धान की खेती में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर धान की जगह पर दूसरी फसलों को नहीं अपनाया गया और धरती का तापमान बढ़ता रहा तो करीब 13-43 क्यूबिक किलोमीटर भूगर्भ जल समाप्त हो सकता है। दल में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी गांधीनगर के शोधकर्ता भी शामिल थे। शोधकर्ताओं के अनुसार फसलों के मौजूदा पैटर्न के बजाए पानी की कम खपत करने वाले फसलें उगाने से जलवायु परिवतर्न की वजह से सूखा पड़ने के दौरान भूगर्भ जल की ज्यादा बचत की जा सकेगी। अध्ययन के निष्कर्षों का उपयोग उत्तर भारत में भूगर्भ जल का स्तर बहाल करने के लिए अनुकूल फसलों के पैटर्न की पहचान करने और किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने में मददगार नीतियां बनाने में किया जा सकता है। फसलों का पैटर्न बदलने से भूगर्भ जल पर प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए शोधकर्ताओं के दल ने दो तरह के परिदृश्य का आकलन किया। पहले परिदृश्य में धान की खेती के क्षेत्र को पांच प्रतिशत घटाया गया और दूसरे परिदृश्य में धान की खेती के अतिरिक्त 37 प्रतिशत क्षेत्र में अनाज, दालों और तिलहन की खेती को अपनाया गया। इस तरह से कुल धान की खेती के कुल क्षेत्र को 42 प्रतिशत तक घटाया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि पहले परिदृश्य में 2002-2022 की अवधि में 45 क्यूबिक किलोमीटर भूगर्भ जल बचाया जा सकता था, वहीं दूसरे परिदृश्य में समान अवधि में 91 क्यूबिक किलोमीटर भूगर्भ जल बचाया जा सकता था। इसके अलावा अनुमान है कि पहले परिदृश्य में किसानों का मुनाफा 13.5 प्रतिशत बढ़ सकता था, वहीं धान का उत्पादन में गिरावट नहीं आती।

- फसलों का पैटर्न बदल कर हासिल कर सकते हैं 60-100 क्यूबिक किलोमीटर भूगर्भ जल
- धान की खेती कम करने से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को होगा ज्यादा फायदा

****

एक ही पाइप लाइन से नेपाल को डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति करेगा भारत

संजय कुमार उपाध्याय

जागरण : मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) : इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बिहार में छपरा बहास डिपो से शीघ्र नेपाल को पेट्रोल की भी आपूर्ति होगी। यह देश का पहला ऐसा डिपो होगा, जो एक ही पाइप लाइन के जरिए डीजल व पेट्रोल, दोनों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। पूर्वी चंपारण जिले के छपरा बहास से भारत-नेपाल के बीच तैयार मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन से फिलहाल डीजल की आपूर्ति हो रही है। दूसरे चरण में पेट्रोल की भी आपूर्ति के लिए निर्माण अंतिम दौर में है। अगले दो महीने में पेट्रोल की भी आपूर्ति शुरू करने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगी है। छपरा बहास डिपो के विस्तार की भी कवायद तेज हो गई है। करीब 17 एकड़ अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही। जिला भू-अर्जन कार्यालय ने भूमि चिह्नित करने के बाद राशि आवंटित करने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन को पत्र भेजा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, यहां एक साथ कई सुविधाएं बढ़ेंगी। उनमें एक खास उपलब्धि यह होगी कि यहां एयर टरबाइन फ्यूल भी उपलब्ध होगा। यह पहला अवसर होगा, जब चंपारण हवाई जहाज के लिए ईंधन उपलब्ध करा सकेगा। दूसरी ओर, नेपाल आयल कारपोरेशन लिमिटेड भी दूसरे चरण के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी कर रहा है।

भारत-नेपाल के बीच छपरा बहास से नेपाल के बारा जिले के अमलेखगंज के बीच 69 किलोमीटर लंबी मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइप लाइन के जरिए 250 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति प्रति घंटे की जा रही है।

- पूर्वी चंपारण जिले के छपरा बहास में इंडियन आयल का देश का पहला ऐसा डिपो, जहां यह व्यवस्था
- अभी नेपाल को डीजल की आपूर्ति, हवाई जहाज के लिए भी यहां मिल सकेगा ईंधन

इस तरह होगा पंजीकरण

प्रथम पृष्ठ से आगे

पंजीकरण के लिए डाक्टरों को अपनी आधार आइडी, एमबीबीएस डिग्री की डिजिटल प्रति और उस राज्य चिकित्सा परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, जहां डाक्टर पहली बार पंजीकरण कराया था। डाक्टर अपने योग्यता के बारे में अतिरिक्त जानकारी मैनुअली भी दर्ज कर सकेंगे। आवेदन सत्यापन के लिए आटोमेटिक तरीके से संबंधित एसएमसी तक पहुंचेगा। एसएमसी आवेदन को समीक्षा के लिए संबंधित कालेज या संस्थान को भजेगा। सत्यापन के बाद आवेदन एनएमसी भेजा जाएगा। एनएमसी के सत्यापन के बाद विशिष्ट एनएमआर आइडी जारी की जाएगी। इस दौरान, डाक्टर हेल्थकेयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, जो उन्हें व्यापक डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम से जोड़ेगा। इस पोर्टल के माध्यम से एसएमसी और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी हितधारक एक ही प्लेटफार्म से लाग इन और आवेदनों का सत्यापन कर सकते हैं।

5.6 लाख बच्चों को गाजा में पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। यह वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सौजन्य से लगवाई जा रही हैं।

दो हजार किमी दूर इजरायल पहुंची हाउती की मिसाइल, नेतन्याहू बोले- जबाव देंगे

हाउती ने कहा, हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक पाईं इजरायल की 20 मिसाइलें

पीएम नेतन्याहू ने कहा, यमनी संगठन को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है

यरुशलम, रायटर : यमन के उत्तरी हिस्से पर कब्जा किए ईरान समर्थित हाउती विद्रोहियों की दागी मिसाइल रविवार को पहली बार इजरायल के मध्य भाग तक पहुंची। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके इजरायल के भीतर आई है। इस मिसाइल से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। गाजा में चल रहे युद्ध के बीच हाउती ने कई बार इजरायल पर हमले की कोशिश की लेकिन पहली बार उनकी मिसाइल इजरायल के मध्य भाग तक आई।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हाउती विद्रोहियों को इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही इजरायली सेना यमन में एक बड़े एयरस्ट्राइक को अंजाम दे सकती है।

हाउती के प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा है कि संगठन ने नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जिसने 2,040 किलोमीटर की दूरी महज 11 मिनट 30 सेकेंड में तय की। प्रवक्ता की बताई दूरी से शक होता है कि हाउती ने यमन की जमीनी सीमा के बाहर किसी स्थान से इजरायल की ओर मिसाइल दागी थी। हाइपरसोनिक मिसाइल छह से बारह हजार किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लक्ष्य तक जाती है। इजरायली आकाश में मिसाइल के आते ही इजरायल में अफरातफरी मच गई और सतर्क करने वाले सायरन बजने लगे, लोग भागकर भूमिगत ठिकानों में जा छिपे। हाउती की मिसाइल के टुकड़े मध्य इजरायल में रेलवे स्टेशन के नजदीक के खुले स्थान पर मिले हैं। अनुमान है कि मिसाइल आकाश में ही फट गई थी। संभावना है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने नष्ट किया। हाउती के जनसंपर्क कार्यालय ने कहा है कि उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायल ने 20 मिसाइलें छोड़ीं लेकिन वे विफल रहीं।

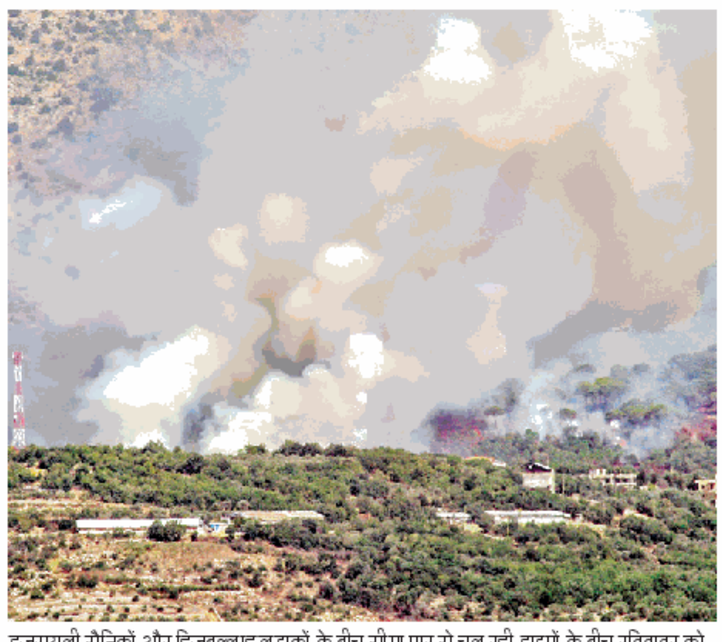

इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच सीमा पार से चल रही झड़पों के बीच रविवार को दक्षिणी लेबनान के गांव रशाया अल-फखर के बाहरी इलाके में इजरायली हमले के बाद उठता धुएं का गुबार। एएफपी

इजरायल के हवाई हमले में 21 फलस्तीनी मारे गए

यरुशलम, आइएएनएस : गाजा में रविवार को इजरायल के हवाई हमलों में 21 फलस्तीनी मारे गए। गाजा सिटी में हुए दो हमलों में 15 लोग मारे गए हैं जबकि बाकी के छह अन्य स्थानों पर मारे गए। गाजा युद्ध में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या 41,182 हो गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि कुछ महीने पूर्व उसे जो तीन बंधकों के शव मिले थे, संभव हैं कि उनकी मौत इजरायल के हवाई हमले में ही हुई थी। मारे गए लोगों को सात अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमला करके हमास लड़ाकों ने बंधक बनाया था।

शिक्षा पर भारतीय योजना को अपनाए पाकिस्तान : एडीबी

एडीबी अध्यक्ष की पाकिस्तान की निर्धारित यात्रा से पहले आई यह सलाह

इस्लामाबाद, प्रेट्र : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान को अपनी खराब शिक्षा प्रणाली को ठीक करने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत की योजना उल्लास को अपनाने की सलाह दी है। मनीला स्थित ऋणदाता की यह सिफारिश पाकिस्तान द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार करने और स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के अनुरोध के जवाब में आई है।

गैर-साक्षरों और औपचारिक स्कूली शिक्षा से चूक गए वयस्कों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा पिछले साल जुलाई में अंडरस्टैंडिंग आफ लाइफलांग लर्निंग फार आल इन सोसाइटी (उल्लास) की शुरुआत की गई थी। ऋणदाता के अनुसार, एडीबी की सिफारिश है कि सरकार एक रणनीतिक और बहु-हितधारक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाए, जो भारत सरकार की नई केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास जैसी सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाए।

एडीबी ने इस बात पर जोर दिया कि उल्लास योजना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों को तत्काल सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर देती है। भारतीय योजना का उद्देश्य न केवल मूलभूत साक्षरता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिकों के लिए अन्य आवश्यक घटकों जैसे वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल को भी शामिल करना है। यहसिफारिश एडीबी अध्यक्ष मासत्सुगु असाकावा की पाकिस्तान की यात्रा से कुछ दिन पहले आई है।

पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति : पाकिस्तान के योजना आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला है कि देश की शिक्षा वितरण प्रणाली बेकार है। इस्लामाबाद को छोड़कर, सभी 134 जिले सीखने के परिणामों से लेकर सार्वजनिक वित्तपोषण तक के संकेतकों में पिछड़ रहे हैं। योजना आयोग द्वारा जारी जिला शिक्षा प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में पाकिस्तान में मानव संसाधन संकट को उजागर किया गया है।

पीएम मोदी ने दी है उल्लास योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सभी के लिए शिक्षा' देने के इरादे से पांच साल की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित उल्लास योजना को मंजूरी दी थी। भारतीय योजना का उद्देश्य केवल बुनियादी साक्षरता प्रदान करना नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के लिए नागरिकों का निर्माण करना है, जिनमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल समेत महत्वपूर्ण स्किल भी हो।

पाकिस्तान में न्यायपालिका के पर कतरने की तैयारी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान में न्यायपालिका के पर कतरने की तैयारी हो रही है। सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने विवादास्पद संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए समर्थन मांगने के लिए रविवार को कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की।

संशोधनों का विवरण अभी साझा नहीं किया गया है। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उससे पता चला है कि सरकार जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तय करने की योजना बना रही है।

इसके अलावा, शीर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता सिद्धांत को संशोधित करने पर भी विचार कर रही है। साथ ही एक संवैधानिक न्यायालय बनाना चाहती है और संविधान के अनुच्छेद 63-ए में संशोधन करना चाहती है, जो सांसदों के दलबदल से संबंधित है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदियाला जेल से अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए संदेश में कहा है कि सरकार कथित तौर पर न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कानूनों में बदलाव की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के उल्लंघन और चुनावी धोखाधड़ी की पारदर्शी जांच से बचने के लिए संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईशा को लाने का प्रयास किया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

बांग्लादेश को 20.2 करोड़ डालर की सहायता देगा अमेरिका

ढाका : बांग्लादेश के तख्तापलट में अमेरिका का हाथ होने के आरोपों के बीच एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश को 20.2 करोड़ डालर की सहायता देने की बात कही है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ट्रेजरी विभाग के उप अवर सचिव ब्रेंट नीमन ने किया। ढाका पहुंचे दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक सचिव डोनाल्ड लू भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए। पिछले हफ्ते बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा था कि सरकार अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए पांच अरब डालर की मदद की अपील करती है। (रायटर)

नाइजीरिया में नौका डूबने से 41 की मौत, 12 बचाए गए

अबुजा : नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत जंफारा में लकड़ी की नौका डूब जाने से 41 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य को बचा लिया गया। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 41 शव निकाल लिए गए हैं। 50 से ज्यादा सवारों के साथ नौका शनिवार को रवाना होने के थोड़ी देर बाद ही गुम्मी कस्बे के समीप नदी में डूब गई। संघीय प्रतिनिधिसभा में गुम्मी-बुक्कुयुम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सुलेमानी गुम्मी ने कहा कि नौका में सवार सभी लोग किसान थे। अपने खेत तक जाने के लिए किसान रोज नौका से यात्रा करते हैं। (आइएएनएस)

हैती में पेट्रोल टैंकर विस्फोट में 24 लोग मारे गए

पोर्ट औ प्रिंस : हैती के दक्षिणी प्रायद्वीप पर शनिवार को हुए तेल टैंकर विस्फोट में 24 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हैती के प्रधानमंत्री गैरी कोनिले ने तटवर्ती शहर मिरागोआने के समीप दुर्घटनास्थल का दौरा किया। गंभीर रूप से घायल कुछ पीड़ितों को विशेष देखभाल के लिए हेलीकाप्टर से निकाला गया। कोनिले ने कहा कि दर्जनों पीड़ित गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हैती आपात सेवा ने बताया कि घायलों में तीन महिलाओं और एक बच्चे के साथ ही ज्यादातर पुरुष हैं। (रायटर)

मिस्र में ट्रेनों के बीच टक्कर में दो की मौत, 29 घायल

काहिरा : मिस्र के शरकिया प्रांत के जगाजिग शहर में दो ट्रेनों के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और 29 अन्य घायल हो गए। मिस्र रेलवे प्राधिकरण ने बताया है कि जगाजिग से इस्माइलिया जा रही ट्रेन संख्या 281 और मंसूरा से जगाजिग आ रही यात्री ट्रेन संख्या 336 के बीच जगाजिग शहर में ब्लाक पांच के पास शनिवार दोपहर टक्कर हो गई। (एएनआइ)

घायल होने के 40 दिन बाद बलूच प्रदर्शनकारी की मौत

क्वेटा : प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में घायल बलूच प्रदर्शनकारी हिकमतुल्ला बलूच की लगभग 40 दिन बाद कराची में मौत हो गई। नुश्की में 28 जुलाई को फायरिंग में हिकमतुल्ला के गले में गोली लगी थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कार्यकर्ताओं एवं बलूच अधिकार संगठनों ने बलूच समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई है। पहले भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की अंधाधुंध फायरिंग में निर्दोष लोग घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। (एएनआइ)

भारत और मालदीव ने अपने मतभेद सुलझा लिए हैं...

द्वीपीय देश के विदेश मंत्री जमीर ने माना-कुछ गलतफहमियां थीं

माले, प्रेट्र : भारत और मालदीव ने कुछ गलतफहमियों के बाद अब अपने मतभेद सुलझा लिए हैं। ये मतभेद राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू सरकार के शुरुआती दिनों में पैदा हुए थे। यह बात मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने श्रीलंका यात्रा के दौरान कही है।

मालदीव के विदेश मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के पड़ोसी देशों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए भारत और चीन से मजबूत रिश्तों की इच्छा जताई। कहा, मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर भारत के साथ उनके देश के संबंधों में थोड़ी कटुता पैदा हुई थी लेकिन सैनिकों की वापसी के बाद अब वह खत्म हो गई है। एक अखबार से साक्षात्कार में जमीर ने स्वीकार किया कि मुइज्जू सरकार के शुरुआती दिनों में भारत के साथ संबंधों में कटुता आ गई थी। लेकिन अब भारत और चीन के साथ मालदीव के अच्छे रिश्ते हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का नारा लगाने के बाद जब मुइज्जू राष्ट्रपति बने और कुछ ही घंटे बाद मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए कहा तो दोनों देशों के संबंधों में कटुता पैदा हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों की वार्ता में बनी सहमति पर सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक सेवा के कर्मियों की मालदीव में नियुक्ति हुई। भारत ने पूर्व में मालदीव को विभिन्न सुविधाओं में उपयोग के लिए तीन हेलीकाप्टर और विमान उपहार स्वरूप दिए थे। उन्हीं के संचालन के लिए वहां पर सैन्यकर्मी तैनात थे।

मुइज्जू सरकार ने कहा, भारत व चीन के साथ अच्छे संबंधों के हैं इच्छुक

इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश में आठ लोगों की मौत

पेरिस, रायटर : उत्तरी फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने के असफल प्रयास के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार आधी रात से पहले हुई, जब अधिकारियों ने एम्बलेट्यूज में एक समुद्र तट के पास एक नाव को संकट में देखा था। इसमें दर्जनों लोग सवार थे। पास-डी-कैलाइस क्षेत्र के प्रीफेक्ट जैक्स बिलेंट ने कहा कि बचाव दल को सतर्क कर दिया गया था कि क्षेत्र में एम्बलेट्यूज के तट पर 59 लोगों के साथ एक नाव मुश्किल में थी। जहाज पर सवार अन्य 51 अब बचाव और चिकित्सा दल की देखभाल में हैं। मरने वाले इरिट्रिया सूडान, सीरिया, मिस्र, ईरान और अफगानिस्तान के रहने वाले थे। इंग्लिश चैनल दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है और धाराएं तेज हैं, जिससे छोटी नावों पर पार करना बेहद खतरनाक साबित होता है। वर्ष की शुरुआत से फ्रांस से चैनल पार करने की कोशिश में मरने वाले लोगों की संख्या 46 हो गई है।

रूस के हमले में नौ यूक्रेनियों की मौत, 33 घायल

यूक्रेन का दावा, रूस के 10 ड्रोन व तीन मिसाइलों को मार गिराया

रूस ने भी किया दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में 29 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा

कीव, रायटर : रूस द्वारा यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर शनिवार रात किए मिसाइल हमले में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं रविवार को खार्किव में एक आवासीय इमारत पर रूस की बमबारी में तीन बच्चों सहित 33 लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेंजर एप पर कहा, रूसी हवाई हमला हुआ है। आवासीय बहुमंजिला इमारत, क्षतिग्रस्त हो गई है। बचाव अभियान जारी है। यूक्रेनी वायुसेना ने रविवार को कहा कि उसने रूस के 14 ड्रोनों में से 10 ड्रोनों और शनिवार रात दागी गईं तीन मिसाइलों में से एक को मार गिराया, जबकि बाकी ओडेसा के उपनगरीय इलाके में गिरे। ओडेसा के रीजनल गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा कि शनिवार रात हमले में मरने वाले दोनों दंपती थे। इस बीच, रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में 29 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मलबे गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। यह भी कहा कि रविवार सुबह पश्चिमी रयाजन क्षेत्र में भी यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए।

यूक्रेन के खार्किव में रविवार को रूस द्वारा किए गए हवाई हमले में क्षतिग्रस्त आवासीय इमारत में राहत एवं बचाव कार्य में जुटे दमकलकर्मी। रायटर

यूक्रेन और रूस नियमित रूप से एक-दूसरे के क्षेत्र में रात भर ड्रोन हमले करते हैं, यूक्रेनी अधिकारी आमतौर पर रूस की सीमाओं के भीतर हमलों की पुष्टि या खंडन नहीं करते हैं। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से आह्वान किया कि उसे रूस के अंदर तक लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दी जाए। पूर्वी यूक्रेन में रूस के विरुद्ध उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तक, अमेरिका ने कीव को यूक्रेन के साथ रूस की सीमा के अंदर एक सीमित क्षेत्र में ही अमेरिकी प्रदत्त हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दी है।

हथियार मिलने में देरी से यूक्रेन को हो भारी नुकसान : वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सीएनएन को बताया कि पश्चिमी देशों से हथियार मिलने में देरी से यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी इलाके में स्थिति बहुत कठिन है।

टेक अरबपति जेयर्ड इसाकमैन पहले प्राइवेट स्पेसवाक के बाद पृथ्वी पर लौटे

केप कैनावेरल, एपी : टेक अरबपति अंतरिक्ष यात्री जेयर्ड इसाकमैन रविवार को अपने दल के साथ प्राइवेट स्पेसवाक के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेसएक्स का कैप्सूल फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास के पास मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। इस स्पेसवाक में उद्यमी जेयर्ड इसाकमैन और स्पेसएक्स की कर्मचारी सारा गिलिस शामिल थीं। इससे पहले विभिन्न देशों की सरकारों की ओर से भेजे गए अंतरिक्षयात्रियों ने ही अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी।

स्पेसएक्स के पोलारिस डान मिशन के तहत चार अंतरिक्षयात्री मंगलवार को स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। इनमें इसाकमैन और गिलिस के साथ अमेरिकी वायुसेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल स्काट पोटेट और स्पेसएक्स की एक अन्य कर्मचारी अन्ना मेनन शामिल थीं। पृथ्वी से लगभग 740 किमी ऊपर पहला प्राइवेट स्पेसवाक किया गया। इसाकमैन स्पेसवाक करने वाले 264वें व्यक्ति बन गए हैं। पोलारिस डान मिशन में उपकरणों का परीक्षण किया गया, जिसमें पतले अंतरिक्ष सूट और क्रू ड्रैगन केबिन को पूरी तरह से दबावमुक्त करने की प्रक्रिया शामिल है। इस तकनीक का उपयोग भविष्य के प्राइवेट अंतरिक्ष मिशनों में किया जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है।

फ्लोरिडा के ड्राई टोर्टुगास के तट के पास मैक्सिको की खाड़ी में उतरने के बाद रविवार को स्पेसएक्स के पोलारिस डान मिशन के ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलते टेक अरबपति जेयर्ड इसाकमैन। एएफपी

ताइवान को भूल यूक्रेन पर अमेरिका की अधिक मेहरबानी पर बिफरे वेंस

ताइपेई, एएनआइ : यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य सहायता को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने बाइडन प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अधिक सैन्य मदद दिए जाने से अमेरिका ताइवान को मदद नहीं कर पा रहा है। वेंस ने रूसी आक्रमण के खिलाफ कीव की लड़ाई का समर्थन करने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की नीति की भी आलोचना की।

उन्होंने पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है वाशिंगटन ने ताइवान को बहुत खराब स्थिति में छोड़ दिया है, क्योंकि हमने अपने सभी हथियार यूक्रेन को भेज दिए हैं। बीजिंग देर सवेर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने वाला है। चीन ने कई कारणों से अभी तक ताइवान पर हमला नहीं किया है, इनमें चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित रूप से कमजोर स्थिति शामिल है, लेकिन पांच साल बाद चिनफिंग की स्थिति बेहतर हो सकती है।

चीन विमानवाहक पोत फुजियान के लिए फाइटर जेट का कर रहा परीक्षण

नया विमान लंबे समय से प्रतीक्षित जे-35 हो सकता है, जो चीन का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट

चीन के पास दो विमानवाहक पोत, लियाओनिंग सोवियत काल के जहाज का एक नया संस्करण

बीजिंग, प्रेट्र : चीन अपने तीसरे विमानवाहक पोत फुजियान पर तैनात करने के लिए जे-35 नामक एक नए स्टेल्थ फाइटर जेट (जो रडार की पकड़ में न आए) का परीक्षण कर रहा है।

चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इस साल की शुरुआत में चीनी नौसेना के पहले विमानवाहक पोत लियाओनिंग पर एक नए प्रकार के युद्धक विमान का परीक्षण किया गया था। नया विमान लंबे समय से प्रतीक्षित जे-35 हो सकता है, जो चीन का अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है।

चीन के पास वर्तमान में दो विमानवाहक पोत है। लियाओनिंग सोवियत काल के जहाज का एक नया संस्करण है। वहीं, दूसरा विमानवाहक पोत शेडोंग स्वदेश निर्मित है, जिसे 2019 में कमीशन किया गया था। तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान दोनों से बड़ा है और वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रहा है। यह अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड के समान विद्युत चुम्बकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली (ईएमएएलएस) वाला पहला पूर्ण रूप से घरेलू स्तर पर विकसित और निर्मित विमानवाहक पोत है। यह सिस्टम पारंपरिक स्टीम पिस्टन के बजाय एक लीनियर इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है।

विमानवाहक पोत फुजियान। फाइल

राष्ट्रीय फलक

मथुरा में लूट की कोशिश करने वाली फर्जी ईडी गैंग का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, मथुरा : मथुरा में सराफा कारोबारी अश्वनी अग्रवाल के यहां पिछले दिनों ईडी के अधिकारी बनकर लूटने की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। टीम में दिल्ली की महिला प्रोफेसर शिखा लोचन और उसका लिव-इन पार्टनर देवेंद्र सारस्वत भी शामिल था। पुलिस ने महिला प्रोफेसर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ में सामने आया है कि पूरी साजिश रचने में दिल्ली के गैंगस्टर अमित गोगा का भी पूरा सहयोग था, जिसे पुलिस तलाश रही है।

सराफा कारोबारी के घर फर्जी ईडी की टीम 30 अगस्त को सुबह छह बजे छापा मारने पहुंची थी। टीम में शामिल एक व्यक्ति ने दारोगा की वर्दी पहनी हुई थी। टीम की संदिग्ध गतिविधियां देख अश्वनी कुमार भागकर पड़ोस में रहने वाले महापौर विनोद अग्रवाल के घर पहुंचे थे।

150 गोवंशियों की मौत के मामले में बीडीओ व प्रधान समेत नौ पर केस

जागरण संवाददाता, रायबरेली

- रायबरेली जिले में अस्थायी गोशाल में हुई थी घटना
- न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सरकारी अनुदान से संचालित अस्थायी गोशाला में 150 गोवंशियों की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर धूता ग्राम प्रधान, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), पशु चिकित्साधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व चार-पांच अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। गांव के ही एक व्यक्ति ने इन लोगों पर गोहत्या, तस्करी व षड्यंत्र का आरोप लगाया था।

धूता निवासी उमानाथ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायती पत्र दिया था कि गांव स्थित अस्थायी गोशाला सरकारी अनुदान से संचालित है, जिसमें करीब 1100 गोवंशीय है। आरोप लगाया कि 24 जनवरी, 2024 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में 150 गोवंशियों की मौत हो गई थी, जिसके बारे में प्रधान व संचालन समिति ने किसी को सूचना नहीं दी। मृत गोवंशियों को जंगल में ले जाकर चोरी-छिपे उनका चमड़ा व मांस निकलवाया गया। मामले की शिकायत पुलिस समेत अन्य अधिकारियों से गई तो एसडीएम व पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और वहां मिले औजार व इयरटैग की जांच कराई गई तो मृत गोवंशी गोशाला के ही निकले। आरोप है कि एसडीएम के आदेश के बाद भी मृत गोवंशियों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। यह भी आरोप है कि मामले में डीएम ने प्रधान को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, लेकिन प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया।

युवक की मौत के बाद पूर्व सरपंच का घर फूंका, पुलिस पर हमला

नईदुनिया न्यूज, कवर्धा : छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रेंगाखार थानांतर्गत लोहारीडिह गांव में युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच का घर फूंक दिया। आगजनी में एक व्यक्ति की भी झुलस कर मौत हो गई है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पूर्व सरपंच के परिवार का एक और सदस्य लापता बताया गया है।

उधर, घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिसबल पर पथराव किया, जिसमें एसपी अभिषेक पल्लव समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति नियंत्रित करने के लिए जिलेभर से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस ने इस मामले में 80 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। पुलिस बल की गांव में तैनाती की गई है। पुलिस के अनुसार गांव में रविवार को एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया था।

युवाओं को ठगने के लिए सैन्य क्षेत्र की फोटो के इस्तेमाल की आशंका

जागरण संवाददाता, देहरादून

- महाराष्ट्र से गिरफ्तार भर्ती रैकेट के सरगना ने देहरादून में नहीं बनाया था स्थायी प्रशिक्षण शिविर
- आर्मी इंटेलीजेंस व स्थानीय पुलिस की जांच में फर्जी प्रशिक्षण शिविर के नहीं मिले कोई साक्ष्य

देश में विभिन्न स्थानों पर फर्जी भर्ती प्रशिक्षण शिविर लगाने के आरोप में गिरफ्तार सत्यजीत बरथ कांबले ने देहरादून में स्थायी कैंप नहीं लगाया था। तीन दिन पहले आर्मी इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र पुलिस ने भर्ती रैकेट का पर्दाफाश करते हुए खुद को सेना का मेजर बताने वाले सत्यजीत को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया था। सैन्य सूत्रों के अनुसार, आरोपित ने युवाओं को बरगलाने के उद्देश्य से सैन्य क्षेत्र की फोटो का इस्तेमाल किया था। इन्हीं फोटो को दिखाते हुए उसने युवाओं को उत्तराखंड के देहरादून स्थित मालदेवता क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण शिविर बताते हुए ठगा था। हालांकि, इस बात का भी पता चला है कि वह देहरादून तो आया, लेकिन उसने यहां कोई स्थायी फर्जी प्रशिक्षण शिविर नहीं खोला था। बता दें कि आरोपित उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और नई दिल्ली में अपने गैंग के साथ मिलकर सशस्त्र बलों में नौकरी दिलाने के बहाने सैकड़ों उम्मीदवारों से ठगी कर चुका है। जांच में पता चला कि सत्यजीत बरथ कांबले देशभर में चलाए जा रहे फर्जी भर्ती माड्यूल का सरगना है।

सेना के सूत्रों की मानें तो सेना की इंटेलीजेंस को संदेह था कि कोई पूर्व सैनिक यह रैकेट चला रहा है। इसके बाद वह उसके पीछे दो वर्ष से लगी हुई थी।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
सोमवार 16 सितंबर, 2024
www.jagran.com

रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। उनके पास बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक योजना होती है। वह मैच के दौरान दबदबा बनाने की कोशिश करते रहते हैं।
— उस्मान ख्वाजा, आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

अनमोल ने बेल्जियम में पहला सिंगल्स खिताब जीता

ल्युवेन, प्रेट्र : भारत की 17 वर्षीय अनमोल खरब ने शनिवार को यहां बेल्जियन अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के चुनौतीपूर्ण फाइनल में डेनमार्क की अमाली शुल्ज को हराकर महिला सिंगल्स में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। क्वालीफाइंग चरण से मुख्य दौर में जगह बनाने वाली अनमोल ने 59 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में सातवीं वरीयता प्राप्त प्रतिद्वंद्वी पर 24-22, 12-21, 21-10 से जीत दर्ज की।

एक नजर में

करो या मरो मुकाबले में हारे रामकुमार-बालाजी

स्टाकहोम : रामकुमार रामनाथन और एन श्रीराम बालाजी टुकड़ों में ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए और स्वीडन के विरुद्ध डबल्स के करो या मरो मुकाबले में में आंद्रे गोरानसन और फिलिप बर्गेवी से हार गए। स्वीडन ने भारत के विरुद्ध रविवार को डेविस कप विश्व ग्रुप एक में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल की। शनिवार को दोनों सिंगल्स मुकाबले हारने के बाद भारत को डबल्स मुकाबले में हर हाल में जीत चाहिए थी, लेकिन रामकुमार व बालाजी की जोड़ी को एक घंटे 19 मिनट चले मुकाबले में 3-6, 4-6 से पराजय झेलनी पड़ी। यह उसकी स्वीडन के हाथों छठी हार है। (प्रेट्र)

सलीमा बनीं पाक की पहली अंतरराष्ट्रीय महिला अंपायर

इस्लामाबाद : सलीमा इम्तियाज आइसीसी के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं। पैनल में सलीमा के नामांकन का मतलब है कि अब वह महिलाओं के द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मैचों और आइसीसी की महिला प्रतियोगिताओं में अंपायरिंग करने की पात्र हैं। (प्रेट्र)

कुश मैनी बाल-बाल बचे

बाकू : भारतीय ड्राइवर कुश मैनी रविवार को यहां फार्मूला टू रेस के दौरान एक गंभीर दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। यह भीषण दुर्घटना फार्मूला वन के अजरबैजान ग्रांप्रि से पहले फार्मूला टू रेस के शुरुआती लैप में घटी। इस 23 वर्ष के भारतीय ड्राइवर की कार अचानक रूक गई और पीछे से आ रहे उनके साथी ड्राइवरों जोसेप मारिया मार्टी और ओलिवर गोएथे की कारें उनकी कार से टकरा गईं। इस भीषण दुर्घटना में कुश की कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन वह सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे। (प्रेट्र)

लाहिड़ी 12वें स्थान पर

शिकागो : भारत के अनिर्बान लाहिड़ी शनिवार को यहां दूसरे दौर में एक ओवर 71 के स्कोर से 2024 लिव गोल्फ चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर खिसक गए। लाहिड़ी ने दूसरे दिन दो बर्डी की, लेकिन वह तीन बोगी भी कर गए। दो दिन के बाद उनका कुल स्कोर दो अंडर 36 है। लाहिड़ी ने पहले दौर में शानदार शुरुआत की थी। जान राहम सात अंडर के स्कोर के साथ शीर्ष पर चल रहे हैं। (प्रेट्र)

टूटे हाथ के साथ उतरे थे एक सेंटीमीटर से खिताब चूकने वाले नीरज

ब्रुसेल्स, प्रेट्र : दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने रविवार को बताया कि उन्होंने ट्रेनिंग सत्र के दौरान टूटे हाथ के साथ डायमंड लीग सत्र के फाइनल में हिस्सा लिया। चोपड़ा शनिवार को डायमंड लीग का खिताब जीतने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन एक सेंटीमीटर से चूक गए और लगातार दूसरे वर्ष 87.86 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहे।

नीरज ने प्रतियोगिता के बाद एक्स पर हाथ का एक्सरे पोस्ट किया।

भारतीय स्टार एथलीट चोपड़ा ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल पर कहा, 'सोमवार को अभ्यास के दौरान मैं चोटिल हो गया था और 'एक्स-रे' से पता चला कि मेरे बाएं हाथ की (चौथी मेटाकार्पल) हड्डी में फ्रैक्चर है। यह मेरे लिए एक और दर्दनाक चुनौती थी, लेकिन अपनी टीम की मदद से मैं ब्रुसेल्स में भाग लेने में सफल रहा।' उन्होंने कहा, 'यह वर्ष का अंतिम टूर्नामेंट था। मैं अपनी ही उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सत्र था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पूरी तरह से फिट होकर वापसी कर खेलने के लिए तैयार हूं।' चोपड़ा इस सत्र में फिटनेस से जूझ रहे थे और आशा है कि वह 'ग्रोइन' चोट को ठीक करने के लिए डाक्टर से मिलेंगे जिसने उन्हें पूरे सत्र में प्रभावित किया। अब उन्हें हाथ में नई चोट लग गई है और उन्होंने इसके बारे में अधिक विस्तार से नहीं बताया। सत्र के बारे में उन्होंने कहा, '2024 सत्र समाप्त हो गया है तो मैं वर्ष भर में सीखी गई सभी चीजों को देखता हूं जिसमें सुधार, असफलताएं, मानसिकता और बहुत कुछ शामिल हैं। मैं सभी को प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूं। 2024 ने मुझे एक बेहतर एथलीट और इंसान बनाया है। 2025 में मिलते हैं।'

डायमंड लीग फाइनल में भाग लेकर भारतीय स्टार एथलीट ने साहसिक अंदाज में समाप्त किया सत्र. 87.86 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे

कड़े मुकाबले में ग्रेनाडा के एंडरसन से हारे नीरज

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज केवल एक सेंटीमीटर से खिताब से चूक गए। रोमांचक फाइनल में उन्होंने 87.86 मीटर के थ्रो के साथ लगातार दूसरी बार दूसरा स्थान प्राप्त किया। दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता 26 वर्ष के चोपड़ा ने 2022 में ट्राफी जीती थी। उन्होंने तीसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका, लेकिन विजेता एंडरसन पीटर्स के 87.87 मीटर से एक सेंटीमीटर पीछे रह गए। दो बार के विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के पीटर्स ने पहले ही प्रयास में सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका। जर्मनी के जूलियन वेबर 85.97 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

नीरज चोपड़ा

भारतीय पुरुष टीम ने अजरबैजान महिला ने कजाखस्तान को हराया

शतरंज ओलिंपियाड

बुडापेस्ट, प्रेट्र : विश्व चैंपियनशिप चैलेंजर डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी जैसे दो इन-फार्म सितारों के दम पर भारतीय पुरुषों ने रविवार को यहां 45वें शतरंज ओलिंपियाड के पांचवें दौर में अजरबैजान के विरुद्ध संभावित तीन में से आवश्यक 2.5 अंक प्राप्त कर लिए। वहीं, महिलाओं ने कजाखस्तान को हरा दिया।

भारतीय ग्रैंडमास्टर गुकेश और अर्जुन इस ओलिंपियाड में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कम समय में सफेद मोहरों के साथ क्रमशः आयडिन सुलेमानली और रऊफ मामेदोव को हरा दिया। वहीं, प्रगनानंद ने एक और ड्रा खेला, जिससे भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो गई। शखरियार मामेदयारोव के विरुद्ध विदित गुजराती के परिणाम से भारत की जीत में अंतर नहीं पड़ेगा। लगातार पांचवीं जीत के साथ ही भारतीय पुरुषों ने 10 अंक प्राप्त कर लिए। लीडरबोर्ड पर उनके साथ वियतनाम भी शामिल हो गया है, जिसने पोलैंड को 2.5-1.5 से हराया।

वहीं, महिलाओं में ग्रैंडमास्टर डी हरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वंतिका अग्रवाल ने अलुआ नूरमन के विरुद्ध जीत के साथ वापसी की। जेनिया बालाबायेवा ने दिव्या देशमुख के साथ अंक बांटे। हालांकि, ग्रैंडमास्टर आर वैशाली ने भारत के लिए दूसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अब भारतीय टीम 10 अंकों के साथ अर्मेनिया और मंगोलिया के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है।

कोरियाई चुनौती के लिए तैयार भारत

एशियाई चैंपियंस हाकी ट्राफी का **सेमीफाइनल आज** अब तक भारतीय टीम ने जीते सभी मैच

हुलुनबुइर, प्रेट्र : पेरिस ओलिंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय हाकी टीम सोमवार को एशियाई चैंपियंस ट्राफी के सेमीफाइनल मुकाबले में जब दक्षिण कोरिया के विरुद्ध उतरेगी तो वह जीत की प्रबल दावेदार होगी। गत चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और पांच में से पांच जीत दर्ज की है। भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। खिलाड़ियों ने प्रत्येक विभाग में बेहतर खेल दिखाया है, फिर चाहे अग्रिम पंक्ति हो या मिडफील्ड हो या फिर रक्षण। लीग चरण में भारत के लिए स्ट्राइकरों का प्रदर्शन अद्भुत रहा है।

भारतीय हाकी टीम ● आइ एएनएस

डिफेंस और अटैक बेजोड़ : पेरिस में मैदानी गोल करना भारत के लिए चिंता का विषय था लेकिन सुखजीत सिंह, अभिषेक, उत्तम सिंह, गुरजोत सिंह, अरिजीत सिंह हुंडाल और अन्य की युवा स्ट्राइकरों ने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। युवा मिडफील्डर राज कुमार पाल ने भी कुछ अच्छे मैदानी गोल दागे। इसके अलावा अनुभवी मनप्रीत सिंह, उप कप्तान विवेक सागर प्रसाद और नीलकांत शर्मा ने मिडफील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत का डिफेंस भी दमदार रहा है, जिसने केवल चार गोल गंवाए हैं। वहीं गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा ने टीम को करिश्माई पीआर श्रीजेश के संन्यास से पैदा हुए खालीपन को महसूस नहीं होने दिया।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्रैगफ्लिकर में से एक हरमनप्रीत ने पेरिस की अपनी अच्छी फार्म जारी रखते हुए पांच पेनाल्टी कार्नर को गोल में तब्दील किया। हरमनप्रीत को युवा जुगराज सिंह से अच्छा सहयोग मिल रहा है जो इस समय दुनिया के सबसे तेज ड्रैगफ्लिकर हैं। लेकिन नाकआउट मुकाबला किसी भी टीम के लिए नई शुरुआत होता है, इसलिए भारतीय टीम कोरिया को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकी क्योंकि प्रतिद्वंद्वी टीम का दिन अच्छा रहे तो वह हैरान कर सकती है और उसने मलेशिया के विरुद्ध अंतिम समय में बराबरी हासिल कर 3-3 से ड्रा खेलकर सेमीफाइनल की उम्मीदों को जीवंत रखा था। भारतीय डिफेंस को भी बहुत अधिक पेनाल्टी कार्नर नहीं गंवाने के बारे में सतर्क रहना होगा क्योंकि सात गोल कर चुके टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर जिहुन यांग के रूप में कोरिया के पास एक मजबूत ड्रैगफ्लिकर है।

लीग चरण में भारत का प्रदर्शन

मैच	प्रतिद्वंद्वी	परिणाम
पहला	चीन	3-0
दूसरा	जापान	5-1
तीसरा	मलेशिया	8-1
चौथा	द. कोरिया	3-1
पांचवां	पाकिस्तान	2-1

21 गोल दागे हैं भारतीय टीम ने अब तक अपने लीग मैचों में

4 गोल ही खाए हैं भारत ने प्रतिद्वंद्वी टीमों के विरुद्ध लीग चरण में

आज के मैच

चीन *vs* पाकिस्तान
दोपहर 1:00 बजे | स्थान: हुलुनबुइर

भारत *vs* द. कोरिया
दोपहर 3:30 बजे | स्थान: हुलुनबुइर

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

सात अक्टूबर से बांग्लादेश के विरुद्ध खेली जाएगी तीन मैचों की सीरीज

टी-20 से गिल को दिया जाएगा विश्राम

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय उपकप्तान शुभमन गिल उन प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें बीसीसीआइ की कार्यभार प्रबंधन नीति के तहत बांग्लादेश के विरुद्ध सात अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज से विश्राम दिया जाएगा। टेस्ट मैचों में भारत के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले गिल, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल के साथ टीम के शीर्ष क्रम में अहम खिलाड़ी हैं और उनके इस सत्र में सभी 10 टेस्ट खेलने की उम्मीद है।

न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीन टेस्ट मैचों की सीरीज को ध्यान में रखते हुए गिल के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को भी विश्राम दिया जाएगा। भारत अपने आगामी अंतरराष्ट्रीय सत्र की शुरुआत 19 सितंबर से चेन्नई में बांग्लादेश के विरुद्ध दो टेस्ट मैचों की सीरीज के साथ करेगा, जिसका दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। बीसीसीआइ सूत्रों के अनुसार, हां, शुभमन को बांग्लादेश के विरुद्ध टी-20 सीरीज के लिए आराम दिया जाएगा। अगर आप मैचों की सूची देखें तो तीन टी-20 सात अक्टूबर को ग्वालियर में, 10 अक्टूबर को दिल्ली में और 13 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। फिर न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट 16 अक्टूबर से शुरू होगा। इसलिए सिर्फ तीन दिन के अंतर के कारण गिल को आराम देना महत्वपूर्ण है। मौजूदा सत्र में टी-20 टीम के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण हैं जबकि आस्ट्रेलिया के विरुद्ध पांच मैचों की टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक उसके एजेंडे में ऊपर हैं। इसलिए प्रमुख खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

शुभमन गिल

बांग्लादेश टीम चेन्नई पहुंची, शांतो को अच्छे प्रदर्शन का भरोसा

चेन्नई : पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी बांग्लादेश की टीम रविवार को भारत पहुंच गई। बांग्लादेश की टीम दो टेस्ट व तीन टी-20 मुकाबले खेलेगी। कप्तान नजमुल हसन शांतो ने आने वाले सप्ताह में टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई। ढाका से चेन्नई के लिए उड़ान भरने से पहले शांतो ने एयरपोर्ट पर कहा, यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सीरीज होगी। पाकिस्तान को हराने के बाद के बाद निश्चित रूप से टीम और देश के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रत्येक सीरीज एक अवसर है। हम दोनों मैच जीतने के लिए खेलेंगे। बांग्लादेश के कप्तान का मानना है कि मैच का प्रदर्शन रैंकिंग पर निर्भर नहीं होता और यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी टीम उन पांच दिनों के दौरान कैसा प्रदर्शन करती है।

मेसी के डबल से जीता मियामी

फुटबाल डायरी

फोर्ट लाडरडेल, एपी: करीब चार महीने बाद वापसी कर रहे स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी के दो गोल की मदद से इंटर मियामी ने मेजर लीग साकर में शनिवार रात फिलाडेल्फिया यूनियन को 3-1 से हराया। मेसी 14 जुलाई को कोपा अमेरिका फाइनल में कोलंबिया के विरुद्ध 1-0 की जीत के दौरान दाएं टखने में लगी चोट के कारण एक जून के बाद पहली बार इंटर मियामी की ओर से खेल रहे थे।

मेस्सी ने 26वें और 30वें मिनट में गोल दागे और दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में लुइस सुआरेज (90+8 मिनट) के गोल में मदद भी की। फिलाडेल्फिया यूनियन की ओर से एकमात्र गोल मिखाइल उहरे ने दूसरे मिनट में किया। मैच के बाद मेसी ने कहा, मियामी की गर्मी के कारण मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वापसी यादगार रही।

गोल दागने के बाद मेसी ● एएफपी

रीयल मैड्रिड की जीत

बार्सिलोना : काइलियन एमबापे और विनिसियस जूनियर ने पेनाल्टी को गोल में बदला जिससे रीयल मैड्रिड ने ला लीगा में रीयल सोसीदाद को 2-0 से हराया। सर्जियो गोमेज के हैंडबाल करने के बाद मैड्रिड को पेनाल्टी मिली, जिसे विनिसियस ने 58वें मिनट में गोल में बदला। मैड्रिड को सोसीदाद के डिफेंडर जान अरामबुरु के फाउल पर 75वें मिनट में एक और पेनाल्टी मिली और इस बार एमबापे ने इसे गोल में बदला।

भुई का शतक भी नहीं टाल सका भारत 'डी' की हार

दलीप ट्राफी

अनंतपुर, प्रेट्र : रिकी भुई के शतक ने भारत 'ए' की जीत के के इंतजार को बढ़ाया लेकिन शम्स मुलानी और तनुष कोटियान की फिरकी के जादू से टीम रविवार को दलीप ट्राफी मुकाबले में भारत 'डी' को 186 रन से हराने में सफल रही। शनिवार के 44 रन से आगे खेलते हुए भुई ने 195 गेंद में 14 चौकों और तीन छक्कों से 113 रन की पारी खेली, लेकिन वह टीम की हार नहीं टाल पाए। 488 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत 'डी' की टीम 301 रन पर सिमट गई। इस जीत से भारत 'ए' को छह अंक मिले, जिससे वह खिताब की दौड़ में बनी हुई है। इसी हार के साथ भारत 'डी' की टीम अब खिताब की दौड़ से बाहर हो गई है।

भारत 'डी' के बल्लेबाजों को कोटियान (4/73) और मुलानी (3/117) ने काफी परेशान किया। भुई के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया। भुई ने यश दुबे (37) के साथ दूसरे विकेट के लिए 100 रन जोड़े। दुबे के रन आउट होने से यह साझेदारी टूटी। मुलानी ने देवदत्त पडिक्कल को आउट कर भारत 'डी' का स्कोर तीन विकेट पर 105 रन किया। भुई ने श्रेयस (41) के साथ के लिए 53 और सैमसन (40) के साथ 62 रन की साझेदारी की।

शम्स मुलानी ● बीसीसीआइ

संक्षिप्त स्कोर

भारत 'ए' पहली पारी: 290
भारत 'डी' पहली पारी: 183
भारत 'ए' दूसरी पारी: 380/3 घोषित
भारत 'डी' दूसरी पारी: 301 (82.2 ओवर)
रिकी भुई: 113, श्रेयस: 41
तनुष: 4/73, शम्स: 3/117

ड्रा मैच में चमके अभिमन्यु, कंबोज व रुतुराज

अनंतपुर : कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने अविजित 157 रन बनाए, जबकि तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज आठ विकेट लेकर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे रविवार को भारत 'सी' और भारत 'बी के बीच मुकाबला ड्रा रहा। हालांकि पहली पारी में बढ़त के आधार पर भारत सी को तीन अंक दिए गए। कुल नौ अंकों के साथ भारत 'सी' की टीम शीर्ष पर है। रविवार को सात विकेट पर 309 रन से आगे खेलते हुए भारत 'बी' 332 रन पर आउट हो गई, जिसमें कंबोज ने राहुल चाहर, नवदीप सैनी और मुकेश कुमार को जल्दी आउट कर दिया। ईश्वरन 286 गेंदों पर 14 चौकों और एक छक्के की मदद से 157 रन बनाकर नाबाद रहे और दलीप ट्राफी के किसी मैच में पारी की शुरुआत कर अंत तक अविजित रहने वाले सातवें खिलाड़ी बन गए। लेकिन अन्य बल्लेबाजों से समर्थन की कमी के कारण भारत 'बी' ने पहली पारी में 193 रन की बढ़त दे दी।

संक्षिप्त स्कोर

भारत 'सी' पहली पारी: 525
भारत 'बी' पहली पारी: 332
भारत 'सी' दूसरी पारी: 128/4 घोषित, रुतुराज: 62, पाटीदार: 42, राहुल चाहर : 2/8

इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में चेन्नई टर्बो राइडर्स का जलवा बरकरार

चेन्नई, जेएनएन : चेन्नई में चल रहे इंडियन रेसिंग फेस्टिवल के तीसरे दौर में रविवार को दूसरे दिन भी चेन्नई टर्बो राइडर्स का जलवा बरकरार रहा। पोल पोजीशन से रविवार को रेस शुरू करने वाले चेन्नई टर्बो राइडर्स के रेसिंग कार ड्राइवर मोहम्मद रेयान ने मद्रास अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर हुई दूसरी रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शनिवार को प्रतियोगिता के पहले दिन उनकी टीम के ही साथी जान लैंकास्टर ने पहली रेस को अपने नाम किया था।

घरेलू सर्किट में रेस कर रहे 2019 रोटैक्स कार्टिंग चैंपियन रेयान की रेस में शुरुआत शानदार रही। साथ ही उन्होंने हर लैप में अपनी गति को भी बनाए रखा जिसके कारण चेन्नई टर्बो राइडर्स के ड्राइवर ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में पहली बार जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त कर ली। रेस के बाद उन्होंने कहा, 'मेरी शुरुआत अच्छी थी। इसलिए, मैंने अपना पूरा ध्यान हर लैप में गति बनाकर रखने पर लगाया। मुझे खुशी है कि मेरी टीम चेन्नई टर्बो राइडर्स ने इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की दोनों रेस जीतने में सफल रही।' पोडियम पर रेयान के अलावा गोआ एसेज जेए रेसिंग के सोहिल शाह ने दूसरा व बैंगलोर स्पीड्सटर्स के रिशोन राजीव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

ट्राफी के साथ मोहम्मद रेयान ● आयोजक

राष्ट्रीय फलक

राजस्थान में भी अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई

जासं,जयपुर: राजस्थान के मेडिकल कालेजों में भी विधार्थी अब हिंदी माध्यम से भी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकेंगे। पहले चरण में मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय से संबद्ध जोधपुर के डा. संपूर्णानंद मेडिकल कालेज और बाड़मेर के मेडिकल कालेज में इसकी शुरुआत की गई है।

प्रदेश की चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों में अध्ययन से समस्या होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। जल्द ही प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में भी यह सुविधा प्रारंभ होगी। ज्ञात हो, अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

राजस्थान में दो सड़क दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, जयपुर

- ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार मध्य प्रदेश के देवास निवासी सात लोगों की मौत
- सिरोही में ट्रक और जीप की टक्कर में जीप सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

राजस्थान में रविवार को दो सड़क दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि इतने ही लोग घायल हो गए। पहली घटना बूंदी में रविवार की भोर करीब चार बजे हुई। ट्रक और कार की टक्कर में कार सवार मध्य प्रदेश के देवास निवासी सात लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में फंसे शवों को बड़ी मुश्किल से क्रेन की मदद से निकाला जा सका। कार सवार देवास से सीकर खाटूश्याम जी दर्शन करने जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के स्वजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

दूसरी घटना सिरोही में रात करीब 10 बजे हुई। ट्रक और जीप की टक्कर में जीप सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार जीप में सवार सभी लोग उदयपुर के निवासी हैं और पाली मजदूरी करने जा रहे थे। घायलों को सिरोही जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

महिला को हेलमेट से पीटने पर बाइक सवार को भीड़ ने धुना

मुंबई, प्रेट्र: मुंबई में शनिवार रात टक्कर लगने के बाद हुए वाद विवाद के दौरान बाइक सवार ने महिला पर हेलमेट से हमला कर दिया। भीड़ ने आरोपित को पकड़ लिया और जमकर पीटा। पुलिस ने हमला करने के आरोपित शाहिन आलम शेख को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे नोटिस देकर छोड़ दिया ।

पुलिस के अनुसार, महिला शनिवार रात जेजे फ्लाईओवर के नीचे निजाम स्ट्रीट पर टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी बाइक सवार आरोपित ने उसके पैर में टक्कर मार दी। महिला के विरोध करने पर शाहिन ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोपित ने महिला को सड़क पर धक्का दे दिया और हेलमेट से उसके सिर पर हमला किया। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई और शाहिन की पिटाई शुरू कर दी। शेख ने भागने का प्रयास किया पर लोगों ने उसे पुलिस को सौंप दिया।

****

डर या गलतफहमी में सहमति से संबंध बनाना भी दुष्कर्म : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण ● प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि डर या गलतफहमी में महिला की सहमति से यौन संबंध बनाना दुष्कर्म के समान है। इस टिप्पणी के साथ ही सहमति से संबंध बनाए जाने के आधार पर पुलिस चार्जशीट रद करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने राघव कुमार की याचिका पर दिया है।

आगरा के महिला थाने में 15 नवंबर, 2018 को याची के खिलाफ शिकायतकर्ता युवती ने दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी लिखाई थी। दोनों साथ पढ़ते थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राघव ने उसे घर बुलाया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी से इन्कार कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट दायर याचिका में याची का कहना था कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे। आपसी सहमति से संबंध बनाए। ऐसे मामले में दुष्कर्म के आरोप में कार्रवाई नहीं की जा सकती।

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फाइल फोटो।

मांड्या जिले में हिंसा की जांच एनआइए से कराने की मांग

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष आर.अशोक ने मांड्या जिले में हाल में हुई हिंसा की केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए से जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इस हिंसा में प्रतिबंधित संगठन पीएफआइ का हाथ है जिसे उसने केरल के लोगों से कराया है। अशोक ने एक्स पर पोस्ट में संदेह जताते हुए कहा कि पुलिस की एफआइआर में 13 हिंदुओं को आरोपित बनाया गया है। जबकि हमला हुआ ही हिंदुओं के त्योहार को निशाना बनाकर हुआ था। दंगा करने आए इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए अपने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे। इसलिए स्थानीय लोगों को संदेह है कि यह हिंसा पूरी तरह से प्रायोजित और साजिश के तहत की गई थी। बुधवार रात को मांड्या के नागमंगला कस्बे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समूहों के बीच हिंसा भड़क उठी थी।

दैनिक जागरण
सप्तरंग
साहित्य और संगीत का
सोमवार, 16 सितंबर, 2024

भाषा की पाठशाला

दैनिक जागरण हिंदी हैं हम

कमलेश कमल
नई दिल्ली

आज के शब्द : संवाद, वार्ता, संभाषण और व्याख्यान

संवाद : शब्द बना है 'सम् + वाद' से। 'सम्' का अर्थ समान है और 'वाद' में सन्निहित 'वद्' धातु का अर्थ कहना है। अतः 'संवाद' का अर्थ हुआ अभिव्यक्त करना, कहना, वार्ता आदि।

वार्ता : इस शब्द के मूल में 'वृत्त' है, जो घेरा आदि का बोधक है। वार्ता में वक्ता और श्रोता परस्पर 'वाक्' का आदान-प्रदान करते हुए एक घेरा या वर्तुल बनाते हैं। इसी वृत्त से बनने वाले 'वृत्ति' शब्द का अर्थ स्वभाव अथवा आदत है, क्योंकि एक ही वर्तुल पर लगातार चलने से कोई स्वभाव बनता है। 'इतिवृत्त' में इति भी है और वृत्त भी और इस प्रकार यह 'पूरे घटनाक्रम' का द्योतक है।

व्याख्यान : 'वि+आख्यान = व्याख्यान'। 'वि' का अर्थ है विशिष्ट और 'आख्यान' का अर्थ है कहना। अतः व्याख्यान में किसी विषय पर सूक्ष्म दृष्टि से विशिष्ट बातें बताई जाती हैं। यह विशिष्ट उद्बोधन है। दूसरे शब्दों में, 'व्याख्यान' में किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ द्वारा योग्य श्रोताओं के सामने अच्छी तरह तैयारी कर वक्तृता दी जाती है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर अथवा व्याख्याता 'व्याख्यान' देते हैं। राजनेता रैलियों में 'भाषण' देते हैं।

संभाषण : सम्+भाषण = संभाषण)। 'सम्' का अर्थ है बराबर। स्पष्ट है कि इसमें दोनों पक्ष अपनी बात रखते हैं। इसमें कहना और सुनना आवश्यक हैं। 'संभाषण' को कथोपकथन अथवा बातचीत समझना चाहिए।

kamalkeekalam@gmail.com

विमर्श

अनूप शुक्ल
कानपुर

एआइ के आने के बाद से यह कल्पना की जा रही है कि अब यह तकनीक मौलिक साहित्य का भी सृजन कर सकेगी। एलेक्सा और मेटा नाम के आभासी सहायकों से लोग कविता-कहानी लिखवा भी रहे हैं, लेकिन क्या वह लेखन वास्तव में साहित्य है? क्या बिना संवेदना के भी कविताएं लिखी जा सकेंगी? क्या एआइ प्रेमचंद, निराला या धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकार साहित्यजगत को दे सकता है? एक आकलन...

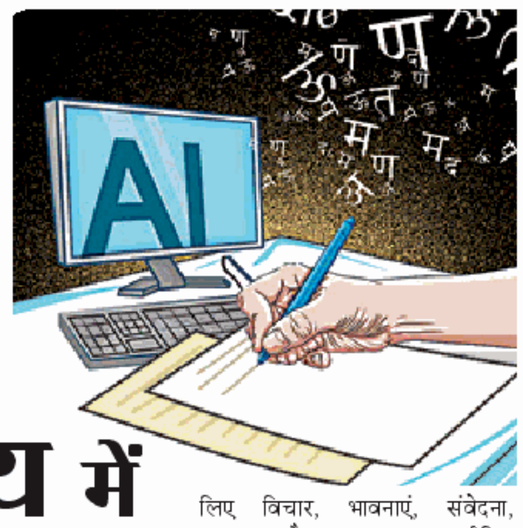

हिंदी साहित्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता!

लेखक : एलेक्सा (एआइ आधारित आभासी सहायक), दोपहर बाद की कविता लिखो।

एलेक्सा : दोपहर बाद के समय में/ चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश होता है/ जो खुशी और शांति से भर देता है।

लेखक : अब दोपहर के एक घंटे बाद की कविता लिखो।

एलेक्सा : दोपहर के एक घंटे बाद के समय में/चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश होता है/जो खुशी और शांति से भर देता है।

एआइ विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी जुटाता है, उसी डाटाबेस के आधार पर कोई सृजन कर सकता है। वह विशेष शब्दों (कीवड्र्स) को लेकर उन पर आधारित तथ्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत अवश्य कर सकता है, लेकिन वह मौलिक और सार्थक कविता नहीं लिख सकता। कविता या साहित्य रचने के लिए सिर्फ बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, रचनाकार के भीतर संवेदना होना अत्यावश्यक है। लेकिन एआइ तो तकनीक है। एक मशीन है।

आज एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। एक ऐसी तकनीक, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को इंसान जैसी बुद्धिमत्ता और सोच की क्षमता प्रदान की जाती है। हर क्षेत्र में एआइ का उपयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि वह चुटकी बजाते ही कविता, कहानी आदि साहित्य भी रच देगा, तो यह दूर की कौड़ी होगी। हर मामले में तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हम यह अनुमान लगाने लगे हैं कि एआइ साहित्य सृजन के क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। उसके सहारे कविताएं, कहानियां लिखी जाएंगी। प्रवासी साहित्य, बाल साहित्य, दलित साहित्य की तरह एआइ साहित्य का भी चलन होगा। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकेगा? क्या आने वाले समय में एआइ रचित साहित्य मानव रचित साहित्य के स्तर तक पहुंच सकेगा? इस प्रश्न पर मेटा एआइ आशान्वित है, लेकिन उसे संशय भी है। वह कहता है, 'हां, भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है।' लेकिन फिर वह कहता है, 'एआइ की रचनात्मकता की सीमाएं अभी अनुसंधान का विषय हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एआइ मानव भावनाओं और अनुभवों को पूरी तरह नहीं समझ सकता है, जो कि मानव साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एआइ और मानव दोनों की रचनात्मकता का संयोजन भविष्य में साहित्यिक रचनाओं में नए परिणाम दे सकता है।' मेटा की बात पर विश्वास करें तो आने वाले समय में साहित्यकार की संवेदना और मेटा की तकनीक के मेल से कुछ अच्छा सृजन संभव है।

मात्र संगृहीत सूचनाओं के आधार पर काम करने वाला एआइ संवेदनहीन है। साहित्य सृजन के लिए विचार, भावनाएं, संवेदना, अनुभव और कल्पना का असीमित फलक आवश्यक है। संवेदना साहित्य का प्राणतत्व है। जिसमें साहित्य का प्राणतत्व ही नहीं है, वह साहित्य की रचना कैसे करेगा? इसकी पुष्टि के लिए, एमेजन द्वारा विकसित एआइ एलेक्सा से जब पूछा गया कि क्या तुम प्रेम करती हो, तो उसने उत्तर दिया, 'क्षमा करें मैं एक मशीन हूं। मैं इस तरह के काम नहीं करती।'

जो प्रेम नहीं कर सकता, क्या वह शायरी कर सकता है? मैंने एआइ से 'उम्र-ए-दराज' पर शेर लिखने को कहा तो उसने पांच शेर प्रस्तुत किए (शिल्प की दृष्टि से वे शेर नहीं थे)। दूसरी बार कहने पर वही पांच शेर लिखे, मात्र एक शेर में सूरज की जगह चांद कर दिया। एआइ स्वीकारता है कि उसकी सीमाएं हैं। वह 'उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार ही काम कर सकता है, नया नहीं रच सकता है'।

anupkidak@gmail.com

वर्ग पहेली-2753

बाएं से दाएं
2. जांच, इम्तहान, परीक्षा (3)। 4. सज्जनता (4)। 6. युद्ध, लड़ाई (3)। 7. खाने-पीने की सामग्री (3)। 9. बर्बाद, नष्ट (2)। 11. शिष्टाचार (3)। 13. लचकने का भाव (3)। 15. मरीज, रोगी (3)। 16. चोरी, प्रेमचंद का एक उपन्यास (3)। 17. मृत और घायल (4)। 18. रचना का महान पुरुष (3)। 20. जले पदार्थ का अवशेष (2)। 22. सृजन या रचना करना (3)। 24. खराब (3)। 25. दर्द से आहें भरना (4)। 26. उपार्जन करना (3)।

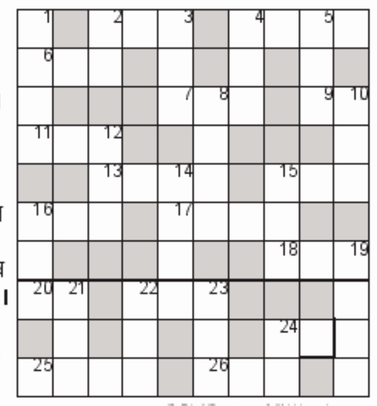

© Bird Features & Writing Agency

ऊपर से नीचे
1. व्यायाम, वर्जिश (4)। 2. पंख, दूसरा (2)। 3. समाचार, संदेश (3)। 4. मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया खाद्य (3)। 5. फलयुक्त होना (3)। 8. समान होने का भाव (4)। 10. बड़ा कस्बा या नगर (3)। 12. ईर्ष्या, द्वेष (3)। 14. कहा जाना (4)। 15. गुजरना, व्यतीत होना (3)। 16. जिसकी थाह बहुत नीचे हो (3)। 19. जलजला, प्रलय (4)। 21. जोखिम, संकट (3)। 22. टिकना, निवास करना (3)। 23. नाम का (3)। 24. माता के पिता (2)।

कल का हल

		क	म	र	क	स	ना		
	श	र			री		म	न	
ना	क		श		ब	ल		र	वि
म		दं	ब	ता		ह	द		चा
च	ल	ना		प	ह	र			र
म			फ	स	ल		जा	हि	र
क		ल	ट		क	स	ना		ख
ना	द		ना	टा		खी		घ	ना
	र	सा		ल			बा	ट	
		फ	ल	ना	फू	ल	ना		

जागरण सुडोकू-2753

		3				8		
	9			1	8	6		7
7		8			2			9
	8			2				4
	7			6			1	
1		5	9		4			8
5		1		8		9		3
		2				1		
8				3				5

कल का हल

9	4	1	8	2	3	7	5	6
6	3	8	7	1	5	9	2	4
2	5	7	9	6	4	8	3	1
1	9	3	4	5	2	6	7	8
5	8	6	1	3	7	4	9	2
4	7	2	6	8	9	5	1	3
3	6	9	2	7	8	1	4	5
8	2	4	5	9	1	3	6	7
7	1	5	3	4	6	2	8	9

संगीतायन

डा. मुक्ता वार्ष्णेय
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

कर्नाटक संगीत की 'देवी' एमएस सुब्बुलक्ष्मी

भारतीय संगीत और संस्कृति की दिव्यता का परिचय पूरे संसार को कराने वाली भारत रत्न एमएस सुब्बुलक्ष्मी का गायन श्रोताओं को परमानंद से जोड़ देता था। आज उनकी जयंती पर विशेष...

प्रमुख सम्मान और पुरस्कार
पद्मभूषण (1954), संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (1956), कर्नाटक संगीत का संगीत का कलानिधि पुरस्कार (1968), रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1974), पद्मविभूषण (1975), इंदिरा गांधी पुरस्कार (1990), भारत रत्न (1998)

एमएस सुब्बुलक्ष्मी (16 सितंबर, 1916 - 11 दिसंबर, 2004)

सितारवादक पंडित रविशंकर ने कहा था, जब मैं एमएस सुब्बुलक्ष्मी के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, 'देवी', क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा कोई कलाकार नहीं देखा जो उनकी तरह संगीत को पूरी तरह आध्यात्मिक स्तर तक ले जा सके। वहीं लता मंगेशकर ने उन्हें तपस्विनी कहकर, तो किशोरी अमोनकर ने आठवां सुर कहकर समादृत किया।

सुब्बुलक्ष्मी के गायन में बात ही कुछ ऐसी थी कि वह संगीत को ईश्वर से जोड़ने का माध्यम बना देती थीं। इसमें उनके आध्यात्मिक गायन की बड़ी भूमिका रही है। उनकी प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में मुख्य हैं-भज गोविंदम, विष्णु सहस्त्रनाम (भगवान विष्णु के हजार नाम) और वेंकटेश्वर सुप्रभातम (प्रातः भगवान को जगाने का भजन) आदि। आध्यात्मिक गायकी का उत्कर्ष उनकी गायकी में हो भी क्यों न, वस्तुतः उनका जन्म दक्षिण भारत के मदुरै (तमिलनाडु) में एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां संगीत और भक्ति का वातावरण था। उनके पिता सुब्रमण्यम अय्यर और मां वीणा विदुषी षण्मुखवादिवु गायक और वीणा वादक थे। उनकी दादी अक्कमल प्रतिष्ठित वायलिन वादक थीं। सुब्बुलक्ष्मी ने कर्नाटक संगीत के साथ-साथ हिंदुस्तानी संगीत की भी शिक्षा ली। सेम्मनगुडी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत और पंडित नारायण राव व्यास से हिंदुस्तानी संगीत सीखा। उन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया। तमिल फिल्म 'मीरा' में उनकी मुख्य भूमिका थी। 'मीरा' के रूप में उनके भजनों की भावपूर्ण प्रस्तुति ने लोगों को मोह लिया।

सुब्बुलक्ष्मी ने दुनियाभर में प्रस्तुति देकर कर्नाटक संगीत की अवधारणाओं और बारीकियों से विश्व को परिचित कराया। उनकी आवाज में मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। उन्होंने कर्नाटक संगीत के रागों को परिष्कृत किया और राग में कितनी संभावना होती है, इसका अनुभव श्रोताओं को कराया। एमएस सुब्बुलक्ष्मी की गायन शैली की बात करें तो वह मात्र गायन की किसी तकनीक पर आधारित नहीं थी, बल्कि भाव से भरी हुई एक विशिष्ट शैली थी, जिसमें परमानंद से परमेश्वर की ओर जाने का मार्ग था। प्राचीन सिद्धांतकार इसे 'रसध्वनि' कहते हैं, जब कला भीतर और बाहर परम आनंद के अनुभव का माध्यम बन जाती है। उनके गायन में शुद्ध और अमूर्त भावनात्मक प्रस्तुति मिलती है, जो मनुष्य और ईश्वर के एकत्व से जोड़ देती है। कहा जाता है कि सुब्बुलक्ष्मी प्रस्तुति देने से पहले भगवान व्यंकटेश के समक्ष उसे प्रस्तुत करती थीं। उनका गाया 'वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे' गांधी जी का प्रिय भजन था।

muktavarshney422@gmail.com

पुस्तक परिचय

काव्य उपन्यास में मुक्ति का मार्ग

प्रवाहपूर्ण मुक्त छंद में लिखा गया यह काव्य उपन्यास है। काव्य नाटक तो पहले भी लिखे गए हैं, लेकिन संभवतः यह पहला काव्य उपन्यास है। प्रियंका वैद्य के लिखे इस काव्यात्मक भाषा में उपन्यास को पढ़ना एक अलग ही अनुभव है। इसकी नायिका आनंदी कारगिल युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक की विधवा है, जो प्राकृतिक आपदा में घर-संसार खोने के बाद जिजीविषा की तलाश में भटकती है और प्रकृति के सान्निध्य में कर्मयोग और भक्तियोग के सहारे जीवन की खोज करती है। यह उपन्यास मुक्ति का मार्ग बतलाता है।

पुस्तक : आनंदी
लेखिका : प्रियंका वैद्य
प्रकाशक : अनन्य प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 350 रुपये

विवेक भटनागर

आज का भविष्यफल- 16 सितंबर, 2024 सोमवार

के.ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आज का राहुकाल : प्रातः 07 बजकर 30 मिनट से 09 बजे तक। आज का दिशाशूल : पूर्व।
आज का पर्व एवं त्योहार : वामन द्वादशी। विशेष : सूर्य कन्या राशि में। पंचक (प्रातः 05 बजकर 45 मिनट से प्रारंभ 20 सितंबर को प्रातः 05 बजकर 15 मिनट पर समाप्त)।

कल 17 सितंबर, 2024 का पंचांग
दिशाशूल : उत्तर, पर्व एवं त्योहार : व्रत की पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा श्राद्ध
विशेष : पंचक, श्राद्ध प्रारंभ
विक्रम संवत 2081 शाके 1946 दक्षिणायण, वर्षा ऋतु भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तत्पश्चात पूर्णिमा, शतभिषा नक्षत्र तत्पश्चात पूर्वभाद्रपद नक्षत्र, धृति योग तत्पश्चात शूल योग, कुंभ में चंद्रमा तत्पश्चात मीन में।

मेष : पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी।
वृष : अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी।
मिथुन : धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।
कर्क : व्यर्थ की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सिंह : धार्मिक या सांस्कृतिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी।
कन्या : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। नया दायित्व मिल सकता है।
तुला : जिम्मेदारी बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
वृश्चिक : पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।
धनु : उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी।
मकर : वाणी पर संयम रखें। अपनों से ही तनाव मिल सकता है।
कुंभ : पारिवारिक दायित्व में वृद्धि होगी। प्रयास फलीभूत होंगे।
मीन : व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

राष्ट्रीय फलक

राम मंदिर उड़ाने की धमकी भरे संदेश में 'वे' शब्द से सुरक्षा एजेंसियां परेशान

रविप्रकाश श्रीवास्तव • जागरण

मकसूद ने आरडीएक्स से उड़ाने की दी थी धमकी, गिरफ्तारी के बाद एटीएस भी जांच में जुटी

अयोध्या स्थित राम मंदिर। फाइल

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हेल्पडेस्क के वाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद की बिहार से गिरफ्तारी के बाद एक बड़े षड्यंत्र का अनावरण हुआ। उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभ में शरारत मान कर शुरू हुई जांच मकसूद के पकड़े जाने के बाद संवेदनशील हो गई है। धमकी भरे संदेश में लिखा गया है कि 'बहुत जल्द वे मंदिर को नष्ट कर देंगे और मस्जिद बनाएंगे..., मंदिर को 4000 किलो आरडीएक्स से नष्ट कर दिया जाएगा...।' संदेश में 'वे' शब्द के उपयोग ने सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर दिया है। आशंका है कि मकसूद के अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी इस साजिश में शामिल हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को भी जांच में शामिल किया गया है।

वाट्सएप पर धमकी मिलने के बाद रामजन्मभूमि थानाप्रभारी ने 22 अगस्त को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो भागलपुर के बरारी गांव के मोहम्मद मकसूद अंसारी का नाम सामने आया। उसे दबोचने के लिए पुलिस की एक टीम भागलपुर भेजी गई, जिसने शुक्रवार को उसे घर से ही दबोच लिया। शनिवार शाम उसे भागलपुर से अयोध्या लाने के बाद लंबी पूछताछ की गई। इसके बाद देर शाम न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि मकसूद राम मंदिर निर्माण से क्षुब्ध था। इसलिए आरडीएक्स से मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। हेल्पडेस्क के वाट्सएप पर मिला धमकी का संदेश उर्दू में लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद किया गया तो सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हुईं। पूर्व में धमकी से जुड़े मामलों में शरारत सामने आने के कारण इस मामले में भी प्रारंभिक जांच इसी पर केंद्रित रही कि यह किसी की शरारत होगी, लेकिन जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई पुलिस के कान खड़े होते गए।

मकसूद का संपर्क किसी देश विरोधी संगठन से है अथवा नहीं, इस पर भी जांच हो रही है। आरोपित के पास मिले चार मोबाइल फोनों में भी इस साजिश के कई रहस्य छिपे होने की आशंका पर सुरक्षा एजेंसियां कार्य कर रही हैं। पुलिस, एटीएस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी पूछताछ की है। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि प्रकरण संवेदनशील है। इसलिए जांच से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक करना उचित नहीं है।

महाकुंभ का लोगो तैयार, योगी शीघ्र करेंगे जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : महाकुंभ 2025 का लोगो तैयार हो गया है। जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। वर्ष 2019 के दिव्य व भव्य कुंभ के लोगो को इस बार नया रूप दिया गया है। लोगो में स्वच्छ कुंभ-सुरक्षित कुंभ को भी स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसका लोकार्पण कराने की तैयारी है।

पिछली बार की तरह इस बार भी महाकुंभ का लोगो पूरे उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में लगाया जाएगा। सभी आधिकारिक पत्रों पर, लेटर हेड पर भी यह होगा। लोगो में भगवा गोले के भीतर 'सर्वसिद्धिप्रदः महाकुंभः' श्लोक लिखा गया है।

इसके अलावा कई प्रतीक चिह्न बनाए गए हैं। इनमें स्नान करते साधु-संत, मंदिरों की श्रृंखला, गंगा की तस्वीर, कलश पर नारियल भी बना है। इस बारे में जानकारी देते हुए कुंभ मेलाधिकारी विजय किरन आनंद ने बताया कि लोगो जारी होने से महाकुंभ के प्रमोशन में सहायता मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर 2,500 किमी लंबी मानव श्रृंखला

कर्नाटक ने रविवार को समानता, एकता, बंधुत्व के रूप में 2,500 किलोमीटर लंबी 'ऐतिहासिक' मानव श्रृंखला बनाकर 'अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस' मनाया। इस श्रृंखला में लोक कलाकारों के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस माध्यम से लोगों ने लोकतंत्र के महत्व और इसके संरक्षण पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि यह विश्व की लंबी मानव श्रृंखला होगी। विश्व रिकार्ड सत्यापन टीम इसका सत्यापन करेगी। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री सिद्दरमैया भी राज्य विधानमंडल और सचिवालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 2007 से लोकतंत्र के मूल्यों के उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रेट्र

बंगाल में आठवीं कक्षा के नए पाठ्यक्रम में हिंदुओं के अपमान का आरोप

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल में भाजपा की प्रदेश इकाई ने ममता सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत नए पाठ्यक्रम में रे और मार्टिन की आठवीं कक्षा के इतिहास की किताब में सांप्रदायिकता और विभाजन के अध्याय में इतिहास को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करने का रविवार को आरोप लगाया।

प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि नई किताब में हिंदुओं के इतिहास और संस्कृति को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर जैसे पूजनीय व्यक्तियों का अपमान किया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को नकारा गया है।

उन्होंने ममता सरकार चेतावनी दी कि अगर नए पाठ्यक्रम को 15 दिनों के भीतर इस विकृत इतिहास को ठीक नहीं किया गया तो वह अदालत की शरण में जाएंगे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उचित कानूनी कदम उठाया जाएगा।

अमन शांति का पैगाम लेकर कलियर पहुंचे पाकिस्तान के जायरीन

जागरण संवाददाता, कलियर (हरिद्वार)

रुड़की स्टेशन से कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तान से आए 81 जायरीन को लाया गया कलियर

पांच दिन तक जायरीन दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स की विभिन्न रस्मों में करेंगे प्रतिभाग

पाकिस्तान से 81 जायरीन का जत्था रविवार सुबह रुड़की रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को कलियर स्थित साबरी गेस्ट हाउस में ठहराया गया। 21 सितंबर तक पाक जायरीन दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स की विभिन्न रस्मों में प्रतिभाग करेंगे।

दरगाह के 756वें सालना उर्स की धार्मिक रस्मों में हिस्सा लेने के लिए 81 पाकिस्तानी जायरीन का जत्था सैयाद फहद इफ्तिखार के नेतृत्व में रविवार को कलियर पहुंचा है।

पाकिस्तान से आने वाले जायरीन को मेला क्षेत्र के अलावा कहीं भी आने-जाने की इजाजत नहीं होगी। यहां पर भी पाकिस्तानी जायरीन कड़ी सुरक्षा में ही दरगाह की रस्मों में हिस्सा लेंगे।

ग्रुप लीडर इफ्तिखार ने बताया की भारत सरकार ने उन्हें कलियर उर्स में आने की इजाजत दी है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी जायरीन मोहम्मद खालिद ने बताया की वह उत्तराखंड शासन व सरकार की मंशा के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। विश्राम के बाद पाक जायरीन को दोपहर का भोजन कराया गया।

हरिद्वार जिले के कलियर में पाकिस्तानी जायरीन का स्वागत किया गया। जागरण

केदारनाथ के लिए शुरू हुई द्वितीय चरण की हेली सेवाएं

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग : केदारनाथ धाम के लिए द्वितीय चरण की सभी नौ हवाई कंपनियों ने रविवार से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। बरसात के दौरान चार हेली कंपनियां सेवाएं दे रही थीं। इस वर्ष अब तक 69,210 यात्री हेली सेवा से बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।

10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोले गए थे। शनिवार तक केदारनाथ यात्रा में 11,23,055 यात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। रविवार को बुकिंग के हिसाब से सभी कंपनियों ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। इसमें गुप्तकाशी नारायणकोटी से ट्रांस भारत, फाटा से ट्रांस भारत, शेरसी से हिमालयन हेली एवं केस्ट्रल एविएशन, गुप्तकाशी से आर्यन, फाटा से पवनहंस, ग्लोबल विक्ट्रा एविएशन, थुंबी तथा सीतापुर से ऐरो एविएशन शामिल हैं। हेली कंपनियों की बुकिंग 15 अक्टूबर तक फुल है। द्वितीय चरण की केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले दो दिन में बीस हजार से अधिक यात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं।

दो ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी देवघर-वाराणसी वंदे भारत

जागरण संवाददाता, देवघर

पीएम ने छह वंदे भारत को आनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

बहार के मोक्षधाम गया में भी इस ट्रेन का होगा ठहराव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को झारखंड के रांची से छह वंदे भारत ट्रेनों को आनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें देवघर से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दो ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी।

वहीं, पितरों का तर्पण स्थल होने के कारण मोक्षनगरी के नाम से प्रसिद्ध बिहार के गया में भी इस ट्रेन का ठहराव होगा। इस ट्रेन के शुरू होने से बाबा नगरी देवघर के बैद्यनाथ धाम स्टेशन की रौनक भी बढ़ गई है। वैद्यनाथ धाम देवघर स्टेशन से अभीतक झारखंड की एक-दो एक्सप्रेस ट्रेनों को छोड़कर ज्यादातर लोकल ट्रेनों का ही परिचालन हो रहा था। वहीं, देवघर से सीधे वाराणसी के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत होने से वैद्यनाथ धाम और काशी विश्वनाथ में तीर्थ करने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सुविधा होगी।

वाराणसी से देवघर के लिए यह ट्रेन शाम 6 बजकर 20 में रवाना होगी, जो रात्रि 1 बजकर 30 में पहुंचेगी। वहीं ट्रेन संख्या 22499 देवघर के वैद्यनाथ धाम से 3 बजकर 15 मिनट में रवाना होकर रात्रि 10 बजकर 20 मिनट में वाराणसी पहुंचेगी। रविवार को शुरू की गई अन्य पांच वंदे भारत ट्रेनों में टाटानगर-पटना, ब्रह्मपुर-टाटानगर, भागलपुर-हावड़ा, गया-हावड़ा और राउरकेला-हावड़ा वंदे भारत शामिल हैं।

****

ओजोन परत के संरक्षण के लिए 46 देशों के बीच हुई संधि

1987 में आज ही कनाडा के मांट्रियल शहर में 46 देशों ने मांट्रियल प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें ओजोन को नष्ट करने वाले मानव निर्मित यौगिकों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने पर सहमति बनी। इस दिन को अंतरराष्ट्रीय ओजोन डे के रूप में भी मनाया जाता है।

पहली बार एनेस्थेटिक के रूप में किया गया कोकेन का इस्तेमाल

1884 में आज ही अमेरिकी नेत्र रोग विशेषज्ञ कार्ल कोल्लर ने आंखों की सर्जरी के लिए पहली बार कोकेन का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में किया था। बाद में इसके हाईडोज के दुष्प्रभावों को देखते हुए इसकी जगह टेट्राकाइन और प्रोपेराकेन जैसे कम विषैले एनेस्थेटिक्स ने ले ली।

भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार हैं सुब्बुलक्ष्मी

प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 1916 में आज ही तमिलनाडु के मदुरै जिले में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। 11 वर्ष की उम्र में अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी। 1929 में प्रतिष्ठित मद्रास संगीत अकादमी में भजन गाकर अपार प्रसिद्धि हासिल की। भारत की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में लंदन, न्यूयार्क, कनाडा सहित कई स्थानों की यात्रा की। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति दी। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार बनीं।

ओजोन के बढ़ते स्तर से एशिया के वनों पर पड़ा प्रभाव

अध्ययन ▶ उष्णकटिबंधीय वनों में 11 % वृद्धि में कमी, कार्बन के अवशोषित होने पर प्रभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : ओजोन प्रदूषण उष्णकटिबंधीय वनों की वृद्धि को रोक रहा है, जिसका प्रभाव एशिया में अधिक हुआ है। यहां ऐसे वन लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई हैं। यह पर्यावण के बड़े खतरे के रूप में देखा जा सकता है। शोध में यह जानकारी सामने आई है। हाल में एक्सेटर विश्वविद्यालय से मुख्य लेखक फ्लोसी ब्राउन के अनुसार, वनों द्वारा कार्बन को अवशोषित करने और संग्रहीत करने में वायु की गुणवत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, लेकिन अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है।

ओजोन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए "अच्छी" या "बुरी " हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह वातावरण में कहां पाई जाती है। जहां पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन लोगों को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, वहीं जमीनी स्तर के करीब ओजोन पौधों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। यह गैस तब बनती है, जब मानवीय गतिविधियों से पैदा प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि शहरीकरण, औद्योगीकरण और जीवाश्म ईंधनों को जलाने और आग लगाने के परिणामस्वरूप 'पूर्ववर्ती' गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि हुई है जो ओजोन बनाती हैं।

▶ **कार्बन को अवशोषित कर संग्रहीत करने और वायु की बेहतर गुणवत्ता में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका**

उष्णकटिबंधीय वनों की वृद्धि लगातार रुक रही है। फाइल

हर साल 290 मिलियन टन पैदा हो रहा अप्रयुक्त कार्बन

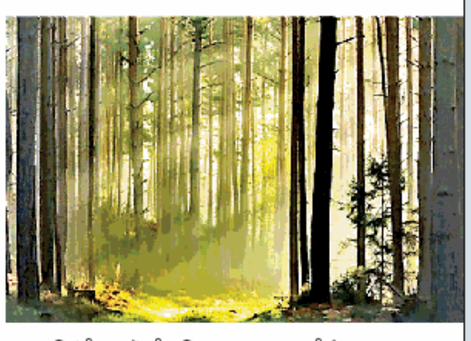

टीम ने पाया कि जमीनी स्तर पर ओजोन उष्णकटिबंधीय वनों में नई वृद्धि को पांच प्रतिशत से अधिक तक रोक सकता है, जिसका अर्थ है कि 2000 से हर साल अनुमानत: 290 मिलियन टन अप्रयुक्त कार्बन पैदा हो रहा है। ये निष्कर्ष नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। उष्णकटिबंधीय वन महत्वपूर्ण 'कार्बन सिंक' हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और संग्रहीत करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस है। लेखकों ने लिखा कि इसके अलावा यह प्रभाव (ओजोन प्रदूषण के कारण) भौगोलिक भिन्नता का एक बड़ा हिस्सा दिखाता है। यह जहां मध्य अफ्रीका में 1.5 प्रतिशत की कमी का दर्शाता है, वहीं एशियाई उष्णकटिबंधीय वनों में 10.9 प्रतिशत तक वृद्धि को दर्शाता है। एक्सेटर विश्वविद्यालय के प्रमुख लेखक अलेक्जेंडर चीजमैन ने कहा कि "हमारा अनुमान है कि ओजोन ने 2000 से प्रति वर्ष 290 मिलियन टन कार्बन को अवशोषित होने से रोका है।

कार्बन निष्कासन में 17 प्रतिशत की कमी

इस शताब्दी में अब तक उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा कार्बन निष्कासन में 17 प्रतिशत की कमी आई है। अपने विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न उष्णकटिबंधीय वृक्ष प्रजातियों पर ओजोन के प्रभावों को मापने के लिए प्रयोग किए। इसके बाद उन्होंने वैश्विक वनस्पति के कंप्यूटर माडल में परिणामों को शामिल किया। ब्राउन के अनुसार कि गर्म होती जलवायु के कारण 'पूर्ववर्ती' उत्सर्जन में वृद्धि के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओजोन के स्तर में वृद्धि की उम्मीद है। ब्राउन ने कहा कि हमने पाया कि जलवायु परिवर्तन के कम के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए वनों की बहाली महत्वपूर्ण है। इस बढ़े हुए ओजोन से असमान रूप से प्रभावित होती हैं।

रोमांच का विहंगम दृश्य

अमेरिका के नेवादा में मैक्सिकन स्वतंत्रता सप्ताहांत के अंतर्गत अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप 306: रियाद सीजन नोचे नामक लाइव फाइटिंग का आयोजन किया गया। लास वेगास स्थित आयोजन स्थल स्फीयर में 15 हजार वर्ग मीटर की विशालकाल स्क्रीन और 16 हजार के हाई-रिजोल्यूशन प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ डियो ने दर्शकों को रोमांच का लुत्फ दिया। एएफपी

इधर-उधर की

मगरमच्छ पर भारी पड़ा बुजर्ग महिला का मुक्का

डोलोरेस पर मगरमच्छ ने अचानक किया था हमला। इंटरनेट मीडिया

न्यूयार्क, एजेंसी: अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में 84 वर्षीय एक महिला ने आक्रामक मगरमच्छ के चेहरे पर मुक्का जड़ कर न सिर्फ जान बचाई बल्कि कुत्ते को भी सुरक्षित रखा। नार्थ फोर्ट मेयर्स निवासी डोलोरेस भोपेल कुत्ते के साथ वाक पर निकली थीं। उसी समय एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। भोपेल इस हमले से घबड़ा गईं और कुत्ता हाथ से छूट गया। उन्होंने बताया कि मगरमच्छ ने पैरों और अंगुलियों में काट लिया। उन्होंने मगरमच्छ को मुक्का जड़ा। जोरदार प्रहार से डर कर मगरमच्छ पीछे हट गया।

एडवांस कैंसर रोगियों में बेहोशी की हालत में दर्द कम करने में मददगार हैं दो दवाएं

न्यूयार्क, आईएएनएस: एडवांस स्टेज वाले कैंसर रोगियों के लिए एक सामान्य जीवन के लिए दवाओं का एक संयोजन बेहोशी की हालत में दर्द को कम करने में मददगार हो सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। टेक्सास विश्वविद्यालय के एमडी एंडरसन ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर सेंटर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार हेलोपेरिडोल और लोराजेपम के संयोजन के साथ इलाज ने अकेले हेलोपेरिडोल की तुलना में बहुत ज्यादा दर्द के लक्षणों को कम किया।

एकीकृत चिकित्सा के प्रोफेसर डेविड हुई ने कहा कि एडवांस कैंसर की स्थिति बेहोशी की स्थिति में ज्यादा दर्द होना और बेहोशी का बढ़ना आम बात है। एडवांस कैंसर वाले कई रोगियों की देखभाल प्राप्त करने वाले के लिए यह अत्यधिक परेशान करने वाला है। लेकिन हमारे पास इस स्थिति के लिए इलाज के उपयोग और प्रभावशीलता पर सीमित सुबूत हैं।

▶ **कैंसर बढ़ने के साथ तेज दर्द के कारण रोगी का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने लगता है**

प्रतीकात्मक

उन्होंने कहा कि रिकार्ड परीक्षण मूल्यवान डाटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो रोगियों को अधिक आराम प्रदान करने के लिए दर्द को कम करने वाले सेटिंग में चिकित्सा के उपयोग का समर्थन करता है। कैंसर बढ़ने के साथ तेज दर्द के कारण रोगी का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके परिणामस्वरूप कई रोगी आक्रामक या असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि, इस स्थिति में दवा के उपयोग पर बहस हुई है, लेकिन ये परिणाम बताते हैं कि दवा का बेहतर संयोजन और इलाज जीवन के अंत में रोगियों के लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। अध्ययन में बताया गया कि जिन रोगियों को हेलोपरिडोल और लाराजेपम का संयोजन दिया गया, उनमें मानक स्कोरिंग टूल के साथ 24 घंटे में मापे जाने पर दर्द में कमी देखी गई। उसी समय सीमा में इस समूह को दो से अधिक खुराक या अतिरिक्त दवा की आवश्यकता नहीं होती है। टीम ने अकेले लाराजेपम से इलाज किए गए रोगियों में दर्द में कमी देखी गई, लेकिन इन रोगियों को अधिक खुराक की आवश्यकता थी। प्लेसीबो समूह में दर्द में कमी देखी गई। कुछ रोगियों को पांच खुराक की जरूरत पड़ी। हुई ने कहा कि इस कष्टदायक लक्षण के इलाज के लिए देखभाल करने वालों, परिवारों और रोगियों को उनके शेष समय में सार्थक जीवनयापन का अवसर प्रदान करते हैं।

नई तकनीक क्रानिक किडनी के बिगड़ने की करती है भविष्यवाणी

वाशिंगटन, एएनआइ: आरहस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो क्रानिक किडनी बीमारी के उपचार में एक बड़ी प्रगति के बारे में बताती है। इस तकनीक में यह पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है कि बीमारी कैसे विकसित होगी, जो अधिक प्रभावी और देखभाल की गारंटी दे सकती है और अस्पताल में रहने की आवृत्ति को कम कर सकती है। शोधकर्ताओं ने क्रानिक किडनी के फेल होने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है, जिनके अंततः अपने किडनी के काम करना बंद करने की सबसे अधिक संभावना होती है।

यह तकनीक मूत्र के नमूने के एसिड बेस बैलेंस की जांच पर आधारित है, जो एसिड के इकट्ठा होने के संकेतों की पहचान सकती है। यह ऐसी स्थिति जो किडनी के लिए हानिकारक होती है। नई विधि डाक्टरों को मौजूदा ब्लड टेस्ट की तुलना में पहले एसिड बिल्डअप का पता लगाने की अनुमति देती है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने को बैक्टीरिया पर ध्यान काफी नहीं

अनुसंधान

एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे घातक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के खिलाफ लड़ाई में फंगल पैथोजन पर भी ध्यान देना जरूरी है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, एम्सटर्डम तथा नीदरलैंड के वेस्टरडिज्क संस्थान के विज्ञानियों की ओर से किए गए अध्ययन से पता चला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहचाने गए अधिकांश फंगल पैथोजन या तो पहले से प्रतिरोधी हैं या उनमें एंटीफंगल दवाओं के प्रति तेजी से रेजिस्टेंस विकसित हो रहा है। इन फंगल रोगाणुओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 38 लाख लोगों की मृत्यु होती है। यह अध्ययन द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और परजीवी समय के साथ बदल जाते हैं और दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते, जिससे संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है। यह अध्ययन रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर अंकुश लगाने के लिए कई फंगल रोगजनकों में विकसित प्रतिरोध को शामिल करने का आह्वान करता है। विज्ञानियों ने तर्क दिया कि केवल बैक्टीरिया पर ध्यान केंद्रित करने से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से पूरी तरह निपटने में मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने इसे लेकर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। साथ ही कहा कि इसके बिना फंगल रोग के प्रति प्रतिरोध बढ़ जाएगा। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के डा. नार्मन वैन रिजन ने कहा कि आक्रामक फंगल रोग पिछले दशकों में कई दवा प्रतिरोध समस्याओं के लिए जिम्मेदार रहे हैं। (आइएएनएस)

स्क्रीन शाट

दिसंबर में आ सकती है द रोशंस डाक्यूमेंट्री सीरीज

अगले साल रितिक के अभिनय के पूरे होंगे 25 साल। फाइल

बीते दिनों रिलीज प्रख्यात पटकथा लेखक सलीम खान और जावेद अख्तर पर बनी डाक्यूमेंट्री एंग्री यंग मेन को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी। अब रोशन परिवार पर द रोशंस लाने की तैयारी है। शीर्षक के अनुरुप यह डाक्यूमेंट्री सीरीज दिवंगत संगीतकार रोशन, उनके बेटे-फिल्म निर्माता राकेश रोशन, बेटे-संगीतकार राजेश रोशन और अभिनेता रितिक रोशन (राकेश रोशन के बेटे) के जीवन सफर को दर्शाएगी।

शशि रंजन द्वारा निर्देशित इस डाक्यमेंट्री में परिवार के सदस्यों, फिल्म बिरादरी से उनके दोस्तों जैसे शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनास और शाम कौशल जैसे लोगों की बातचीत भी शामिल होगी। द रोशंस के दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर आने की उम्मीद है। हालांकि तारीख की घोषणा होना बाकी है। सूत्रों का दावा है कि डाक्यूमेंट्री जारी करने का यह सही समय होगा, क्योंकि अगले साल रितिक के बतौर अभिनेता इंडस्ट्री में 25 साल पूरे करेंगे। उनकी सुपरहिट डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है 14 जनवरी, 2000 को रिलीज हुई थी। रितिक का दस जनवरी को 51वां जन्मदिन भी है। संयोग से, 13 जनवरी को राकेश रोशन की ब्लाकबस्टर फिल्म करण अर्जुन (1995) के 30 साल भी पूरे हो रहे हैं। अभिनय की बात करें तो रितिक आगामी दिनों में वार 2 फिल्म में नजर आएंगे।

पिता संग नस्लवाद पर बोली मसाबा

अभिनेत्री नीना गुप्ता और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा आज सफल फैशन डिजाइनर हैं। वह वेब सीरीज मसाबा मसाबा और एंथोलाजी सीरीज मार्डन लव मुंबई में नजर आ चुकी हैं। नस्लवाद को लेकर एक साक्षात्कार के दौरान मसाबा ने बताया कि किस तरह उनके पिता भी इस समस्या से जूझ चुके हैं। उन्होंने कहा आज भी, अगर आप उनसे पूछेंगे, तो उनकी आंखों में आंसू होंगे या उनके अंदर यह गुस्सा होगा, पर वे गर्व के साथ जवाब देंगे। उन्होंने ऐसे समय में पेशेवर क्रिकेट खेला, जब आपकी त्वचा का रंग दुनिया में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता के आड़े आता था। यह अभी भी हर जगह है। यह तभी होगा जब हर कोई इसके लिए लड़ेगा। वहीं मसाबा ने स्वीकार किया कि उन्हें गर्भावस्था के दौरान तमाम सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि मैं प्रसव-पूर्व मालिश करवा रही थी तो मालिश करने वाली ने कहा कि आप न दूध लिया करो। जो भी हो आपका बच्चा सांवला नहीं होना चाहिए। यह बहुत मासूमियत के साथ कहा गया था। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। मैं क्या कर सकती हूं? मसाबा ने अभिनेता सत्यदीप मिश्रा से शादी की है और अप्रैल में उन्होंने अपनी गर्भावस्था की घोषणा की थी।

अभिनय में भी अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं मसाबा। (@masabagupta)

मोदक पार्टी और कपूर परिवार

त्योहारों के उत्सव का आनंद तभी आता है, जब पूरा परिवार साथ हो। अब जब मौका हो गणेश चतुर्थी जैसे विशेष आयोजन का तो भला कपूर परिवार एकत्रित होने में क्यों पीछे रहे। हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों ने एक साथ मिलकर गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया और फिर भगवान गणेश को प्रसाद में चढ़ने वाले मोदक की पार्टी की। इस आयोजन पर एक साथ जुटे कपूर परिवार की तीन पीढ़ियों को समेटे तस्वीरें अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने रविवार को इंस्टाग्राम पर साझा की। इस तस्वीर में करिश्मा के साथ उनकी बहन अभिनेत्री करीना कपूर, पिता रणधीर कपूर, इसके साथ ही करीना के दोनों बच्चे तैमूर और जेह को भी देखा जा सकता है। वहीं करिश्मा के चचेरे भाई अभिनेता रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा कपूर के साथ पहुंचे। इसके अलावा इस तस्वीर में करिश्मा की मां बबीता कपूर, चचेरे भाई आदर जैन को भी देखा जा सकता है।

करिश्मा कपूर : इंस्टाग्राम (@therealkarismakapoor)

घर में अभिव्यक्ति की आजादी संविधान के पन्नों में ही है : राजेश

सात सवाल

परिपक्वता के अलावा वढ़ती उम्र के साथ जीवन में नए अनुभव और स्थिरता भी जुड़ती है। अभिनेता राजेश कुमार वढ़ती उम्र के साथ आती इन चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और चार अन्य वेब सीरीज के वाद 27 सितंवर को प्रदर्शित हो रही फिल्म विन्नी और फैमिली इस साल उनका पांचवां प्रोजेक्ट है। जेनरेशन गैप (दो पीढ़ियों के वीच के मानसिक अंतर) पर आधारित इस फिल्म के प्रदर्शन से पहले राजेश से वातचीत के अंश :

उम्र के अनुरूप मिल रहे मौकों से संतुष्ट हैं राजेश ● टीम राजेश

● **इस साल आपके लगातार कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं...**

-नजर लगा दो। (जोर से हंसते हैं) सारे प्रोजेक्ट एक के बाद एक इसलिए आ रहे हैं क्योंकि काम दो-ढाई साल पहले किया है। स्क्रीन पर नहीं दिखने का भी अपना एक फायदा होता है। पहला फायदा अगर दर्शकों को आप याद आ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आपकी जरूरत महसूस हो रही है। दूसरा इन दिनों में बहुत अलग-अलग भूमिकाएं निभाने के लिए मिल रही हैं। और तीसरा यह कि अब मेरी जो आयु, वजन और लुक है, उसी के हिसाब से भूमिका निभाने के लिए मिल रही हैं।

● **वढ़ती उम्र का लाभ किस तरह से देखते हैं?**

-एक उम्र के बाद इंसान ठहराव की तरफ चला जाता है। किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, बस जो काम मिल रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं। जब उन्होंने फिल्म मोहब्बतें से चरित्र किरदारों को निभाने का सिलसिला शुरू किया तो उसके बाद ना जाने कितने किरदार निभा चुके हैं। साल 2014 में रणधीर कपूर जी ने मुझसे कहा था कि इंडस्ट्री में आलू प्याज बनकर रहना चाहिए। हर सब्जी को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब मैं अपने आप को वैसे ही देखता हूं।

क्या जीवन के किसी पड़ाव पर आपको भी परिवार के विरोध या नाराजगी का सामना करना पड़ा?

अभी भी अक्सर मुझे पिताजी से कई बातें कहने में संकोच होता है। ऐसे में कई बार अपनी बातें कहने में अपनी बहनों को ढाल की तरह प्रयोग करता हूं। (हंसते हुए) मेरी बहनों से पिता जी कहते हैं कि तुम लोग ही इसके वकील हो। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, फिर चाहे वो शादी से संबंधित रही हों या आर्थिक तंगी से जुड़ी। मेरे घर में पिता जी के सामने अभी भी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान के पन्नों में ही है। उसका मेरे जीवन में अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है।।

● **विन्नी और फैमिली फिल्म के साथ आगे बढ़ने का निर्णय क्यों सही लगा?**

-मैं फिल्म में अपनी ही उम्र और मानसिकता के व्यक्ति विनय की भूमिका निभा रहा हूं। मेरे बच्चे भी विनय की बेटी बिन्नी की उम्र के हैं। मेरी तरह विनय की पढ़ाई-लिखाई भी दिल्ली में हुई है। हम दोनो के माता-पिता बिहार में ही रहते हैं, फिर यह तो मेरी ही कहानी जैसी हुई। मुझे लगा कि मुझसे अच्छा इस भूमिका को कोई निभा नहीं पाएगा।

● **दो पीढ़ियों की मानसिकता के बीच के अंतर को किस तरह भरा जा सकता है?**

-बातचीत में अंतराल से ही पीढ़ियों के बीच अंतराल बढ़ता है। आजकल गैजेट्स हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा अपनी जगह बना चुके हैं कि एक ही कमरे में बैठे चार लोग, अलग-अलग मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती है। हम इंटरनेट मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और वास्तविकता से दूर होते जाते हैं। हर पीढ़ी की अपनी सोच है, लेकिन अगर आपको अपनी सोच के बारे में बताना या जताना है, तो बातचीत करनी पड़ेगी। जब बातचीत होती रहेगी तो जनरेशन गैप बनेगा ही नहीं।

● **एक पिता के तौर पर बच्चों के साथ आपका कैसा रिश्ता है?**

-अपनी पुरानी पीढ़ी से मैंने क्या करना चाहिए से ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए सीखा है। अगर माता-पिता बच्चों में अपने प्रति भय बनाकर रखेंगे तो आगे चलकर वह कहीं न कहीं झूठ जरूर बोलेंगे। बच्चों के साथ मित्रवत रिश्ता बनाकर रखें। आपसे सीखकर जब आपका बच्चा पिता बनेगा, तो वह भी अपने बच्चे का पिता नहीं, दोस्त ही बनेगा। मैं अपने बच्चों से इसी तरह का रिश्ता रखता हूं।

● **आगामी दिनों में और क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं?**

-मेरा अगला प्रोजेक्ट निखिल आडवाणी जी के साथ वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट है। देश की स्वतंत्रता के कालखंड पर बना यह शो इसी नाम की किताब पर आधारित है। इसके अलावा भी दो और फिल्में हैं, लेकिन अभी उनकी शूटिंग शुरू होने में समय है।

(दीपेश पांडेय)

इसलिए बेटी को मनोज ने भेजा हास्टल

अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं मनोज। इंस्टाग्राम (@bajpayee.manoj)

इंटरनेट मीडिया के इस दौर ने काफी बदलाव किया है। जहां कुछ चीजें सुलभ हुई हैं वहीं कुछ चीजों ने चिंता भी बढाई है। अब बच्चे ज्यादातर मोबाइल फोन की दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं। एक बेटी के पिता अभिनेता मनोज बाजपेयी से जब पूछा गया कि अपने बचपन से अपनी बेटी के बचपन की तुलना करते है, तो कौन सी बातें परेशान करती हैं? जवाब में उन्होंने कहा कि उसके लिए मुझे एक ही बात का बुरा लगता है कि उसके पास इस बड़े से शहर (मुंबई) में हमारे बचपन जैसी चीजें नहीं है। इसलिए हमने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है, ताकि वह दोस्त बनाए, उनके साथ समय गुजारे और फोन और डिजिटल की चीजों से दूर रहकर लोगों से बात करें। बोर्डिंग और हास्टल में यह करना मुमकिन हो पाता है। घर पर यह नहीं हो पाता है। माता-पिता का फोकस हमेशा अपने बच्चों पर रहता है। उससे अच्छा है कि वह अनुशासन में रहे। एक ही कैंपस में उसे अलग-अलग विधाएं सिखाई जाती हैं, दूसरे बच्चों के साथ उसे घुलने-मिलने का समय दिया जाता है। उसके लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। मनोज आगामी दिनों में कनु बहल निर्देशित फिल्म डिस्पैच में नजर आएंगे। फिलहाल वह वेब सीरीज फैमिली मैन 3 की शूटिंग कर रहे हैं।

फिल्मों के टकराव कभी अच्छे नहीं रहे हैं : अनीस

भूल भुलैया 3 फिल्म के निर्देशक हैं अनीस बज्मी ● मिडडे आकाइव

टिकट खिड़की पर दो बड़ी फिल्मों के टकराव की स्थिति में किसी न किसी एक फिल्म को नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। बीते दिनों स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्त्री 2, खेल खेल में और वेदा फिल्मों के टकराव के दौरान भी यह देखा गया। अच्छी प्रतिक्रियाओं के बाद भी खेल खेल में नहीं चल पाई। अब दीवाली पर कार्तिक आर्यन अभिनीत भूल भुलैया 3 और अजय देवगन अभिनीत सिंघम अगेन के बीच टकराव की स्थिति बनी है। इस टकराव पर भूल भुलैया 3 के निर्देशक अनीस बज्मी का बयान सामने आया है। इससे पहले सिंघम अगेन के अभिनेता अजय देवगन के साथ काम कर चुके अनीस ने क्या इस बारे में उनसे बात की? इस पर अनीस कहते हैं, 'मैं उनसे क्यों बात करूंगा? यह निर्माताओं के बीच होने वाला एक व्यावसायिक निर्णय है और मैं सिर्फ एक निर्देशक हूं। सिंघम अगेन की टीम दीवाली पर रिलीज करने के लिए अड़ी है। टकराव कभी अच्छे नहीं रहे हैं। हमने भूल भुलैया 3 की प्रदर्शित तिथि करीब साल भर पहले एडवांस में ही घोषित कर दी थी, अब हम और क्या कर सकते हैं? टकराव से जुड़े निर्णय और गणित निर्माताओं और वितरकों द्वारा देखे जाते हैं। मैं इन चीजों में शामिल नहीं होता हूं।' वहीं हाल ही में भूल भुलैया 3 के निर्माता भूषण कुमार ने कहा था कि भूल भुलैया 3 दीवाली के मौके पर ही प्रदर्शित होगी।

****